

# वैश्विक संवाद GLOBAL DIALOGUE

5.1

15 भाषाओं में एक वर्ष में 4 अंक

चार्ली हेब्दो

बोवेन्चुरा द सोसॉ सांतोस

सार्वजनिक समाजशास्त्र  
के दो रास्ते

नीरा युवाल-डेविस

विवेचनात्मक अनुबंध  
का जीवन

इस्सा शिवजी

पूँजीवाद बनाम्  
जलवायु न्याय

हर्बर्ट डोकेना

सार्वजनिक समाजशास्त्र  
का निर्वाह करना

अरियाने हनेमायर  
क्रिस्टोफर जे शनाइडर

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य :

- > अनौपचारिक बस्तियों में विरोध
- > फ्रांस में कार्य के बदलते प्रतिमान
- > इंडोनेशिया में समाजशास्त्र

सूचना पत्र



International  
Sociological  
Association



अंक 5 / क्रमांक 1 / मार्च 2015  
<http://isa-global-dialogue.net>

GD



## > सम्पादकीय

### एक सार्वजनिक समाजशास्त्री होना

वैश्विक संवाद का यह अंक चार्ली हेब्डो कार्टूनकारों की भयावह हत्या पर बोवेन्चुरा द सोसॉ संतोस के चिन्तन से प्रारम्भ होता है। यदि कभी घटनाओं की कोई ऐसी श्रृंखला थी जो समाजशास्त्रीय विश्लेषण के लिए पुकार रही थी तो वह यह थी—हत्या के कारणों, हत्यारों की प्रकृति, कार्टूनों का प्रभाव, राज्य की प्रतिक्रिया और जो समर्थन इसने प्राप्त किया को देखना। हम यह सीखते हैं कि “बोलने की स्वतन्त्रता” प्रदत्त कम और प्रतिवाद का स्थान अधिक है। और यही “मुस्लिम” और “आतंकवादी” के अर्थ पर लागू होता है—एक व्यक्ति का आतंकी अन्य के लिए स्वतन्त्रता सेनानी होता है और उससे भी अधिक, हमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा जैसा कि संतोस बड़ी प्रवीणता से करते हैं। हमें घटनाओं को विश्व में फैल रही हिंसा और उग्रवाद की व्यवस्थाओं के संदर्भ में देखना चाहिए। इनमें से बहुत कुछ राष्ट्र-राज्यों द्वारा शुरू की जाती हैं और इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।

हत्याएँ समाजशास्त्रीय विश्लेषण की मांग करती हैं, परन्तु समाजशास्त्री, इस जोखिम भरे स्थान में कदम रखने और सार्वजनिक समाजशास्त्री बनने के डर से चुप हैं। वास्तव में यह खतरनाक हो सकता है। इन मुद्दों पर मंथन करते हुए, नीरा युवल-डेविस सार्वजनिक समाजशास्त्र की ओर जाने वाले दो रास्तों की तरफ इंगित करती है : एक निर्वासन में समाजशास्त्री जो हाशिये पर रह कर पोजीशन लेता है और दूसरा, प्रख्यात इजराइली समाजशास्त्री बरूच किमरलिंग जैसे जो इजराइली केन्द्र में से मुद्दे उठाते हैं परन्तु और अधिक समीक्षात्मक हो जाते हैं। अफ्रीका में अत्यन्त भिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे, इस्सा शिवजी का वर्णन, एक कार्यकर्ता विद्वान जो तन्जानिया सरकार की आलोचना और विश्वविद्यालय स्वायत्तता की रक्षा के बारे में अटल है, को दर्शाता है।

सार्वजनिक समाजशास्त्र आवश्यक रूप से खतरनाक नहीं है परन्तु जटिल एवं अत्यावश्यक है। हर्बट डोकेना जलवायु परिवर्तन पर क्रमोत्तर होने वाली संयुक्त राष्ट्र की संगोष्ठियों पर नजर रख रहे हैं। निराशाजनक वार्ताओं को विफल होते देख, वे अधिक कठोर हस्तक्षेप की मांग करने वाले बढ़ते पूंजीवाद विरोधी आंदोलनों पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं। अंततः महत्वपूर्ण सार्वजनिक समाजशास्त्र स्थानीय स्तर पर भी किया जा सकता है। ऐसा एरियन हनेमायर और क्रिस्टोफर श्नाइडर अपनी कॉफी हाउस बैठकों, जो विश्वविद्यालय को जनता के पास और अपने खुली कक्षाओं, जो जनता को विश्वविद्यालय के पास लाती है, के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं।

वैश्विक संवाद के इस अंक में तीन संगोष्ठिया भी सम्मिलित हैं। हमारे पास चिले, उरूग्वे, कोलम्बिया, दक्षिण अफ्रीका और जाम्बिया में पनप रहे अनौपचारिक शहरी बस्तियों और भूमि बेदखली के बारे में निबन्धों का संग्रह है। निवासियों के विरुद्ध आत्मश्लाघी हिंसा के बावजूद प्रतिरोध जारी है – सजह विस्फोट के रूप में नहीं परन्तु हमेशा नहीं बल्कि कभी कभी सफल होने वाले राजनैतिक रूप से संगठित चाल के रूप में। हम धर्म, शिक्षा, श्रम और सामाजिक गतिशीलता की विरासत को आकार देने वाली नई लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पाँच निबन्धों के माध्यम से इंडोनेशिया के समाजशास्त्र का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अंत में, हमारे पास फ्रांस से तीन निबन्ध हैं। ये निबन्ध कार्य के नये प्रतिमान—फैशनबल निर्माण प्रयोगशालाएँ, पुराने रोगों का कार्यस्थल आवास, और एक “बहु-सक्रिय समाज” के आदिरूप जो श्रम मजदूरी, अवैतनिक सेवा कार्य और नागरिक गतिविधियों के मध्य के अंतर को खत्म कर देते हैं, पर केन्द्रित हैं।

- > वैश्विक संवाद को आईएसए वेबसाइट पर 15 भाषाओं में देखा जा सकता है।
- > प्रस्तुतियां (Submissions) [burawoy@berkeley.edu](mailto:burawoy@berkeley.edu) पर प्रेषित की जा सकती हैं।



विश्व विख्यात पुर्तगाली समाजशास्त्री एवं विधि विद्वान बोवेन्चुरा द सोसॉ संतोस चार्ली हेब्डो कार्टूनकारों की हत्याओं पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य लेते हैं।



नीरा युवाल डेविस, जेंडर एवं मानवाधिकारों की प्रख्यात समाजशास्त्री, प्रसिद्ध इजराइली समाजशास्त्री बरूच किमरलिंग के साथ लोक समाजशास्त्र के विभिन्न रास्तों पर आंतरिक संवाद करते हुए।



तंजानिया के स्थापित और जाने माने वामपंथी आलोचक, इस्सा शिवजी का अफ्रीका में विश्वविद्यालय की भूमिका पर उनके ही विद्यार्थी द्वारा लिया गया साक्षात्कार।



Global Dialogue is made possible by a generous grant from SAGE Publications.

# > Editorial Board

Editor: Michael Burawoy.

Associate Editor: Gay Seidman.

Managing Editors: Lola Busuttil, August Bagà.

Consulting Editors:

Margaret Abraham, Markus Schulz, Sari Hanafi, Vineeta Sinha, Benjamin Tejerina, Rosemary Barba-  
ret, Izabela Barlinska, Dilek Cindoğlu, Filomin Gut-  
ierrez, John Holmwood, Guillermina Jasso, Kalpana  
Kannabiran, Marina Kurkchian, Simon Mapadi-  
meng, Abdul-mumin Sa'ad, Ayse Saktanber, Celi  
Scalon, Sawako Shirahase, Grazyna Skapska,  
Evangelia

Tastsoglou, Chin-Chun Yi, Elena Zdravomyslova.

Regional Editors

Arab World:

Sari Hanafi, Mounir Saidani.

Brazil:

Gustavo Taniguti, Andreza Galli, Renata Barreto  
Preturlan, Ângelo Martins Júnior, Lucas Amaral,  
Rafael de Souza, Benno Alves.

Colombia:

María José Álvarez Rivadulla, Sebastián Villamizar  
Santamaría, Andrés Castro Araújo, Katherine Gaitán  
Santamaría.

India:

Ishwar Modi, Rashmi Jain, Pragya Sharma,  
Jyoti Sidana, Nidhi Bansal, Pankaj Bhatnagar.

Iran:

Reyhaneh Javadi, Abdolkarim Bastani, Niayesh Dolati,  
Mitra Daneshvar, Faezeh Khajehzadeh.

Japan:

Satomi Yamamoto, Hikari Kubota, Takazumi Okada,  
Fuma Sekiguchi, Kazuki Uyeyama.

Kazakhstan:

Aigul Zabirowa, Bayan Smagambet, Gulim Dossanova,  
Julduz Battalova, Almagul Nurusheva, Daurenbek  
Kuleimenov, Elmira Otrá.

Poland:

Jakub Barszczewski, Martyna Dolores, Mariusz  
Finkielsztejn, Weronika Gawarska, Krzysztof  
Gubański, Kinga Jakiela, Justyna Kościńska,  
Przemysław  
Marcowski, Mikołaj Mierzejewski, Karolina  
Mikołajewska, Adam Müller, Zofia Penza, Anna  
Wandzel, Justyna Zielińska.

Romania:

Cosima Rughiniş, Ileana-Cinziana Surdu, Corina  
Brăgaru, Telegdy Balazs, Adriana Bondor, Ramona  
Cantaragiu, Ruxandra Iordache, Mihai Bogdan Marian,  
Angelica Marinescu, Monica Nădrag, Mădălin-Bogdan  
Rapan,  
Alina Stan, Elisabeta Toma, Elena Tudor, Cristian  
Constantin Veres.

Russia:

Elena Zdravomyslova, Anna Kadnikova, Asja Voronk-  
ova.

Taiwan:

Jing-Mao Ho.

Turkey:

Gül Corbacioglu, Irmak Evren.

Media Consultants: Gustavo Taniguti, José Reguera.

Editorial Consultant: Ana Villarreal.

# > इस अंक में In This Issue

सम्पादकीय : सार्वजनिक समाजशास्त्री होने के क्रम में	2
चार्ली हेब्बो : कुछ दुष्कर उलझनें बोवेन्चुरा द सोसॉ सांतोस, पुर्तगाल	4
सार्वजनिक समाजशास्त्र के दो रास्ते नीरा युवाल-डेविस, यू.के.	7
विवेचनात्मक अनुबंध का जीवन : इस्सा शिवजी के साथ एक साक्षात्कार सबाथो न्यामसेण्डा, तंजानिया	10
पूँजीवाद बनाम जलवायु न्याय हर्बर्ट डोकेना, फिलिपींस और यू.एस.ए.	13
सार्वजनिक समाजशास्त्र का निर्वाह करना अरियाने हनेमायर एवं क्रिस्टोफर जे र्नाइडर, कनाडा	16
<b>&gt; अनौपचारिक बस्तियों में विरोध</b>	
नगर के अधिकार का पुनर्दावा : चिली में लोकप्रिय सक्रियकरण सिमोन एसकोफेयर, यू.के.	18
उरुग्वे में अवैध बस्तियाँ एवं राजनीति मारिया जोस अलवरेज रिवाडुला, कोलम्बिया	20
ब्राजील के बेघर श्रमिकों के आंदोलन का विकास सिबेल रिजेक एवं आन्द्रे डल'बो, ब्राजील	22
दक्षिण अफ्रीका में गरीब लोगों का विरोध प्रदर्शन प्रिशानी नायडू, दक्षिण अफ्रीका	24
जाम्बिया : सामाजिक आंदोलनों के बिना बेदखली सिंगुम्बे मुयेबा, दक्षिण अफ्रीका	26
<b>&gt; फ्रांस में कार्य के बदलते प्रतिमान</b>	
फैबलैब्स और हैकरस्पेसेज : उभरती हुई एक नई संस्कृति इजाबेल बेरेवी-हॉफमन, मैरी क्रिस्टीन ब्यूरो एवं मिशेल लालेमण्ट, फ्रांस	28
'बहु-सक्रिय समाज' में लैंगिक समानता को पाना बर्नार्ड फुसुलियर, बेल्जियम एवं चंताल निकोल-द्रानकोर्ट, फ्रांस	30
कार्य में पुरानी बीमारी पर बातचीत ऐनी-मैरी बसर, डोमिनिक ल्हूर्डिलियर, फ्रेडरिख बुगुयल्स, पियरे लेनल, ज्यूलाम ह्यूज, जोयल मेज्जा एवं कैथी हेमण्ड, फ्रांस	32
<b>&gt; इंडोनेशिया में समाजशास्त्र</b>	
इंडोनेशिया में लोकतंत्र का उत्सव लुसिया रातिह कुसुमादेवी, इंडोनेशिया	34
इंडोनेशिया की उच्च शिक्षा का निगमीकरण कामान्टो सुनार्तो, इंडोनेशिया	36
इंडोनेशिया में श्रमिक आंदोलन और कामगार वर्ग राजनीति हरि न्यूग्रोहो, इंडोनेशिया	38
जब धर्म कानूनी पहचान बन जाये एंटोनियस काह्यादी, इंडोनेशिया	40
इंडोनेशिया में उध्वगामी गतिशीलता को प्रोत्साहन इन्देरा रत्ना इरावती पट्टीनासरानी, इंडोनेशिया	42



# > चार्ली हेब्दो : कुछ दुष्कर उलझनें

बोवेन्चुरा द सोसॉ सांतोस, कोइम्बरा विश्वविद्यालय, पुर्तगाल एवं आई.एस.ए. विश्व कांग्रेस  
2014 की कार्यक्रम समिति के सदस्य



चार्ली हेब्दो हत्याओं के पीड़ितों के सम्मान में  
पेरिस में आयोजित एक रैली में विश्व नेता एक  
साथ मार्च करते हुए।

चार्ली हेब्दो के कार्टूनकारों एवं पत्रकारों के विरुद्ध हिंसा की जघन्य प्रकृति ने इस बर्बर कार्यवाही, उसके संदर्भ और उदाहरणों के साथ इसके प्रभाव और भविष्य में होने वाले परिणामों का ठंडे दिमाग से विश्लेषण करने की पेशकश करना अत्यन्त मुश्किल है। फिर भी विश्लेषण अत्यावश्यक है अन्यथा हम एक ऐसी आग की लपटों को हवा देंगे जो हमारे बच्चों के विद्यालयों, हमारे घरों, हमारी संस्थाओं और एक दिन हमारे विवेक को जला सकती हैं। इस विश्लेषण की ओर यहां कुछ विचार प्रस्तुत हैं।

## > हिंसा एवं लोकतंत्र

चार्ली हेब्दो दुखद घटना और अमरीका एवं उसके सहयोगियों द्वारा 11 सितम्बर 2001 के बाद आतंकवाद के खिलाफ छेड़ी गई लड़ाई के मध्य कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध रेखांकित नहीं किया जा सकता है। यद्यपि यह ज्ञात तथ्य है कि पश्चिम की चरम आक्रामकता कई हजारों मासूम नागरिकों (अधिकांश मुस्लिम) की मौत का कारण बनी है। अमरीकी कांग्रेस को हाल ही में सौंपी गई रिपोर्ट द्वारा प्रमाणित हुआ है कि इस आक्रामकता ने युवा मुस्लिमों,

>>

जिन पर दुराचार के सभी प्रकार के संशय शायद काल्पनिक ही हैं, को आश्चर्यजनक स्तर की हिंसा और अत्याचार से पीड़ित किया है। यह भी विख्यात है कि कई युवा इस्लामी कट्टरपंथी दावा करते हैं कि उनकी कट्टरता उक्त सभी प्रकार की हिंसा का निवारण नहीं करने के प्रति गुस्से से उपजी है। इस के मद्देनजर, हमें रुक कर यह विचार करना होगा कि हिंसा के इस सर्प को थामने के लिए क्या अब तक इसे चलाने वाली उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाना सबसे अच्छा तरीका है, जैसा कि अब काफी स्पष्ट हो गया है। हमले के प्रति फ्रांस की प्रतिक्रिया घेरेबंदी की अधोषित स्थिति के साथ लोकतांत्रिक संवैधानिक सामान्य स्थिति को निलंबित करना था। उसने यह माना कि इस प्रकार के अपराधियों को जेल में रखने और न्याय के समक्ष लाने के बजाय गोली मार देनी चाहिए और यह कि इस प्रकार का व्यवहार किसी भी तरीके से पश्चिमी मूल्यों का खण्डन नहीं करता है। हम कम तीव्रता वाले गृह युद्ध के चरण में प्रवेश कर गये हैं। इससे यूरोप में किसको लाभ हो सकता है? निश्चित तौर पर न तो स्पेन में पोडेमोस दल और न ही ग्रीस का स्यरिजा को।

## > अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता

अपने आप अभिव्यक्ति करने की स्वतन्त्रता एक बहुमूल्य वस्तु है लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं और सच्चाई यह है कि इन सीमाओं में से अधिकांश उन लोगों द्वारा थोपी जाती हैं, जो जब कभी भी उनकी स्वतन्त्रता में कटौती की जाती है, असीम स्वतन्त्रता की वकलात करते हैं। ऐसी सीमाओं के असंख्य उदाहरण हैं : इंग्लैंड में कोई भी प्रदर्शक, यह कहने पर कि डेविड कैमरून के हाथ खून से रंगे हैं, गिरफ्तार हो सकता है; फ्रांस में इस्लामी महिलाओं को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है; 2008 में कार्टूनकार सिने (मॉरिस सिनेट) को कथित तौर पर यहूदी-विरोधी लेख लिखने पर चार्ली हेब्डो से निकाल दिया गया था। इन सब का अर्थ है सीमाएं अवश्य होती हैं, बस ये भिन्न हित समूहों के लिए अलग होती हैं। लेटिन अमरीका का उदाहरण लीजिए, जहां अधिकांश मीडिया कुलीन परिवारों और बड़ी पूंजी से नियन्त्रित हैं, सबसे पहले अबाधित अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की मांग करते हैं ताकि वे प्रगतिशील सरकारों पर दुरुपयोग का लांछन लगा कर इन सरकारों द्वारा गरीबों की भलाई को प्रोत्साहित करने वाले अच्छे कार्यों को दबा सकें। ऐसा प्रतीत होता

है कि मुसलमानों के कार्टून बनाते समय चार्ली हेब्डो में कोई सीमा नहीं थी। यद्यपि इनके कई कार्टूनों को फ्रांस और यूरोप में सामान्य तौर पर फैंली इस्लाम के प्रति भय और अप्रवासी विरोधी लहर को प्रेषित करने वाले नस्लीय प्रचार के रूप में देखा गया। इसके अतिरिक्त, पैगम्बर को अश्लील रूपों में दिखाये जाने वाले कार्टूनों में से एक को चरम दक्षिण पंथी द्वारा काफी उठाया गया। इसने बोको हरम सेक्स गुलाम के रूप में गर्भवती मुस्लिम महिलाओं के एक समूह को अपने सूजे हुए पेट पर हाथ रख, "हमारे कल्याण लाभों से हाथ दूर रखों" चिल्लाते हुए दर्शाया। एक ही झटके में, कार्टून ने इस्लाम, महिलाओं और कल्याणकारी राज्य को कलंकित कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, पिछले कुछ वर्षों में यूरोप में सबसे बड़े मुस्लिम समुदाय ने इस संपादकीय वाक्य को अपमानजनक रूप में देखा। दूसरी तरफ इनके द्वारा पेरिस में बर्बर अपराध की निंदा तत्काल थी। अतः हमें जीवन मूल्यों, जिन्हें हममें से कुछ सार्वभौमिक मानते हैं, के विरोधाभासों और विषमताओं पर चिन्तन करना चाहिए।

## > सहिष्णुता और "पाश्चात्य मूल्य"

अभिमतों की दो प्रवृत्तियाँ अपराध के संदर्भ पर हावी हैं, जिनमें से कोई भी एक समावेशी अन्त-सांस्कृतिक यूरोप के निर्माण के लिए हितकारी नहीं हैं। इन दोनों में से अधिक उग्र खुले रूप में इस्लाम से भय रखने वाली और अप्रवास विरोधी है। ये पूरे यूरोप में फैले चरम दक्षिण पंथी और किसी जगह आगामी चुनावों में संकट का अनुभव करने वाले दक्षिण पंथी हैं (जैसा कि ग्रीस के एन्टोनिनिस समारस के मामले में हुआ)। इस वर्तमान विचार में, यूरोपीय सभ्यता के दुश्मन "हम" में से हैं—वे हमसे घृणा करते हैं, वे हमारे पासपोर्ट रखते हैं और इस स्थिति का तब तक समाधान नहीं हो सकता जब तक ये खत्म न हो जाए। अप्रवासी विरोधी मकसद स्पष्ट दिखाई देते हैं। दूसरी प्रवृत्ति सहिष्णुता की है। ये लोग हमसे काफी भिन्न हैं, वे बोझ हैं परन्तु "हमें उनके साथ रहना होगा" क्योंकि चाहे और कुछ न हो, ये काम के हैं, यद्यपि यदि ये संयम से व्यवहार करें और हमारे मूल्यों को आत्मसात करें तो हमें ऐसा करना चाहिए।

परन्तु "पाश्चात्य मूल्य" क्या हैं? यूरोप के भीतर और बाहर सदियों से इन मूल्यों के नाम पर की गई नृशंसता-औपनिवेशिक

हिंसा से लेकर दो विश्व युद्ध के बाद ये मूल्य क्या हैं और प्रसंग के अनुरूप क्यों कुछ मूल्य अभी और कुछ बाद में प्रधानता ले लेते हैं, के बारे में सतर्कता और चिन्तन उचित है। उदाहरण के लिए, कोई भी स्वतन्त्रता के मूल्य पर सवाल नहीं उठाता है, परन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकतांत्रिक यूरोप में प्रबल कल्याण राज्य की अवधारणा में अन्तर्निहित दो मूल्य समानता और भाईचारे के लिए यह नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि, हाल ही के वर्षों में, सामाजिक एकीकरण के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने वाली सामाजिक सुरक्षा पर रूढ़िवादी राजनेता सवाल करने लगे हैं और यह अब शासन दलों, चाहे वाम-केन्द्र हों या दक्षिण केन्द्र, के लिए अवहनीय विलासिता के रूप में देखी जाती है। क्या यह सही नहीं है कि सामाजिक सुरक्षा के क्षरण और विशेष तौर पर युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के कारण उपजा सामाजिक संकट, युवा पीढ़ी के अन्दर कट्टर पंथ की लपटों को बढ़ाने में सहायक है? ऐसा विशेष तौर पर उन पर होता है जो बेरोजगार होने के साथ नस्लीय और धार्मिक भेदभाव का शिकार भी हैं।

## > कट्टरवाद का टकराव न कि सभ्यताओं का

आज हम जिसका सामना कर रहे हैं, वह सभ्यताओं का टकराव नहीं है क्योंकि ईसाई और इस्लामी सभ्यताएं एक ही जड़ का हिस्सा हैं। हमारे समक्ष जो है वह कट्टरवादिता का टकराव है, चाहे उनमें से कुछ हमारे इतने नजदीक हैं कि हम उन्हें इस रूप में पहचान नहीं सकते हैं। इतिहास गवाह है कि कट्टरवादिता और इसमें टकराव के तरीकें हमेशा कुलीन वर्ग के आर्थिक और राजनैतिक हितों से सम्बन्धित होते हैं। वे कभी भी आम जनता, जिसने पैदल सैनिक बन इन टकरावों के आघात को झेला है, के लिए लाभकारी नहीं रहे हैं। यूरोप और इसके प्रभाव के क्षेत्रों में धर्मयुद्ध और धर्म न्यायाधिकरण, औपनिवेशिक आबादी का ईसाई धर्मान्तरण, उत्तरी आयरलैंड में धार्मिक युद्ध और संघर्ष के मामलों में ऐसा ही हुआ है। यूरोप के बाहर, बौद्ध धर्म जैसे शांतिप्रिय धर्म ने श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों के हजारों सदस्यों के वध को वैध ठहराया; 2003 में हिन्दू कट्टरपंथियों ने भी गुजरात की मुस्लिम आबादी का संहार किया, और प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही की जीत के फलस्वरूप उनकी शक्ति बढ़ने की संभावना से डर

>>

लगता है; इजराइल भी धर्म के नाम पर फिलीस्तीन की अदण्डनीय नस्लीय सफाई कर रहा है और तथाकथित इस्लामी अमीरात सीरीया और इराक में मुस्लिम आबादी की हत्या कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि अन्तर सांस्कृतिक यूरोप में, जहां कई लोगों की इस विशिष्ट मूल्य से पहचान नहीं है, अनियंत्रित धर्मनिरपेक्षता की वकालत स्वयं अतिवाद का एक स्वरूप है? क्या अतिवाद एक दूसरे के विरोधी हैं? क्या वे आपस में सम्बन्धित हैं? जिहादियों और पश्चिमी खुफिया सेवाओं के मध्य क्या सम्बन्ध है? ऐसा कैसे है कि इस्लामी अमीरात के जिहादी जो आज आतंकवादी माने जाते हैं, गद्दाफी और असाद के विरुद्ध लड़ते समय स्वतन्त्रता सेनानी थे? ऐसा कैसे है कि पश्चिम के सहयोगी सउदी अरब, कतार, कुवैत और तुर्की सभी, इस्लामी अमीरात की आर्थिक मदद कर रहे हैं? यह कहने के पश्चात, तथ्य यह है कि कम से कम पिछले दस वर्षों में सभी प्रकार के कट्टरता

(इस्लामी कट्टरता सहित) के बड़ी संख्या में शिकार लोग गैर कट्टर मुस्लिम आबादी के थे।

## > मानवीय जीवन का मूल्य

इन हत्याओं के समक्ष यूरोपीय लोगों द्वारा अनुभव की गई असीम, अप्रतिबंधित घृणा को देख हमें अचंभा होता है कि वे, उच्च नहीं तो उसी के समान संघर्ष जो अंत में चार्ली हेब्रो दुखद घटना से कहीं सम्बन्धित हो सकते हैं, का सामना करते समय उसी प्रकार की घृणा का अनुभव क्यों नहीं करते हैं? उसी दिन, यमन में 37 युवा लोग एक बम हमलने में मारे गये। पिछली गर्मीयों में, फिलीस्तीन पर इजराइल का आक्रमण 2000 फिलीस्तीन, जिसमें 1500 नागरिक और 500 बच्चे थे, की मौत का कारण बना। मेक्सिको में सन् 2000 से अब तक प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए बोलने पर 102 पत्रकारों की हत्या कर दी गई और नवम्बर 2014 में, मेक्सिको के अयोतजिनापा

में 43 युवा प्रदर्शनकारियों को मार दिया गया। यकीनन् प्रतिक्रियाओं का यह अन्तर इस धारणा पर आधारित नहीं हो सकता कि ईसाई संस्कृति से आने वाले श्वेत यूरोपीय लोगों का जीवन, अन्य धर्मों या अन्य क्षेत्रों में उत्पन्न संस्कृति के गैर यूरोपीय लोग या अन्य वर्ण के यूरोपीय से अधिक मूल्यवान है। क्या यह इसलिए है कि परवर्ती यूरोपीय लोगों से दूर स्थित हैं और उनसे कम परिचित हैं? दूसरी तरफ, अपने पड़ोसी से प्रेम करने का ईसाई उपदेश क्या इस तरह के अन्तर को स्वीकार करता है? क्या यह इसलिए है कि पश्चिम में बड़ा मीडिया और राजनेता उन अन्य द्वारा भोगी गई यातना को तुच्छ बताने का प्रयास करते हैं या फिर उन्हें इतना प्रताड़ित करते हैं कि वे सोचने लगते हैं कि उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए? ■

बोवेन्चुरा द सोसों सांतोस से पत्र व्यवहार हेतु पता <[bsantos@ces.uc.pt](mailto:bsantos@ces.uc.pt)>

# > सार्वजनिक समाजशास्त्र के दो रास्ते

नीरा युवाल-डेविस, ईस्ट लंदन विश्वविद्यालय, यू.के., अध्यक्ष, नस्लवाद, राष्ट्रवाद और नृजातीय सम्बन्ध की शोध समिति (RC 05) 2002-06 और सदस्य, आई एस ए कांग्रेस कार्यक्रम समिति, डरबन 2006



एक इजराइली असंतुष्ट, नीरा युवाल डेविस, लंबे समय से मानवाधिकार की रक्षक रही हैं। वे वुमन अगेंस्ट फण्डामेन्टलिस्म और सैन्य संघर्ष क्षेत्रों में महिलाओं के अन्तर्राष्ट्रीय शोध नेटवर्क की संस्थापक सदस्य, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न प्रभागों के साथ साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित अनेक NGOs में सलाहकार भी थीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिंग, नस्लवाद और धार्मिक कट्टरवाद पर अपने शोध के लिए विख्यात, उनकी पुस्तकों में Racialized boundaries, Gender and Nation, The Politics of Belonging, Women against Fundamentalism सम्मिलित हैं। वे ईस्ट लंदन विश्वविद्यालय में Migration, Refugees and Belonging के शोध केन्द्र की निदेशक हैं। इस निबन्ध में वे प्रसिद्ध, अब दिवंगत समाजशास्त्री बारुक किमरलिंग के साथ सार्वजनिक समाजशास्त्र के विभिन्न रास्तों पर एक आंतरिक बौद्धिक संवाद का आयोजन करती हैं।

पूरे जीवन सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित और 1948 के बाद रोमानिया से एक शरणार्थी के रूप में इजराइल पहुंचे बारुक किमरलिंग इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विख्यात समाजशास्त्रियों में से एक थे। ऐसा कम से कम उनके इजराइल प्रेस में अपने लगातार योगदान के वजह से तो नहीं था।

बारुक और मैं, हिब्रू विश्वविद्यालय, जहां हमने स्नातक की शिक्षा ली, के समय से दोस्त हैं। बारुक अपने पूरे जीवन भर हिब्रू विश्वविद्यालय में ही रहे, मैं 1969 में MA पूरा करने के पश्चात् पहले यू. एस. ए. और फिर यू. के. चली गई। शोध छात्र के रूप में हम दोनों ने Shmuel Eisenstadt (जो तकरीबन 40 वर्ष से इजराइली समाजशास्त्र पर हावी थे) के खिलाफ विद्रोह किया परन्तु अपने सामाजिक दृष्टिकोणों और कई वर्षों तक राजनैतिक स्तर पर भी हमारे बीच मतभेद थे। बीस साल की उम्र में, मैं इजराइल राज्य और समाज के गैर और फिर यहूदी विरोधी विश्लेषण के प्रति मुखर थी; कई वर्षों बाद और इजराइल-फिलीस्तीनी संघर्षों और समाजों के व्यवस्थित अध्ययन करने के पश्चात् बारुक भी समान निष्कर्ष पर पहुंचे—यद्यपि उन्होंने खुद को यहूदी के रूप में लेबल करना जारी रखा। उन्होंने समाजशास्त्र के इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण पक्षों का विकास किया जबकि मैं, अपनेपन की प्रतिच्छेदन राजनीति के रूप में जिसे व्यक्त किया जा सकता है, मैं चली गई।

2007 में बारुक की मृत्यु उपरान्त, इजराइल, फिलीस्तीन और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक वैज्ञानिकों में से एक के रूप में आमंत्रित मैंने उनके स्मृति सम्मेलन में इजराइलियों की अस्तित्व संबंधी चिन्ताओं, विशेष रूप से बारुक जिन्हें "Akhusalim", Ashkenazi, धर्मनिरपेक्ष और यहूदी श्रम बुलाते थे और जो बीसवीं सदी के अधिकांश समय यहूदी आंदोलन में प्रमुख थे, पर व्याख्यान दिया। मैंने इस अस्तित्व संबंधी चिन्ताओं को कई सथानिक कारकों, जिनमें से कुछ आबादकार औपनिवेशिक कॉलोनियों में सभी प्रमुख अल्पसंख्यकों में समान; अन्य "नव उदारवादी जोखिम समाजों" में समान; और अन्य इजराइल के लिए विशिष्ट, जो उसके स्थाई युद्ध समाज के चरित्र के साथ साथ बढ़ती मुक्तिवादी यहूदी कट्टरवाद जो इजराइल के धर्म निरपेक्ष शासन को कमतर आंकता है, से सम्बन्धित थी।

मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने जो कहा, उसे सकारात्मक रूप में ग्रहण किया गया। यह पूर्व में मेरे विश्लेषणों के प्रति हुई प्रतिक्रियाओं से बिल्कुल भिन्न था। (हालांकि सम्मेलन में वक्ताओं द्वारा दिये गये अतिवादी संदेशों को कोई चुनौती नहीं दी गई, पांच वर्षों के पश्चात् भी हमारे लेखों का ग्रंथ का अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ है। ऐसा शायद सम्मेलन की मेजबानी करने वाली वेन लियर संस्था के विरोध के कारण हुआ है।)

>>

मैं विशेष रूप से बारुक की आत्मकथा' की सिफारिश करना चाहूंगी जो कि उनके चारित्रिक हाजिरजवाबी और बौद्धिक ईमानदारी के साथ लिखी गई है और जो पाठकों की इजराइली/फिलिस्तीनी संघर्ष की समझ में वृद्धि करेगी। हालांकि यह सार्वजनिक समाजशास्त्र के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। यहां मैं अपने आप को दो मुख्य प्रश्नों तक सीमित रखती हूँ।

## > सार्वजनिक और पेशेवर समाजशास्त्र

बारुक तर्क देते हैं कि उन्होंने अपने सार्वजनिक पत्रकारी और पेशेवर शैक्षणिक कार्य को पूर्ण रूप से अलग रखा है। यह विभेदन, डोना हरावे जिसे "कहीं से सब कुछ देखने की भगवान की चाल" कहती है, में इनके Weberian विश्वास से निकलता है। इसके विपरीत, मैंने अधिकांश नारीवादी चिन्तकों और ज्ञान के समाजशास्त्र के अन्य उग्र परम्पराओं, मार्क्सवादी और नस्ल विरोधी, का अनुसरण करते हुए स्थित ज्ञान और स्थित कल्पना के लिए तर्क दिया। एक सापेक्षवादी पोजिशन—जो यह जोर देती है कि कई सत्य हैं जिन्हें उनकी खुद की योग्यता पर आंके जाने की जरूरत है और अतः इनकी तुलना नहीं की जा सकती है, की अपेक्षा मैं तर्क देती हूँ कि स्वयं के सिद्धान्त/दृष्टिकोण (जिसमें सामाजिक स्थान, पहचान, मानक मूल्य प्रणाली जो एक दूसरे से अलगधुकरणीय परन्तु स्वयं के जीवन अनुभवों और व्यवहारों द्वारा मध्यस्थ, विशिष्ट संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक बाधाओं में भीतर अस्थिर और विवादित सम्मिलित हैं) दुनिया को देखने के नजरिये को प्रभावित करते हैं। "सच" के बारे ज्ञान को संवादात्मक रचनात्मक प्रक्रिया द्वारा ही अनुमानित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कई स्थित दृष्टि विशिष्ट स्थानिक और लौकिक संदर्भों के भीतर भाग लेती है।

राजनैतिक और पेशेवर के मध्य बारुक के द्विभाजन से मेरी समस्या केवल ज्ञान मीमांसीय नहीं है। समाजशास्त्री और राजनैतिक रूप से सक्रिय होने के वर्षों के दौरान मैंने पाया कि कार्य करने के दोनों तरीके एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि को पोषित और प्रदान करते हैं व एक तरफ जमीनी राजनैतिक सक्रियता अन्य स्थित अवलोकन की समानुभूतिपूर्वक समझ हासिल करने में मदद करते हैं और दूसरी तरफ पहचान की राजनीति के कुछ अपक्व द्विभाजनों को परिष्कृत और चुनौती देने में सैद्धान्तिक और अनुभवजन्य विद्वता द्वारा मदद लेते हैं। इसके अतिरिक्त अक्सर जब हम इस पर विचार करते हैं कि क्यों कोई विशिष्ट शोधार्थी विशिष्ट शोध प्रोजेक्ट पर कार्य करता है और वह कैसे अपने शोध निष्कर्षों को प्रसारित करता है, इन क्षेत्रों के मध्य की रेखा कृत्रिम प्रतीत होती है।

1969 में उनके विश्वविद्यालय कैम्पस में कैफेटेरिया पर बमबारी के पश्चात जिस क्षण उन्होंने इजराइल-फिलिस्तीनी संघर्ष का अध्ययन करने का फैसला किया, से प्रारम्भ हो बारुक के सार्वजनिक हस्तक्षेपों ने अतिव्यापी व्यवस्तताओं और आपसी अंतर्दृष्टि के समान पैटर्न प्रदर्शित किये हैं। बारुक के इस दावे पर कि उन्होंने अपने "वैज्ञानिक" कार्य पर अपने राजनैतिक काम के मुकाबले अंतर्ज्ञान पर कम भरोसा किया है, मुझे काफी शक है। कुहन के पैराडाईम परिवर्तन के सिद्धान्त के सम्बन्ध में खुद बारुक लिखते हैं, सभी प्रकार के आंकड़ा संग्रहण में चयनात्मकता के तत्व शामिल होते हैं। फिर भी, मुझे उनकी इस कुंठा से कि लोगों ने उनके लघु सार्वजनिक लेखों को पढ़ने के बाद ही उनके समाजशास्त्रीय कार्य को आंका है, समानुभूति है।

बारुक के ज्ञान के बदलते स्वरूप और इजराइली और फिलिस्तीनी समाजों की उनकी समझ, यद्यपि एक दूसरे मुद्दे को



**बारुक किमरलिंग** का जन्म 1939 में हुआ। उनकी मां हंगरी की और पिता रोमानिया से थे। हॉलोकास्ट से बचने के बाद बारुक का परिवार इजराइल प्रवास कर गया, जहां वे बड़े हुए। उन्होंने जेरुशलम के हेब्रू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र

का अध्ययन किया और यहीं इन्होंने शोध किया एवं अपने वयस्क जीवन का अधिकांश समय अध्यापन किया। 1969 में इसके कैफेटेरिया पर बमबारी के बाद, उन्होंने अपनी जड़ों, इतिहास और इजराइली-फिलिस्तीनी संघर्ष की वास्तविकताओं के अध्ययन की तरफ ध्यान केन्द्रित किया। उनके द्वारा विकसित उपागम आधिकारिक इजराइली वृत्तान्त से का प्रतिकूल था। इजराइली नीतियों के मुखर आलोचक होने के कारण उन्हें व्यापक और कठोर प्रत्यारोप का सामना करना पड़ता था। अपने लेखों और शिक्षण से उन्होंने सच्चे लोकतांत्रिक राज्य जो अपने सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के स्वीकारता है, सैन्य आक्रामकता का परित्याग करता है और समझौते व मानवीय दृष्टिकोण के माध्यम से शांति के लिये प्रयास करता है, के पक्ष में जनमत को प्रभावित करने की कोशिश की। अपने मूल्यों और विचारों के प्रति वफादार एवं इजराइल के भविष्य के लिये चिंतित बारुक किमरलिंग की मृत्यु 2007 में हो गई। उनकी पुस्तकें हैं : Zionism and Territory: The Socioterritorial Dimensions of Zionist Politics (1983), The Invention and Decline of Israeliness: State, Culture and Military in Israel (2001); Politicide: Sharon's War Against the Palestinians (2003).

उठाती है जो बारुक के इस दावे से कि "केन्द्र में एक सीमान्त" की उनकी स्थिति उनके सार्वजनिक समाजशास्त्र की एक पूर्व-शर्त के साथ साथ एक साधन भी थी, से सम्बन्धित है।

## > सार्वजनिक समाजशास्त्र में सामाजिक स्थान की भूमिका

अपने सम्यक, चिन्तनशील, ईमानदार तरीके में, बारुक इजराइल के सबसे पुराने समाचार पत्र हारेज में छपे पहले लेख को साबरी जिरिस की पुस्तक The Arabs in Israel पर विस्तृत और चरम हमले के रूप में वर्णन करते हैं। काफी समय बाद, बारुक को न केवल यह अहसास हुआ कि साबरी सही थे अपितु यह कि अभिलेखीय सामग्री तक पहुंच नहीं होने के कारण, साबरी ने इजराइली फिलिस्तीनियों को नियंत्रित करने और उनकी जमीनें अधिगृहित करने के कपटी तरीकों की सीमा को कम आंका। Ian Lustick की पुस्तक Arabs in the Jewish State, जिसकी उन्होंने बाद में उच्च प्रशंसा की, के बारे में भी बारुक इसी तरह के परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। (यद्यपि वे इसका अपनी आत्मकथा में उल्लेख नहीं करते हैं, 1975 में जब मेरी सह-सम्पादित पुस्तक Israel and the Palestinians प्रकाशित हुई, उन्होंने एक चिंतित मित्र की तरह इसे अपने C.V. में सम्मिलित करने से बचने की सिफारिश की। मेरे सहित, कई लेख, बारुक के बाद के लेखों के अत्यन्त निकट हैं।)

>>



इन वर्षों के दौरान, बारुक इजराइली और फिलीस्तीनी समाजों और संघर्षों के बारे में अपनी समझ का पुनर्मूल्यांकन कर पाये; वे अद्भुत सार्वजनिक समाजशास्त्री, जिसके लेखों ने महत्वपूर्ण रूपों में व्यापक इजराइली राय को प्रभावित किया, बन गये। विभिन्न मुद्दों की मेरी समझ भी काफी समृद्ध हो गई है और इन वर्षों के दौरान बदली है; मैं आशा करती हूँ कि बारुक की तरह मेरे मरने के दिन तक ऐसा ही रहेगा। हालांकि, मैं बारुक के दो दावों के साथ मुद्दे उठाना चाहूंगी।

पहला, बारुक सुझाव देते हैं कि उन्होंने अपना नये दृष्टिकोण और समझ को अपने दम पर विकसित किया। उनके उपर, उनके द्वारा अन्य की पढ़ी गई पुस्तकों और जिन कुछ के साथ इन वर्षों के दौरान उन्होंने कई घंटे बहस में व्यतीत किये, का बहुत कम प्रभाव था। स्व और ज्ञान का गैर संवादात्मक निर्माण ज्ञान और अभिवृत्ति अधिग्रहण की प्रक्रिया को गलत ढंग से पेश करता है। यह एक विडम्बना है कि यह सार्वजनिक समाजशास्त्र के उद्देश्य का, जो वैकल्पिक विश्लेषण और तथ्यों के प्रस्तुतीकरण का लक्ष्य प्रस्तुत करता है, अवमूल्यन करता है।

दूसरा, बारुक तर्क देते हैं कि वे सार्वजनिक समाजशास्त्री इसलिए बन पाये क्योंकि हाशिये पर हम सब के विपरीत, “हम में से एक” के रूप में उन पर भरोसा था। दूसरे शब्दों में, वे अभिजनों की आँखों में ‘वैध’ थे। बारुक कहते हैं कि इसने उनके मुख्य घारा के इजराइली प्रेस (जो कि अविवादित है) में प्रकाशित होना आसान बनाया, जबकि समान विश्लेषण वाले अन्य (उदाहरण के लिए उग्र समाजवादी और यहूदी विरोधी संगठन मत्जपेन के सदस्य) सार्वजनिक क्षेत्र में कम दिखाई दे रहे थे क्योंकि उनके विचारों को अवैध माना जाता था। यह वैधता, उनके अनुसार, सार्वजनिक समाजशास्त्री के रूप में प्रभावी कार्य करने की पूर्व शर्त है।

बारुक सुझाव देते हैं कि “उनमें से एक” की उनकी आकस्मिक स्वीकृति, आंशिक रूप से उनके द्वारा जिरिस और लास्टिक की

जैसी पुस्तकों पर हमलों—उन विश्लेषणों का निराकरण जिसका बाद में उन्होंने सम्मान किया, से उपजी थी। लेकिन यह दृष्टिकोण हमें एक प्रमुख सैद्धान्तिक के साथ राजनैतिक पहली के साथ हमें छोड़ देता है : क्या प्रभावी होने के लिए आवश्यक सामाजिक पूंजी के संचय करने के पूर्व सामूहिकता को एक भरोसेमंद सदस्य के रूप में “साबित” करना आवश्यक है? अगर संचय की वह प्रक्रिया जो विषय की बाद में वकालत करती है, शुरूआत में उसको काम आंके तो क्या होगा?<sup>2</sup>

इस प्रश्न का कोई आसान उत्तर नहीं है। समकालीन इजराइली समाज और राजनीति की वर्तमान स्थिति—साथ ही क्षेत्र के अन्य भाग और दुनिया को एक इकाई के रूप में देखते हुए—मैं अक्सर निराशा के नजदीक महसूस करती हूँ, यद्यपि मैं ग्राम्शी की आशा की राजनीति, इच्छाशक्ति का आशावाद और बुद्धि के निराशावाद से जुड़े रहने की कोशिश करती हूँ। यद्यपि बारुक ने हाशिये की तुलना में मध्य से शुरूआत की है, वह भी इसी तरह से कुंठित और उदास महसूस कर रहे थे। मैं वैश्विक संवाद के अन्य पाठकों से जानना चाहूंगी कि उनके अनुसार सार्वजनिक समाजशास्त्रियों और अन्य सार्वजनिक बुद्धिजीवियों को प्रभावी बनने के लिए अपने आप को कहां स्थित करना होगा? ■

नीरा युवाल डेविस से पत्र व्यवहार हेतु पता  
<n.yuval-davis@uel.ac.uk>

<sup>1</sup> Kimmerling B. (2013) *Marginal at the Centre: The Life Story of a Public Sociologist*. New York and Oxford: Berghahn Books, translated by Diana Kimmerling.

<sup>2</sup> The strategy of many of us in the “illegitimate” margins has been, on the one hand, to work as public activists in a variety of specific (often unpopular) campaigns in Israel, as well as to establish dialogues and solidarity with Palestinians and Arabs with similar values and, on the other hand, also work with socialists and human rights defenders outside Israel and the Middle East in order to influence international public and governmental support of Israel.

# > विवेचनात्मक अनुबंध का जीवन

## इस्सा शिवजी के साथ एक साक्षात्कार



इस्सा शिवजी

इस्सा शिवजी उत्तर-औपनिवेशिक अफ्रीका के महान सार्वजनिक बुद्धिजीवियों में से एक हैं। वे दर-एस सलाम विश्वविद्यालय में प्रख्यात वामपंथी विद्वानों गियोबन्नी अरिधि, इम्मानुअल वॉलरस्टीन और जॉन सॉल के सानिध्य में विधि के विद्यार्थी (1967-1970) थे। दुनिया भर से ये विद्वान विश्वविद्यालय के प्रारंभिक बौद्धिक उफान से आकर्षित हो कर यहां आये थे। एक अकालिक विद्यार्थी के रूप में श्री शिवजी ने तन्जानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस न्यरेरे के उज्जमा शासन की समाजवादी नीतियों को चुनौती देनी शुरू कर दी थी। इस प्रारंभिक काल के दौरान उन्होंने प्रख्यात और व्यापक रूप से चर्चित कृतियां जैसे द साइलेंट क्लाफ स्ट्रगल लिखीं जिसने अफ्रीका की नई पोस्ट कॉलोनीयों में उन सामाजिक ताकतों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जो राजनैतिक रूप से (अ) वर्णित थीं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दर एस सलाम विश्वविद्यालय

से डिग्री प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने विधि संकाय में पद ग्रहण किया और जिसे उन्होंने 2006 में सेवानिवृत्ति तक नहीं छोड़ा। इस समय के दौरान वे भूमि सुधार एवं संवैधानिक कानून को समर्पित सार्वजनिक रूप से प्रसिद्ध व्यक्ति बन गये थे। 1980 के दशक में नव उदारवाद की तरफ झुकाव और विश्वविद्यालय के निगमीकरण के प्रति मुखर टिप्पणियों के बावजूद वे राजनैतिक अशांति के दौरान बच गये। 2008 में उन्हें अखिल अफ्रीका अध्ययन में जूलियस न्यरेरे चेयर से सम्मानित किया गया। ऐसा इस उद्देश्य से किया गया कि विश्वविद्यालय को सार्वजनिक बहस के केन्द्र के रूप में बहाल किया जा सकें। प्रोफेसर शिवजी ने कई युवा शिक्षाविदों, जैसे इस साक्षात्कार का संचालन करने वाले राजनैतिक विज्ञान के प्राध्यापक सबाथो न्यामसेण्डा, को प्रेरित किया। वे डरबन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आई. एस. ए. की विश्व कांग्रेस के सक्रिय प्रतिभागी भी थे।

>>

**एस.एन :** दर एस सलाम विश्वविद्यालय (जो म्लमानी या हिल के रूप में जानी जाती है) से आपका सम्बन्ध 1967 में विधि के एक छात्र के रूप में प्रारंभ हुआ और यहां से स्नातक होने के पश्चात आपने इसी विश्वविद्यालय के विधि संकाय में कार्य प्रारम्भ किया—एक पद जिस पर आप 36 वर्षों तक रहे। आपके कई प्रगतिशील सहकर्मियों के अन्य संस्थाओं में जाने के बावजूद आपने विश्वविद्यालय में बने रहने का निर्णय क्यों लिया?

**आई.एस :** यह सच है कि मेरे कई सहकर्मी राष्ट्रीय सेवा कार्यालय, पार्टी और यहां तक कि सेना, अन्य संस्थानों में चले गये। पश्वदृष्टि में यह शायद थोड़ा सीधा लगे परन्तु सच्चाई यह है कि यह सभी कामरेडों का सामूहिक निर्णय था कि कौन कहाँ अधिक प्रभावशाली होगा। कामरेडो ने सोचा और मैं सहमत हूँ कि मुझे प्रगतिशील बौद्धिक और वैचारिक कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय में रहना चाहिए।

विश्वविद्यालय ने प्रगतिशील विचारों को पनपाने के लिए आपेक्षित स्थान अवश्य उपलब्ध कराया। एक ऐसा स्थान जहां प्रगतिशील बौद्धिक सौहार्द को निर्मित एवं उसे सहेजा जा सके। उस समय, साम्राज्यवादी व्यवस्था की गहन बौद्धिक समझ के साथ समस्त राष्ट्रवादी प्रतिबद्धता ने अतिवादी युवा विद्वानों को तैयार करने में मदद की। इनमें से कई माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनें जहां उन्होंने प्रगतिशील विचार और व्यवहार को आगे बढ़ाया।

अपने पूरे कार्यशील जीवन हिल पर व्यतीत करने का मुझे कभी भी अफसोस नहीं हुआ है।

**एस.एन :** आपकी पुस्तक *Accumulation in an African Periphery* में अफ्रीकी देशों और विशेष रूप से तन्जानिया के उत्तर उपनिवेशिक काल को आपने तीन चरणों में विभाजित किया है : राष्ट्रवादी चरण (1960s और 1970s), संकटकालीन चरण (1980s) और उदारवादी चरण (1990 से वर्तमान तक)। इन परिवर्तनों ने म्लमानी को कैसे प्रभावित किया?

**आई.एस :** विश्वविद्यालय एक सामाजिक वातावरण में पाये जाते हैं और स्पष्टतः वे उस वातावरण में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। अस्सी का दशक, हमारे देश और निस्संदेह बाकी अफ्रीका के लिए, अत्यन्त संकट का काल था। संसाधनों को तरसने के साथ साथ विश्वविद्यालय नव उदारवादी नुस्खों के अनवरत वैचारिक और बौद्धिक आक्रमणों का सामना कर रहे थे। हमारे कई साथी दक्षिणी अफ्रीका लेसोथो, बोत्सवाना, स्वाजीलैंड और बाद में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के विश्वविद्यालयों में चले गये।

परन्तु कुछ, जिसमें कई युवा अतिवादी विद्वान जिन्होंने आंदोलनकारी राष्ट्रीय उत्तेजना वाले प्रारंभिक दो दशकों में प्रगतिशील विचारों को आत्मसात किया था, रुके रहे। उन्होंने लगातार अच्छा कार्य करना जारी रखा। उदाहरण के लिए, उन्होंने निरंकुशता—विरोधी और सरकार—विरोधी मत को व्यक्त कर 1983-4 की विशाल संवैधानिक बहस के बौद्धिक पक्ष का नेतृत्व किया। यद्यपि उदार लोकतंत्र, मानवाधिकार, बहु-दल को अंतिम लक्ष्य के रूप में देखने वाली कई तरह की भिन्न प्रवृत्तियाँ थी और वे क्रांतिकारी सुधार की मांग कर रही थीं। इसके पश्चात अल्पसंख्यक प्रवृत्ति ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष को स्वतन्त्र वर्ग क्रिया के विद्यालय के रूप में देखा : उन्होंने क्रांतिकारी सुधार का आह्वान किया। उदाहरण स्वरूप : सुधारवादी बहु-दलीय व्यवस्था को तुरन्त प्रारम्भ करने की मांग रखेंगे जबकि, क्रांतिकारी पहले राज्य और दलों को अलग करने, और द्वितीय, स्वतन्त्रता—पश्चात के काल का ब्यौरा लेने हेतु

एक लंबी राष्ट्रीय बहस और एक नवीन राष्ट्रीय मतैक्य का निर्माण करने की मांग रखेंगे।

राष्ट्रवादी से नव उदारवाद काल तक के संक्रमण के दौरान, हिल बहसों और बौद्धिक संघर्षों का उपयुक्त स्थान था। सरकार के तृतीय चरण में जैसे जैसे नवउदारवाद ने अपने आप को देश में मजबूत किया और विश्वविद्यालय के व्यवसायीकरण और निगमीकरण ने गति पकड़ी, ये धीमे पड़ने लगे।

**एस.एन :** 2008 में, आप अखिल अफ्रीका में मवालियु न्यरेरे प्रोफेशनल चेंबर जो किशवाहिली में किगोडा कहलाती है के पहले पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। आपके पदग्रहण के तुरंत बाद आप ने कहा था कि यह “आप के लिए गर्व” की बात है कि “आप न्यरेरे की विरासत को जिन्दा” रख रहे हैं। आप किस विरासत की बात करते हैं जबकि आपकी कृतियों में वर्णित न्यरेरे, मार्क्सवाद और नीचे से संघर्ष के बहुत खिलाफ था?

**आई.एस :** न्यरेरे अतिवादी राष्ट्रवादी थे। वह प्रगतिशील अखिल अफ्रीकी और व्यापक रूप से साम्राज्यवाद—विरोधी थे। यह सही है कि उनका साम्राज्यवाद—विरोध क्रूमाह जैसे अतिवादी राजनैतिक अर्थव्यवस्था में स्थित नहीं था। तथापि, उनका आम आदमी के पक्ष वाला रवैया सुसंगत था; साम्राज्यवाद—विरोधी स्थान समर्थन योग्य और राष्ट्रवादिता प्रगतिशील थी।

उनके बाद आने वाले नव—उदारवाद वर्ग की तुलना में और हमारे समाज में इस वर्ग द्वारा उत्पन्न तबाही के मद्देनजर, कोई भी प्रगतिशील, एक मार्क्सवादी भी, न्यरेरे की विरासत को याद नहीं करना चाहेगा और पूंजीवाद के वर्तमान सवग्राही चरण के विरुद्ध संघर्ष में इसे बौद्धिक स्रोत के रूप में काम में नहीं लेना चाहेगा।

न्यरेरे मार्क्सवादी नहीं थे और उसने स्वयं को उस रूप में छिपाया भी नहीं। जब मार्क्स का सामना भोंडे मार्क्सवाद से हुआ तो उसने चिल्ला कर कहा “मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ।”

यह सही है कि देश के मुखिया के रूप में, वे नीचे से संघर्ष के खिलाफ थे। परन्तु क्या इसका अर्थ है कि एक प्रगतिशील व्यक्ति को न्यरेरे की प्रगतिशील विरासत का उल्लास नहीं मनाना चाहिए और उसके विरोधाभासी चरित्र से सीख लेनी चाहिए? मेरे दोस्त, मार्क्सवादी शुद्धतावादी नहीं है; वह राजनैतिक है।

**एस.एन :** न्यरेरे की विरोधाभासी विरासत से आपका क्या तात्पर्य है?

**आई.एस :** मैं मवालियु के बारे में किस्सा सुनाने से बेहतर कुछ नहीं कर सकता। 1978 में राज्य के खिलाफ प्रदर्शन करने के कारण छात्रों को हिल से बाहर निकाल देने के कुछ महीनों पश्चात, वे कैम्पस पर आये। एक छात्र ने बहादुरी से उनसे इस प्रकार से यह पूछा : “मवालियु, आप लोकतंत्र की बात करते हैं परन्तु जब हमने लोकतंत्र के हित में प्रदर्शन किया तो आपने हमें पीटने के लिए FFU (क्षेत्रीय बल इकाई) भेज दी!”

मवालियु ने उसे घूरा और जवाब दिया : “आप क्या अपेक्षा करते हैं? मैं राज्य का मुखिया हूँ; मैं हिंसा के एकाधिकार रखने वाली संस्था का अध्यक्ष हूँ। यदि आप सड़कों पर दंगा करेंगे तब निस्सन्देह मैं FFU भेजूंगा। परन्तु क्या इसका यह अर्थ है कि आपको लोकतंत्र के लिए लड़ना नहीं चाहिए? लोकतंत्र कभी भी चाँदी की तश्तरी में नहीं दिया जाता है।” (उनके सटीक शब्द नहीं)

और हम सबने ताली बजाई। मवालियु जो चाहते थे वो कर सकते थे।

**एस.एन :** ईरानी क्रांतिकारी बौद्धिक अली शरीयती ने एक बार विश्वविद्यालयों को “अपराजेय दृढ़ गढ़”, जिनका मुख्य कार्य कार्पोरेट दुनिया के लिए बौद्धिक दास का उत्पादन करना है, का नाम दिया। क्या अखिल-अफ्रीकी अध्ययन प्रोग्राम, किगोड़ा म्नीमानी “गढ़” के दरवाजे खोलने में सफल हो सका और उसके बुद्धिजीवियों को जनसाधारण से जोड़ सका? यदि हां तो कैसे?

**आई.एस :** मेरे लिए यह दावा करना कि किगोड़ा विश्वविद्यालय “गढ़” के दरवाजे खोलने में कामयाब हुआ, मूर्खता होगी। अल्थूजर के शब्दों में, विश्वविद्यालय वैचारिकी सरकारी अमले का हिस्सा होती हैं। वहां के प्रभुत्वशाली बुद्धिजीवी, प्रभुत्वशाली ज्ञान जो प्रभुत्वशाली विचारधारा का आधार बनता है, के उत्पादक और संवहक होते हैं।

परन्तु ज्ञान के उत्पादन की प्रक्रिया की प्रकृति के कारण, विचारों में टकराव स्वाभाविक है। यह प्रभावशाली के अलावा अन्य दृष्टिकोणों के लिए कुछ जगह छोड़ने की अनुमति देता है। तथापि, इन स्थानों को बेकार नहीं समझना चाहिए। उनकी अपनी सीमाएं हैं और संकट के समय, ये स्थान भी दबा दिये जाते हैं। इन प्रगतिशील रिक्त स्थानों को सतत आधार पर प्राप्त और पुनः प्राप्त करना एक संघर्ष है। और सभी संघर्षों के समान, ये बौद्धिक संघर्ष उनके स्वरूप और पद्धति के लिए कल्पनाशीलता की मांग करते हैं।

किगोड़ा यही सब करना चाहता था; इससे अधिक कुछ नहीं। शायद इसने कुछ बौद्धिक उत्साह पैदा करने में कामयाबी प्राप्त की; शायद यह युवा बुद्धिजीवियों और लोगों के साथ विश्वसनीयता हासिल करने में कामयाब रहा; शायद यह हिल के प्रगतिशील अभिलेखों की खुदाई करने में कामयाब रहा। इसकी भी सीमाएं थी और ये सीमाएं मेरे काल के अंत तक दिखाई देने लगी थीं।

दी गई परिस्थितियों में कोई भी इतना ही कर सकता है। मेरे ख्याल से ई. एच कॉर ने प्लेखोनोव और उसके पहले मार्क्स का अनुसरण करते हुए कहा था कि जहां व्यक्ति इतिहास बनाते हैं, वे उन परिस्थितियों को नहीं चुनते जिसमें वे ऐसा करते हैं।

**एस.एन :** न्यरेरे ने एक बार पीड़ितों को पैसे को अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। तथापि, आज कल बौद्धिक परियोजनाओं के लिए कोष एकत्रित करना केन्द्रीय बन गया है। कोई भी कार्य पैसे के बिना नहीं किया जाता है। यहां तक कि सबसे प्रगतिशील संगठनों को भी पैसे की तलाश में पूंजीवादी अभिकरणों के आगे घुटने टेकना अपरिहार्य लगता है। किगोड़ा ने अपनी गतिविधियां कैसे संचालित की?

**आई.एस :** हां, पैसा और उस पर भी दान का पैसा, बुद्धिजीवी परियोजनाओं को चलाने वाली मोटर बन गया है। बेशक, किगोड़ा को पैसों की मुश्किल का सामना करना पड़ा, परन्तु इसने प्रारंभ में ही कुछ सिद्धान्त स्थापित कर दिये। प्रथम, चैयर एवं उसके सहायक

के वेतन सहित सभी प्रशासकीय खर्च, नियमित विश्वविद्यालय बजट से होंगे। द्वितीय, किगोड़ा विदेशी दानदाताओं से पैसा लेने से बचेगा। तृतीय, जो कुछ भी पैसा घरेलू लोक संस्थाओं या दोस्ताना अफ्रीकी बौद्धिक संगठनों से मिलेगा, वह बिना शर्त के होना चाहिए। और अंत में, किगोड़ा का एजेण्डा और गतिविधियां किगोड़ा सामूहिक द्वारा सख्ती से निर्धारित की जायेंगी।

यह आसान नहीं था परन्तु स्वैच्छिक कार्य पर अधिक जोर दे कर और काफी मितव्ययता से खर्चा कर अपने बजट को साधारण रख कर हमने ऐसा करने में सफलता पाई।

**एस.एन :** अब जब आप विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हो गये हैं, आप कौन से प्रोजेक्ट करने की योजना बना रहे हैं?

**आई.एस :** विश्वविद्यालय में रहते समय, अपने दो सहकर्मियों, प्रोफेसर सर्ईदा याह्या-ओथमन और डॉ. न्वावान्जा कमाता के साथ मैंने म्वालियु न्यरेरे की निश्चित/निर्णायक जीवनी लिखने का प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया था। यह प्रोजेक्ट तन्जानिया के विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग द्वारा समर्थित है। हमने अपना अनुसंधान करीब करीब समाप्त कर लिया है—यदि आप इस प्रकार के अनुसंधान को कभी पूरा कर सकते हैं—और अब लिखने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

इस प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण परिणाम न्यरेरे संसाधन केन्द्र (NRC) की स्थापना है। केन्द्र में एक प्रलेखन कक्ष होगा जहां हमारे द्वारा एकत्रित सभी सामग्री को संग्रहित किया जायेगा और शोधार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा। केन्द्र के चारों ओर हम रणनीतिक सोच, बहस और चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से गतिविधियों का आयोजन करेंगे। हमें इस वर्ष गतिविधियों को प्रारंभ करने की उम्मीद है। यह मेरी उम्मीद है कि NRC देश और महाद्वीप से समक्ष कई ज्वलंत मुद्दों पर चिन्तन करने वाला एक केन्द्र बनेगा।

मैं महसूस करता हूँ कि नव-उदारवाद, गैर-सरकारी संस्थाकरण और नीति पर अधिक जोर—“ज्यादा काम” और “कम चिन्तन” के साथ परामर्श संस्कृति और निर्देशात्मक पूर्वानुमान ने हमारे बौद्धिक चिन्तन पर प्रहार किया है। इसका परिणाम यह है कि हमने दुनिया को विश्लेषित करना और समझना छोड़ दिया है। हम दुनिया को बेहतर ढंग से समझे बिना बेहतर दुनिया के लिए लड़ भी नहीं सकते हैं। इसके लिए, हमें इतिहास को एक लंबे समय तक देखने की जरूरत है। आशा है कि, केन्द्र समग्र, दीर्घकालिक सोच की संस्कृति को पुनर्जीवित करने की दिशा में योगदान देगा। ■

सबाथो न्यामसेण्डा से पत्र व्यवहार हेतु पता <[sany7th@yahoo.com](mailto:sany7th@yahoo.com)> और इस्सा शिवजी से पत्र व्यवहार हेतु पता <[issashivji@gmail.com](mailto:issashivji@gmail.com)>

# > पूंजीवाद बनाम् जलवायु न्याय

हर्बर्ट डोकेना, केलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले, यू. एस. ए. और सदस्य, आई एस ए श्रम आंदोलनों पर शोध समिति (RC 44)



लीमा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रकृति की रक्षा करने के लिए 'व्यवस्था को बदलो न कि जलवायु को' की मांग रखते हुए दुनिया भर से आये सामाजिक आंदोलनों के नेतृत्व में निकाला गया द पीपुल्स मार्च।  
चित्र : हर्बर्ट डोकेना

**19** 72 में स्टॉकहोल्म में आयोजित पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र की पहली कांग्रेस के बाद से, दुनिया भर के हजारों लोग एक बार फिर एक वैकल्पिक "पीपुल्स समिति" के लिए दिसम्बर (2014) में एकत्रित हुए। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के दलों के नवीनतम सम्मेलन (COP) के लिए सैंकड़ों राज्यों के प्रतिनिधियों के सैन्य शिविर में मिलने के दौरान इन्होंने लीमा (पेरू) की सड़कों पर मार्च किया।

'पीपुल्स समिति' के दौरान मांगे हमेशा की तरह विविध थीं। कुछ रंगबिरंगी तख्तियाँ जिन पर "हम गंभीर जलवायु परिवर्तन कानून की मांग करते हैं।" या "और भाषण नहीं, काम करो।" लिखा था, लहरा रहे थे। यह ऐसी मांग थी जो मार्च करने वालों और कुछ चौदह किलोमीटर की दूरी पर अधिकारित सम्मेलन में भाग ले रहे प्रतिनिधियों के मध्य हितों की समरसता है या हो सकती है, का सुझाव देती हैं। यह भी सुझाती है कि उत्तरवर्ती वर्तमान व्यवस्था के

अन्तर्गत "गंभीर जलवायु परिवर्तन कानून" पारित कर सकते हैं।

परन्तु सबसे अधिक समान मांग जो मैंने सुनी वह केन्द्रीय बैनर जिस के पीछे सब मार्च कर रहे थे, पर व्यक्त "व्यवस्था को बदलो, जलवायु को नहीं" और इसके अन्य रूपांतर जैसे "पृथ्वी को पूंजीवाद से बचाओ" और अन्य ऐसे कथन "पूंजीवादी : हत्यारे!" या "COP : शिकारियों का अड़्डा" थीं। यह मांगे संकेत करती हैं कि इन मांगों को रखने वाले और जिन्हें सम्बोधित किया जा रहा है में बुनियादी वैर-भाव है और सम्बोधित किये जाने वाले वर्तमान व्यवस्था में "पृथ्वी को बचाने" में असक्षम हैं।

हाल ही के वर्षों में "व्यवस्था परिवर्तन" की यह मांग दुनिया भर से काफी बड़ी संख्या में उठ रही है : गत सितम्बर में 400-500 सदस्यों के सशक्त मार्च में, वारसों के 2013 संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में छोटे प्रदर्शन में, 2010 में कोचाबम्बा में जलवायु परिवर्तन पर विश्व सामाजिक आंदोलन पर अभूतपूर्व सम्मेलन में, 2009 में कोपनहेगन शिखर

सम्मेलन, और संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के अन्दर भी बोलिविया के आत्म-घोषित समाजवादी राष्ट्रपति इवो मोरालेस द्वारा।

एक तरह से, लीमा में इसका महत्व, इस वर्ष की संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के आयोजन महाद्वीप पर आतंकवाद के उच्च स्तर पर चिन्ता थी। परन्तु लीमा के पार इसकी बढ़ती प्रतिध्वनि/गूंज दुनिया भर में लोगों के अवचेतन और पहचान में व्यापक परिवर्तन और इसके साथ ही वैश्विक आर्थिक संकट के चारों तरफ सामाजिक शक्तियों के व्यापक संतुलन में गहरे परिवर्तन का संकेत भी हो सकती हैं। यह विश्व के प्रभुत्वशाली ब्लाक द्वारा अपनी सबसे शक्तिशाली शक्तियों में एक : लोग दुनिया को कैसे देखते हैं और अपने आप को कैसे श्रेणीबद्ध करते हैं को आकार दे कर बहस के संदर्भ और भाषा को नियत करने की दक्षता को प्रयोग में लेने की बढ़ती असमर्थता की ओर संकेत करती है।

आखिरकार, कम से कम 1970 के दशक से, राज्य अधिकारी, कार्पोरेट कार्यकारी

>>

और अन्य बुद्धिजीवी सक्रिय रूप से भिन्न और कभी कभी प्रतिस्पर्धात्मक तरीकों में, परिवर्तन की किसी भी मांग को अचिन्तय और अकथनीय बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा दुनिया के सत्तारूढ़ समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली विश्व दृष्टि या विचारधारा को पृथ्वी के 'रक्षक', जिनके हित 'लोगों' के साथ बुनियादी सद्भाव में हैं और जो पूंजीवाद के भीतर ही संकट का हल निकालने में सक्षम हैं, के रूप में प्रचारित और विस्तारित किया है।

वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के लिए पूंजीवाद पर दोष मढ़ने वाले और जिसने प्रभावी रूप से सार्वभौमिक हितों को बढ़ावा देने वाले उनके दावों या प्रधान्य पर सवाल उठाने वाले अतिवादी पर्यावरणीय आंदोलनों में अचानक अप्रत्याशित वृद्धि ने उन्हें तथाकथित वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन के विश्लेषकों द्वारा कई बार छूटा एक तरह के संघर्ष : इस परिवर्तन को कैसे समझा जाए और इसका प्रतिनिधित्व कैसे किया जाए, में संलग्न होने का मजबूर किया है।

OECD, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और गैर सरकारी संगठनों एवं वैश्विक नागरिक समाज के अन्य संगठनों के समूहों के ज्ञान उत्पादन उपकरणों के माध्यम से वे अगले दो दशकों में "संपोषित विकास" या "पारिस्थितिक आधुनिकीकरण" जैसे विमर्श विकसित और उनका प्रसार कर अतिवादी पर्यावरणविद् आलोचकों से मुकाबला करेंगे व उन्हें विक्षेपित करने का प्रयास करेंगे। ये विमर्श पारिस्थितिक संकट के लिए कभी भी पूरी व्यवस्था को नहीं अपितु 'बाजार की विफलता', निहित स्वार्थ या फिर सिर्फ जीवाश्म ईंधन उद्योग को दोषी ठहराते हैं और पूंजी को कृपालू, जिम्मेदार भागीदार के रूप में चित्रित करते हैं। रोजाना की संस्थागत कार्यप्रणालियों – वर्ग के अपितु देशों द्वारा उत्सर्जन की गणना के तरीकों से ले कर प्रदूषकों को दण्ड देने के बजाय लुभा कर के द्वारा वे लोगों में सामान्य दृष्टिकोण बिठा देना चाहते हैं कि व्यवस्था समस्या नहीं है और पूंजी दुश्मन नहीं है।

संक्षेप में, वैश्विक अभिजन वैश्विक संस्कृति को आकार देने या लोगों की सामान्य बुद्धि को ढालने पर कार्य कर रहे हैं ताकि वे अतिवादी आंदोलनों द्वारा पेश विचारों का मुकाबला कर सकें एवं उनके द्वारा भड़काये प्रतिरोध को शांत कर सकें। एक हद तक वे सफल भी हुए हैं। एक समय में पूंजीवादी प्रधान्य को हिला देने वाले शक्तिशाली अतिवादी आंदोलनों को 70 और

80 के दशक के प्रारम्भ में हाशिये पर धकेल दिया गया था। "व्यवस्था परिवर्तन" की मांग करने वालों को सफलतापूर्वक दीवाने चरमपंथियों के रूप में कास्ट कर दिया गया था। सचमुच, "व्यवस्था परिवर्तन" के बजाय कयामत की कल्पना करना अधिक आसान हो गया था।

हालांकि लीमा में और दुनिया भर में, लोगों की एक बढ़ती संख्या—जिसमें सर्वाधिक बिक्री करने वाले लेखक नाओम क्लेन, पोप फ्रांसिस और अन्य प्रभावशाली लोग सम्मिलित थे—एक बार पुनः पूंजीवाद को जलवायु परिवर्तन से स्पष्ट रूप से जोड़ रही है। वे पूंजीपतियों को क्रूर दरिदों के रूप में वर्गीकृत कर "प्रणालीगत विकल्पों" की कल्पना कर रहे हैं। यह सब इंगित करता है कि नायक एक अतिवादी वैश्विक आधिपत्य विरोधी आंदोलन को पुनः उभरने से रोकने में सफल नहीं हुए हैं। हालांकि अभी तक जैसा लीमा में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के परिणाम दर्शाते हैं, यह आंदोलन अभी भी दुनिया के प्रभावशाली समूहों द्वारा पारिस्थितिक संकट के लिए अपने पसंदीदा "समाधान" को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है।

वे चाहे इस बात से इंकार करें कि संकट व्यवस्था में आंतरिक रूप से निहित है—और कम दूरदर्शी अधिकारी और व्यापारिक प्रबंधक के संकट की मौजूदगी से इंकार करना और सबसे कमजोर सुधारों का विरोध करने के बावजूद—पूंजीवाद के सेनाग्र OECD, विश्व बैंक, विश्वविद्यालयों, नीति निर्माण विभागों आदि में अपने नजरिये से वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रबंधन का प्रयास करते हैं। ऐसे नेताओं ने अतिवादी पर्यावरणविदों के नारों को वास्तव में बहुत गंभीरता से लिया है। वे "व्यवस्था बदलने" के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन ऐसे कि वह बुनियादी तौर पर समान ही रहे।

पारिस्थितिक संकट और अतिवादी आंदोलनों से धमके, प्रभावशाली समूहों के साथ संरेखित अधिक दूरदर्शी बुद्धिजीवी किसी तरह के "वैश्विक पर्यावरणीय प्रबंधन" को कैसे किया जाए ताकि प्रकृति का पूंजी द्वारा शोषण को "नियोजित" या विनियमित किया जा सके, पर पिछले 30 वर्षों से अन्वेषण और बहस कर रहे हैं।

पिछले पाँच वर्षों में, कई—ज्यादातर परन्तु सिर्फ विकसित देशों से नहीं— एक आम दृष्टिकोण पर जुटे हैं : वह है वैश्विक नवउदारवादी विनियमन के माध्यम से "पारिस्थितिकी आधुनिकीकरण"। यह ऐसा

समाधान है जो 1) सभी सरकारों को कुल वैश्विक उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देने के लिए मापदण्ड निर्धारित करता है परन्तु अंततः क्यों, कैसे और कितना का निर्णय प्रत्येक सरकार पर छोड़ देता है, जबकि उसी समय 2) "कार्बन पर मूल्य निर्धारित कर" पूंजी को "कम-कार्बन" निवेश एवं प्रौद्योगिकी के संक्रमण के लिए लुभाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए "लागत प्रभावी" समाधान ढूँढने की अभियांत्रिकी बाजार तंत्र को अनुमति देता है।

यह सही है कि इस समाधान के समर्थक वैश्विक अभिजनों की आम सहमति प्राप्त करने में पूर्ण रूप में सफल नहीं हुए हैं। वैश्विक दक्षिण से इसका विरोध हुआ है। आंशिक रूप से क्योंकि अपने घर में शासन करने की सहमति प्राप्त करने की उनकी क्षमता उत्तर से प्राप्त रियायतों पर निर्भर करती है, विकासशील देशों के सब नहीं तो कई सत्तारूढ़ कुलीन वर्ग अधिक सामाजिक लोकतांत्रिक वैश्विक विनियमन के माध्यम से एक वैकल्पिक पारिस्थितिक आधुनिकीकरण के लिए मुहिम चला रहे हैं। इस समाधान में दुनिया के राज्य, एक अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए, कुल वैश्विक उत्सर्जन पर संयुक्त रूप से सीमा लगाएगी और इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मुख्य रूप में बाजार की कार्यप्रणाली पर निर्भर न रह कर सरकारों पर प्रत्यक्ष रूप से अपने उत्सर्जन को कम करने और विकासशील देशों को संसाधन हस्तांतरण करने की वैश्विक पुनर्वितरण नीतियां बनायेगी।

लेकिन अपनी आंतरिक कमजोरियों और विरोधाभासों से भरी विकासशील देशों की सरकारें साल दर साल, विकसित देशों द्वारा प्रस्तावित बाजार समाधान को ब्लाक करने और अपने स्वयं के वैश्विक समाधानों के लिए समर्थन जुटाने में असमर्थ रही हैं या अनिच्छुक रही हैं। वार्ताओं के दौरान विकसित देशों के खिलाफ सभी कटु झगड़ों के कारण दक्षिण के कई सत्तारूढ़ कुलीन अंततः लक्ष्य को साझा करते हैं : व्यवस्था को इस तरह बदलना कि वह बुनियादी तौर पर अपरिवर्तित रहे।

इसका परिणाम यह है कि विकसित देशों के अधिकारी एक नये अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन समझौते की नींव को स्थापित करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस समझौते पर अगले वर्ष पेरिस में हस्ताक्षर होंगे और यह वैश्विक नवउदारवादी विनियमन की तर्ज पर 2020



कई वर्षों में एक अत्यंत उग्र अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में विभिन्न राजनैतिक स्पेक्ट्रम से आये लोगों की लीमा शहर में बाढ़ सी आ गई।  
चित्र : हर्बर्ट डोकेना

में प्रभावी होगा। परन्तु भयावह जलवायु परिवर्तन को टालने हेतु उत्सर्जन में कमी लाने या इसके प्रभाव से निपटने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में यह समझौता शायद ही सफल हो। अतः हम एक ऐसे समझौते के तरफ बढ़ रहे हैं जो जलवायु अराजकता और बर्बरता के एक नये युग का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

लेकिन अभी उम्मीद है। आखिरकार, प्रभावशाली ब्लॉक की इस समाधान को थोपने की क्षमता अंततः प्रतिरोध से ध्यान हटाने की उनकी लगातार क्षमता पर टिकी हुई है, जो आगे अपने आप को “भागीदार” के रूप में प्रतिनिधित्व करने की उन की सतत क्षमता पर निर्भर है। बाद में यह फिर दूसरों को यह विश्वास दिलाने पर टिकी है कि वे सार्वभौमिक हितों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और यह कि वे मौजूदा व्यवस्था में संकट का समाधान कर सकते हैं। इस सबके लिए संसाधनों का बलिदान देना होगा जो शासक गुट करना नहीं चाहते है या करने में असमर्थ हैं।

अपने प्राधान्य दावों को सहयोग देने में प्रभावशाली समूहों की ऐसी विफलता अधिक मोहभंग, क्रोध और उत्कंठा को पैदा करेगी। इसके संकेत हमें लीमा वार्ता को छोड़ कर आने वाले नरम पर्यावरणविदों के समूह और आंदोलनों, जो 1972 तक जाते हैं, द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि आधिकारिक बैठक

में भाग लेने वाले “गंभीर जलवायु परिवर्तन कानून” को पारित करने में असमर्थ है की बढ़ती स्वीकार्यता में मिलते हैं।

परन्तु क्या यह प्रकट प्राधान्य संकट जलवायु परिवर्तन के लिए कुलीन वर्ग के गैर समाधान का मुकाबला करने के लिए आवश्यक सामाजिक बल जुटाने में सक्षम आंदोलन में बदलेगा—क्या मोहभंग और उत्कंठा सक्रिय प्रतिरोध में बदल जाएगी—किसी भी तरह स्पष्ट नहीं है। कई भिन्न राजनैतिक प्रवृत्तियों के कई लोगों को सड़क पर लाने और उनकी “साधारण बुद्धि” और व्यक्तिपरकता को नये सिरे से बनाने के लक्ष्य के बीच पुरानी टेंशन पर दक्षता से वार्ता करने की क्षमता पर निर्भर करता है। ये दोनों लक्ष्य हमेशों से समनुरूप नहीं रहे हैं क्योंकि व्यापक गठबंधन विकसित करने से “लघुत्तम” के लक्ष्य का विकास करना, मौजूदा विश्वास को बढ़ावा देना और “व्यवहारिक बुद्धि” की भाषा—एक ऐसी भाषा जो प्रभावशाली के दावों को चुनौती देने के बजाय पुष्ट करती है, बोलने पर दबाव पड़ता है। व्यवहारिक बुद्धि को बदले बिना, सबसे व्यापक गठबंधन और सबसे बड़े प्रदर्शन भी व्यवस्था को समान रखने के लिए परिवर्तित करने के लक्ष्य में शक्तिशाली की मदद करने में बदल जाते हैं।

एक ऐसी रणनीति की आवश्यकता है जो जनता को विमुख नहीं करती लेकिन

गहरी जड़े जमा चुकी श्रेणियों और मानी गई विश्व दृष्टि और स्वप्न जो लोगों को इस व्यवस्था के साथ अपने भविष्य को लगाने के लिए प्रेरित करता है, पर आक्रमण करने से हटती नहीं हैं। इसके अंतर्गत “बड़े प्रदर्शन” को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र की वार्ता पहले नहीं, बल्कि खत्म होने के बाद नियत करना होगा, ताकि इस ..... का खण्डन किया जा सके कि “लोग” पृथ्वी को बचाने के लिए दुनिया के अभिजनों की बुद्धिमानी और कृपा पर भरोसा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जलवायु संकट को वर्ग के बजाय राज्यों के संदर्भ में फ्रेम करने, कार्बन बजट को देशों में विभाजित करने जैसे प्रस्ताव और प्रगतिशील लगने वाले समाधानों की पूछताछ करनी होगी। इसमें प्रगतिशील, समाजवादी सरकारों को भी गैर—निष्कर्षण, गैर जीवाश्म ईंधन निर्भर विकास पथ को गले लगाने का आह्वान शामिल होगा।

एजेंडे पर “व्यवस्था को बदलो” को रखने में सफल होने के बाद, “प्रणालीगत विकल्पों” और हमारे ठोस अनुमानों को बता कर अब इसे प्रेरणाकारक बनाने का कार्य है। ■

हर्बर्ट डोकेना से पत्र व्यवहार हेतु पता  
<[herbertdocena@gmail.com](mailto:herbertdocena@gmail.com)>

# > सार्वजनिक समाजशास्त्र का निर्वाह करना

अरियाने हनेमायर, अलबर्टा विश्वविद्यालय, कनाडा और क्रिस्टोफर जे श्नाइडर, विलफ्रेड लॉरियर विश्वविद्यालय, कनाडा



अरियाने हनेमायर और क्रिस्टोफर श्नाइडर लोक समाजशास्त्र के साथ प्रयोग करते हैं।

**सा**र्वजनिक समाजशास्त्र का आधार जनता को पारस्परिक शिक्षा के संवाद में संलग्न करना है। सार्वजनिक समाजशास्त्र को निर्वाह करने के कई रोमांचक तरीके हैं। इस लघु निबन्ध में हम सार्वजनिक समाजशास्त्र को निर्वाह करने के दो “एनोलोग” संस्करणों को अन्वेषित करते हैं (“डिजिटल” के लिए हनेमायर और श्नाइडर की द पब्लिक सोशियोलोजी डिबेट में आई एस ए की “सार्वजनिक समाजशास्त्र, लाइव!” या “ई—सार्वजनिक समाजशास्त्र” को देखें) पहले प्रयोग में एक समाजशास्त्र “दार्शनिक कैफे” का विकास करना था जिसे हम “सण्डे सोशियोलोजिस्ट” के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसी में से हमारा दूसरा प्रयोग, स्थानीय कॉफी हाउस में हमारी सण्डे सोशियोलोजिस्ट की बैठकों के दौरान उभरने वाले विमर्श से एक विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम संस्करण निकला। कॉफी

हाउस या “पेनी विश्वविद्यालय” जैसा उन्हें कभी कभी कहा जाता है (पेनी प्रवेश शुल्क के संदर्भ में) ने ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण सामाजिक वातावरण के रूप में सेवा प्रदान की है जहां बहुल जनता जिसमें विद्यार्थी, व्यापार और बुद्धिजीवी सम्मिलित होते हैं के मध्य संवादकीय आदान प्रदान होता है।

2009 में “पेनी विश्वविद्यालय” से प्रेरणा ले कर हमने सण्डे सोशियोलोजिस्ट ([www.sundasociologist.com](http://www.sundasociologist.com)) प्रारम्भ किया। इस का उद्देश्य अलग-अलग और व्यापक परिप्रेक्ष्य/दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों को एक साथ लाना था। हमने समुदाय सदस्यों, विश्वविद्यालय संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों को केलोवाना, ब्रिटिश कोलम्बिया, कनाडा के मध्य में स्थित स्थानीय कॉफी की दुकान में महीने में एक बार आने और आपसी महत्व के मुद्दों पर चर्चा

>>



और बहस करने के लिए आमंत्रित किया (राष्ट्रीय समाचारों, वायरल विडियो, राजनैतिक प्रोजेक्ट इत्यादि)। इन बैठकों का लक्ष्य एक तरफ तो विविध आबादी तक पहुंचना और दूसरी तरफ स्थानीय एवं वैश्विक महत्व के मामलों पर आपसी शिक्षा में संलग्न होना था। बातचीत ने काफी बार फलदायक और जोशीले बहस को प्रोत्साहित किया जिसने महत्वपूर्ण निजी परेशानियों और सार्वजनिक मुद्दों को विश्वविद्यालय की कक्षाओं से परे हमारे पेशेवर समाजशास्त्री के जीवन को रवा बनाने, आकार देने और विकसित करने में मदद की। हमने अपनी बैठकों को प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को सांयकाल में आयोजित करने का निर्णय लिया। समय निर्धारण, पूर्ण कालिक रोजगार में वे लोग जो सप्ताह के दौरान शायद अन्यथा व्यस्त हो, को आकर्षित करने के लिए एक जानबूझ किया गया प्रयास था। हमने एक शुल्क रहित वेबपेज के माध्यम से समाजशास्त्री कैफे का प्रचार किया। मासिक बैठकों में विभिन्न संकाय सदस्यों, विश्वविद्यालय एवं उच्च-विद्यालय के विद्यार्थी, सेवानिवृत्त लोग और साथ ही में स्वयं को "वैक्यूम विक्रेता" और "सामान्य जन" के रूप में बताने वाला एक ब्रेनडन नाम के व्यक्ति ने भाग लिया।

यद्यपि हमारा समाजशास्त्रीय कैफे का सप्ताह के एक दिन पर नामकरण हुआ था, हम इस विचार को महत्व देना चाहते थे कि चाहे हम जीवन में किसी भी व्यवसाय राजनैतिक या सामाजिक में हो, हम सभी अपने जीवन में समाजशास्त्रीय प्रश्नों पर सोचते हैं—चाहे हम इसे जानते हैं या नहीं। पेशेवर केमिस्ट के विपरीत, जनता हमारी प्रयोगशाला में रहती है—सामाजिक उन्हें आकार देता है और वे सामाजिक को आकार देते हैं। समाजशास्त्रीय कल्पना के रोगाणु पहले से ही मौजूद है। यदि समाजशास्त्रीय कल्पना एक रविवारीय संध्या को चिन्तन के लिए प्रोत्साहित कर सकती है तब इस तरह के विचारों के विकास को हमारी कॉफी हाउस बैठकों में आने वाली जनता के जीवन में एक उपयोगी कामगार साधन के रूप में देखा जा सकता है।

सण्डे सोशियोलोजिस्ट ने अपने स्वयं के पाठ्यक्रम के साथ विश्वविद्यालय प्रायोजित पाठ्यक्रम कोर्स को प्रेरित किया। इसका उद्देश्य जनता के सदस्यों को समाजशास्त्र के एक पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना था। प्रत्येक सप्ताह, एक आमंत्रित समाजशास्त्री सार्वजनिक रूप से सुलभ तरीके से एक घंटे का व्याख्यान और उसके बाद एक घंटे की लघु समूह चर्चा (कोर्स में 30 विद्यार्थियों की सीमा थी) की पेशकश करेगा। कोर्स और प्रत्येक अतिथि वक्ता का प्रचार साप्ताहिक तौर पर विश्वविद्यालय प्रेस विज्ञापित और सामाजिक मीडिया पर किया गया था। (साप्ताहिक उपस्थिति आम तौर पर लगभग 100 व्यक्ति थी) समाजशास्त्र के विद्यार्थी और जनता के सदस्य चर्चा समूहों में बांटे किये गये थे ताकि वे आपसकी संवाद कायम कर सकें।

फिर, आमंत्रित समाजशास्त्र के प्रोफेसर और शिक्षण सहायक के साथ, सुनने और संवाद में समाजशास्त्रीय सामग्री डालने के लिए हम समूहों के मध्य घूम रहे थे।

नियमित रूप से सण्डे सोशियोलोजिस्ट में आने वाले कुछ लोगों ने कोर्स में भाग लिया। प्रतिक्रियाएँ उत्साही थीं। उदाहरण के लिए, वैक्यूम विक्रेता ब्रेनडन ने कहा : "इन बातचीतों में भाग लेने और मेरे लिए ताज्जुब कि मैं भी योगदान कर सकता हूँ, एक अत्यन्त सशक्त और स्फूर्ति देने वाली प्रक्रिया रही है, ऐसी जिसका मुझे कभी पहले अनुभव नहीं हुआ है।" एक अन्य सार्वजनिक सदस्य प्रतिभागी ने कहा : मेरे जैसे 80 साल की आयु वाले व्यक्ति के लिए युवा और जीवन्त मनस को सुनना और उनके साथ घुलना—मिलना सौभाग्य और खुशी की बात रही।

सार्वजनिक समाजशास्त्र की इन पहलों ने हमें हमारे पेशेवर सामाजिक प्रतिबद्धताओं और दृष्टिकोणों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। हमारे द्वारा सामना की जाने वाली सबसे लगातार दुविधाओं में से एक, जटिल समाजशास्त्रीय विचारों को प्रासंगिक और स्पष्ट कैसे किया जाये, थीं। समुदाय के अन्तर्गत हमारे काम हमारे पेशेवर कार्य के साथ काफी भार डालने वाला परन्तु यह एक अविश्वसनीय रूप से पुरूस्कृत सार्वजनिक शिक्षण अनुभव था। हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारा जनसमर्थन मिला और हमारे कार्य में समुदाय को जोड़ने के लिए नये और अभिनव तरीकों को तलाशना काफी आशाप्रद लगा। इन प्रोजेक्टों की सफलता में व्यापक संदर्भ द्वारा योगदान की संभावना अधिक थी।

कलोना एक विशिष्ट रूप से धनी सेवानिवृत्त समुदाय है, ब्रिटिश कोलंबिया के दक्षिणी भीतरी इलाकों में रहने के लिए बहुत ही वांछनीय जगह है। सण्डे सोशियोलिजिस्ट और सार्वजनिक समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम के कई प्रतिभागी स्नातक डिग्री के साथ धनी सेवानिवृत्त लोग थे। उदाहरण के लिए, कोर्स और सण्डे सोशियोलोजिस्ट के नियमित सार्वजनिक प्रतिभागी ने कहा : "मैं भूल गया था कि 70 और 80 के दशक में मैंने कॉलेज में समाजशास्त्र का कितना आनंद लिया था और मैं अपने आप को फिर कितना उत्तेजित महसूस कर रहा हूँ।" श्रमिकों के कार्यशील समुदाय में समान प्रोजेक्ट को विकसित करने की कोशिशें शायद अलग चुनौतियों का सामना करेंगी। जिस समुदाय के लिए हमने प्रोजेक्ट का निर्माण किया, उसकी विशिष्ट मान्यताओं पर हमारा प्रोजेक्ट निर्भर था : हम यह मान सकते थे कि अधिकांश लोगों के पास कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच थी, वे स्थानीय समाचार और घटनाओं को विज्ञापित करने वाले वाम झुकाव वाले रेडियो चैनल को सुनते हैं और यह कि वे विश्वविद्यालय के साथ वैकल्पिक रूपों में संलग्न होने के लिए प्रेरित थे। अपने गृह समुदायों में इस तरह के समान पहलों को लाने की आशा करने वाले समाजशास्त्रियों को उनके विशिष्ट संदर्भ में जनता को संलग्न करने की रणनीति बनाते समय अपने कार्य के वातावरण में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर विचार करना पड़ सकता है। ■

अरियाने हनेमायर से पत्र व्यवहार हेतु पता <ahanemaa@ualberta.ca>  
और क्रिस्टोफर जे. श्नाइडर से पत्र व्यवहार हेतु पता <cschneider@wlu.ca>

# > नगर के अधिकार का पुनर्दावा : चिली में लोकप्रिय सक्रियकरण

सिमोन एसकोफेयर, आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यू. के.



फ्रांस के एक विला की दीवार, सेंटीयागो के विवादास्पद पड़ोस में से एक, निवासियों को 'जीत के लिए संघर्ष, संघर्ष के लिए संगठित होने' हेतु प्रेरित करती है।

फोटो : नथाली विलीगन

से प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि कभी-कभी यह अन्यों के तुलना में और ज्यादा व्यवस्थित रहा है। चिली के नगरीय गरीबों का आवास हेतु सामूहिक संघर्ष के इतिहास को 1920 के दशक से देखा जा सकता है। राजनीतिक दलों एवं अन्य अनेक सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़कर यह 'आवासीय आंदोलन' राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर एक केन्द्रीय भूमिका निभाता है और सरकार पर नगरीय भूमि अधिग्रहण द्वारा दबाव डालता है। 1957 से 1970 के मध्य भूमि के अधिग्रहण लोकप्रिय और इन्होंने चिली के नगरों विशेषतः सेंटीयागो को पुनः आकार प्रदान किया। वास्तव में सन् 1972 में एलेण्डे प्रशासन के दौरान, सेंटीयागो की आबादी का 16.6 प्रतिशत अनौपचारिक नगरीय बस्तियों में रहता था (सांटा मारिया, 1973 : 105)।

वामपंथी संगठनों के गृह क्षेत्रों के रूप में कई गरीब बस्तियों का सैन्य तानाशाही के दौरान (1973-1989) भारी दमन किया गया। इसमें से कुछ जमीनी स्तर पर प्रतिरोध का मुख्य केन्द्र बनी और 1983 के उपरांत एक राष्ट्रीय विरोध के रूप में इन बस्तियों ने निरंकुश शासन की क्रूरता को लोगों के सामने जाहिर किया।

1990 के उपरांत जब चिली में लोकतंत्र पुनः स्थापित हुआ तब अकादमिक साहित्य से इन गरीब लोगों के तीव्र एवं समन्वित कार्यक्रमों को हटा दिया गया। हालांकि

**स**ामाजिक सक्रियकरण के लम्बे इतिहास के बावजूद 1990 से चिली के नगरीय गरीबों को गैर-सक्रिय राजनीतिक कर्त्ताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है जो पृथक्करण एवं सामाजिक बीमारियों का सामना कर रहे हैं। सेंटीयागो में पैनालोलिन नगर में किये गये मेरे अनुसंधान के आधार पर मैं यह तर्क देना चाहूंगा कि कम से कम कुछ घटनाओं में नगरीय गरीब एक सतत प्रतिरोध को संगठित करने में सक्षम होते हैं और वे 'नगर का अधिकार' का पुनर्दावा करते हैं।

डेविड हार्वे (2008 : 23) नगर का अधिकार को परिभाषित करते हुए यह मत व्यक्त करते हैं कि 'नगर का अधिकार नगर के परिवर्तन के साथ अपने आपको परिवर्तित करने का अधिकार है। नगरीयकरण एवं पूंजीवाद को जोड़ते हुए लाभ के ऊपर व्यक्तियों को वरीयता दिये जाने की अकादमिक परम्परा के अनुरूप हार्वे यह सुझाव देते हैं कि मनुष्य नगरीयकरण की प्रक्रिया को पुनः स्वरूप देने की क्षमता रखता है क्योंकि वह सामूहिक शक्ति को प्रयुक्त करने में सक्षम है। गरीब आवासियों के लिए 'नगर का अधिकार' का अर्थ उनके नगरीय आवास का संरक्षण करना है और नगर में विभिन्न संसाधनों और सेवाओं को उनके लिए उपलब्ध कराना है। यह स्थिति उस नगरीय प्रक्रिया का प्रतिरोध करती है जहां पूंजीपति अधिशेष उत्पादन एवं लाभ की प्रक्रिया में संलग्न रहता है।

मुख्य विचारकों का यह मत है कि एक अनवरत एवं समान प्रकृति का सामूहिक सक्रियकरण चिली के नगरीय गरीबों ने 'नगर का अधिकार' का दावे को प्रभावी तरीके

अनेक अनुसंधान केन्द्रों जैसे चिली विश्वविद्यालय, पी यू सी, सी आई डी यू, एस यू आर, फ्लेक्सो, विकारिया डी ला सोलीडेरीडेड इत्यादि ने 1990 के दशक के माध्यम से लोकप्रिय सक्रियकरण की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया। 1990 के दशक में सामूहिक कृत्यों के स्थान पर वि-सक्रियकरण के अवयव को अकादमिक गतिविधि के केन्द्र में रखा गया। इसके अंतर्गत गरीब बस्तियों को आपराधिकता के अड्डे, अन्य सामाजिक बीमारियों एवं नशीले पदार्थों की तस्करी के केन्द्र के रूप में प्रस्तुत किया गया (हिपशेर, 1996; तिरोनी, 2003)।

पैनालोलिन, सेंटीयागो का पूर्वी जिला तथा चिली के विभिन्न नगरों में उभरे अनेक प्रयास ऐसे प्रति-उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो वि-सक्रियकरण के विमर्श को चुनौती देते हैं। वास्तव में पैनालोलिन में उभरे लोकप्रिय पड़ोस ने पिछले 25 वर्षों में एक व्यवस्थित रूप से विवादास्पद राजनीतिक प्रयासों को विकसित किया है जो न केवल उन आवासियों के अधिकार के दावों का प्रबंधन करते हैं बल्कि संबंधित जिला एवं आवासियों के निकट के परिवेश को प्रत्यक्ष आकार देते हैं।

बिना मकान वाले लोगों द्वारा बनायी गई समन्वय समितियों के द्वारा रहने के अधिकार की मांग की गई और जिले के पूर्वी क्षेत्र में बेशकीमती भूमि पर पैनालोलिन के विभिन्न क्षेत्रों से आये 900 गरीब परिवारों ने कब्जा कर लिया। 1992 की सर्दी में इन्होंने चिली के नवीन लोकतांत्रिक शासन में पहला भूमि अधिग्रहण किया और उसे एसपिरांजा एंडिना का नाम दिया। इन मजबूत सामुदायिक संगठनों ने राजनीतिक दलों एवं सरकार के मनोनयन को अस्वीकार किया तथा एसपिरांजा एंडिना ने प्रयास कर, यह प्रबंधन किया कि स्थानीय नगरीय बस्तियों में सामाजिक आवास की मांग को उठाया जाये और सामाजिक आवासीय नीतियों में विद्यमान इस प्रयास को कि गरीबों की परिधि पर जमीन का पुर्नआबंटन हो, का विरोध किया जाए। अनेक वर्षों के संघर्ष, आंदोलन एवं समझौतों के परिणामस्वरूप इन बेघरों को भूमि अधिकार प्राप्त हुआ। इनके पड़ोस को औपचारिक स्वीकृति मिली और उसी परिसर में मकान बनाने के लिए अनेक रियायतें दी गईं।

जुलाई 1999 में, नगरों की परिधि पर बाध्यतामूलक भेजे जाने की कोशिशों को अस्वीकृत कर दिया गया। बेघरों द्वारा निरन्तर की जा रही आवास की मांग ने पैनालोलिन में दूसरे भूमि अधिग्रहण की स्थितियां पैदा कर दी। 1990 के उपरांत चिली में स्पष्टतः यह सबसे बड़ा भूमि अधिग्रहण था जिसे 'टोमा डा पैनालोलिन' के नाम से जाना जाता है। इसमें 1800 से अधिक परिवार सम्मिलित थे। टोना ने शासन को बाध्य किया कि वे जिले के अन्दर ही सामाजिक आवास के लिए रियायतें (सब्सिडी) प्रदान करें। हालांकि बाद में टोमा का संगठन विभाजित हो गया जिसमें समझौता कर रहे एक हिस्से ने रेडीकल हिस्से का साथ देने से मना किया। 2006 तक पैनालोलिन में निर्मित मकानों में लगभग 900 परिवारों को पुनर्वास हुआ जबकि शेष अन्य लोगों को दूसरे जिलों में आबंटन दिया गया।

सामाजिक आवासों के लिए पैनालोलिन का संघर्ष आज भी जारी है। 2006 के उपरांत मूवमेंट ऑफ ड्वेलर्स इन द स्ट्रगल (MPL), जिले की एक जमीनी वामपंथी संगठन ने जो स्थानीय आवासीय समितियों के साथ समन्वय स्थापित कर सामाजिक आवास के अधिकार की मांग कर रहा है और आवासियों को उसी जिले में मकान दिये जाने हेतु प्रयासरत है।

पैनालोलिन में सामाजिक आवास के लिए होने वाला यह संघर्ष सभी बेघर लोगों को नगर में मुख्य-मुख्य अधिकार दिला पायेगा की दृष्टि से बहुत प्रभावी नहीं है और ना ही यह ऐसा कर सकता है।

2009 में आवासियों एवं जमीनी संगठनों से जुड़े लोग इस तथ्य के प्रति जागरूक हुए कि पैनालोलिन में एक नये मास्टर प्लान (नगरीय योजना) को क्रियान्वित किया जायेगा। भूमि कानूनों को बदलकर भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई। जिले में कार चालकों की सुविधा के लिए कार लेनस् (सड़के) नये तरीके से बनाई गईं। नई खुदरा दुकानें आकर्षक तरीके से निर्मित की गईं। इस नये मास्टर प्लान का उद्देश्य भूमि की कीमत में वृद्धि कर जिले का उन्नयन करना था। इसके अतिरिक्त मास्टर प्लान में जिले में सामाजिक आवास कार्यक्रम के लिए प्रचुर मात्रा में भूमि देने का प्रावधान नहीं रखा गया। जहां कुछ पड़ोसों को यह परिवर्तन उपयुक्त लगा परंतु अधिकांश जमीनी संगठनों ने इसे असमानता की प्रक्रिया बताकर अस्वीकृत कर दिया। वे संगठन जो इस नये मास्टर प्लान का विरोध कर रहे थे, ने मांग की कि प्रत्येक जिले में वैधानिक दृष्टि से जनमत संग्रह किया जाये। नगर परिषद एवं स्थानीय पड़ोस संगठनों ने विवादास्पद प्रचार किये, परंतु इसके बावजूद दिसंबर 2011 के अंत में लोकतांत्रिक तरीके से इस मास्टर प्लान को अस्वीकृत कर दिया गया। जिले को असमानता की प्रणाली से बचाने के लिए गरीब बेघर लोगों ने नगरीय बस्तियों को संरक्षण दिया विशेषतः उन बस्तियों को जिन्हें उन्होंने 1960 एवं 1970 के दशक में स्वयं बताया था।

पैनालोलिन के पूर्वी पड़ोस लोहरमिडा ने पिछले 25 वर्षों में एक विवादास्पद सक्रियकरण की मजबूत संस्कृति पैदा की है। सामूहिक क्रियाओं के आधार पर सामुदायिक मूल्यों एवं पहचान को स्थापित किया गया है। स्थानीय क्षेत्रों को पुनः सम्मिलित करने के लिए यह पड़ोस विभिन्न प्रकार के प्रयासों में संलग्न है जिसके कारण अनेक सामाजिक कर्त्ता इसका हिस्सा बन जाते हैं। उदाहरण के लिए निवासी संगीत की कार्यशाला या सामुदायिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पड़ोस के चौक में करते हैं जिसका स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से जुड़ता है। इस जुड़ाव के फलस्वरूप नशीले पदार्थ के तस्करों और निजी कंपनियों की धमकी प्रभावशाली तरीके से सामना किया जाता है।

सामूहिक क्रियाओं के ये विभिन्न कार्यक्रम पैनालोलिन के बाद अनेक क्षेत्रों में चिली के नगरीय गरीबों के द्वारा किये जा रहे हैं, ताकि नगर में अधिकारों को स्थापित किया जा सके (सुगरानयस, 2010)। यह संघर्ष दर्शाते हैं कि चिली का नगरीय गरीब आज भी सक्षम है और वह प्रभावशाली तरीके से लंबे समय तक चलने वाली सामूहिक सक्रियता को संचालित कर नगर के अधिकार की मांग को प्रभावी तरीके से रख सकता है। ■

सिमोन एसकोफेर से पत्र व्यवहार हेतु पता :  
<[simon.escoffier@sant.ox.ac.uk](mailto:simon.escoffier@sant.ox.ac.uk)>

<sup>1</sup> The movement by the Chilean urban poor between the 1920s and 1989 has been traditionally called "movimiento de pobladores" in Spanish. Although I use "pobladores" and "dwellers" interchangeably, this is not totally precise, for the word in Spanish has historically acquired a political meaning in Chile: it refers to urban poor residents who fight for their collective rights.

#### References

- Harvey, D. (2008) "The Right to the City." *New Left Review* 53: 23-40. Retrieved from <http://newleftreview.org/II/53/david-harvey-the-right-to-the-city>.
- Hipsler, P. (1996) "Democratization and the Decline of Urban Social Movements in Chile and Spain." *Comparative Politics* 28(3): 273-297.
- Santa María, I. (1973) "El desarrollo urbano mediante los 'asentamientos espontáneos': El caso de los 'campamentos' chilenos." *EURE* 3(7): 103-112.
- Sugranyes, A. (2010) "Villa Los Condores, Temuco, Chile Against Eviction and for The Right to the City," pp. 145-148 in A. Sugranyes and C. Mathivet (eds.) *Cities for All Proposals and Experiences towards the Right to the City*. Santiago de Chile: Habitat International Coalition (HIC).
- Tironi, M. (2003) "Nueva Pobreza Urbana, Vivienda y Capital Social en Santiago de Chile," 1985-2001. *Revista de Sociología*. Santiago: Predes Editores.

# > उरुग्वे में अवैध बस्तियाँ एवं राजनीति

मारिया जोस अल्बरेज रिवाडूला, यूनीवर्सिटी डेल रोजारियो, बोगोटा, कोलंबिया एवं आई एस ए की क्षेत्रीय एवं नगरीय विकास की अनुसंधान समिति की कार्यकारिणी सदस्य (RC 21)



मांटीवीडियो में एक अस्थायी अवैध बस्ती जो एक पूर्व नियोजित कब्जे के किनारे धीरे-धीरे विकसित हुई।  
फोटो : मारिया जोस अल्बरेज रिवाडूला

**20** वीं शताब्दी के आखिरी दो दशकों के दौरान मांटीवीडियो में आश्चर्य जनक परिवर्तन आये हैं। नव्य-उदारवाद एवं लोकतांत्रिकरण के समन्वय ने उरुग्वे के राजधानी शहर में असमानता एवं पृथक्करण में वृद्धि की है। सबसे महत्व पूर्ण दिखने वाला परिवर्तन जो कि एक बड़े बदलाव का महज हिस्सा है हमारे सम्मुख अनौपचारिक अवैध बस्तियाँ की वृद्धि के रूप में उपस्थित हुआ है।

मांटीवीडियो की अवैध बस्तियों में परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकृति के परिवर्तन हुए हैं। अवैध बस्तियाँ आश्चर्यजनक रूप में विस्तृत हुई है परंतु यह एक अंतर्विरोध है कि यह बस्तियाँ अधिकतर नियोजित थी। संरचनात्मक स्थितियों जैसे निरन्तर चलने वाला वि-औद्योगीकरण, निर्धनता, राज्य की नौकरियों में छंटनी, वास्तविक

पारिश्रमिक का कम होना एवं किराये में वृद्धि इन परिवर्तनों के पीछे के निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण कारण हैं। तथापि यह तस्वीर अपूर्ण है यदि हम आर्थिक परिवर्तनों एवं राजनीति का परीक्षण न करें। भूमि पर अतिक्रमण में वृद्धि को लोकतांत्रिकरण एवं चुनावी प्रतियोगिता के संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है।

जहां कई अवैध बस्तियों को एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जो कि कठिन हो रही आर्थिक स्थितियों का एक परिणाम है, मांटी-वीडियो का घटनाक्रम यह बताता है कि राजनीतिक नेटवर्क के रूप में संगठन का महत्व बढ़ा है। यह नेटवर्क राजनीतिक अवसरों जैसे चुनाव अथवा विक्रेन्दीयकरण को भी उत्तर देता है।

लैटिन अमेरिका में अवैध बस्तियों के निर्माण में राज्य एवं राजनीति की भूमिका ने लंबे समय से अध्ययन कर्त्ताओं का ध्यान

आकर्षित किया है क्योंकि अन्य देशों की तुलना में लैटिन अमेरिका में यह सम्बंध ज्यादा मजबूत है। हालांकि लैटिन अमेरिका में ही मांटीविडियों का प्रकरण अपने आप में विशिष्ट है। 1940 के दशक से भूमि पर कब्जा यहां पर होता चला गया। यह धीरे-धीरे हुआ जिसे यहां की भाषा में कैंटीग्रिल्स (Cantegriles) कहा जाता है। उरुग्वे की राजधानी में यह क्षमता थी कि वह औपचारिक आवासों के माध्यम से उन ग्रामीण अप्रवासियों को अपने में समायोजित कर सके जो राज्य केन्द्रित औद्योगीकरण के कारण इस नगर में आ रहे थे। 1980 तक नगरीय सामाजिक-आर्थिक असमानता की वृद्धि को दर्शाने वाले अनेक चेतवनी संकेतकों के बावजूद मांटीविडियो इन क्षेत्र के अन्य नगरों की तुलना में अब भी अधिक समतावादी था। यह समता आर्थिक एवं स्थानिक दोनों संदर्भों में थी।

लेकिन 1990 में इन अवैध बस्तियों का विस्तार शुरू हुआ और 1999 तक मांटीवीडियो में स्थापित अवैध बस्तियों में से आधी ऐसी थी जो 15 साल से भी कम पुरानी थी और इन नवीन अवैध बस्तियों का एक तिहाई भाग नियोजित अतिक्रमण से बना था। कम से कम प्रारम्भ में आवासीय अपनी मुख्य आवासीय आवश्यकताओं के अतिरिक्त कुछ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी चाहते थे। वामपंथियों के चरमपंथी समूहों में से यह आवासीय सामान्यतः आये थे। इनके नेताओं ने नियोजित तरीके से भूमि पर अतिक्रमण को भूमि सुधार का जमीनी प्रयास माना। यह अपने आपमें राज्य की आवासीय नीतियों की आलोचना का भी संकेत है। ऐसे लोग जो कम आदर्शवादी थे उन्होंने भूमि पर कब्जा किया और उसका मापन कर आवासीय भूखण्ड वितरित कर दिये और अपने साथियों को मकान बनाने में सहायत दी। सड़क एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए जमीन आबंटन कर दी गई और दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियमों की रचना कर उन्हें लागू कर दिया गया। इसके साथ ही सार्वजनिक सेवाओं, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र एवं पड़ोसी क्षेत्रों की वैधानिकता की मांगों को लेकर वे संगठित होने लगे। उरुग्वे में नगरीय गरीबों द्वारा इन अवैध बस्तियों की रचना संभवतः हाल की राजनीतिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्तिकरण है। पोर्ट्स एवं वाल्टन ने अपनी पुस्तक 'अरबन लैटिन अमेरिका' में इन सभी पक्षों की तथा पिछले 30 एवं 40 वर्षों से चल रहे प्रयासों की व्यापक रूप में चर्चा की है।

इस बदलाव के पीछे के क्या कारण हैं? यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मोण्टीवीडियों ने वास्तविक जनसंख्या वृद्धि का सामना नहीं किया। ग्रामीण अप्रवासी सामान्यतः अन्य स्थानों की अनौपचारिक आवासीय, बस्तियों में बस कर जनसंख्या वृद्धि में योगदान करते हैं, वे इस नगर में ऐसा नहीं करते। मांटीवीडियो में अनेक आवासीय बस्तियाँ स्थापित नगरीय पड़ोसों में उभरीं। वे वहां से अन्यत्र जाने को बाध्य हुए जब उन्होंने नवीन परिवारों का निर्माण किया या वि-औद्योगीकरण से उत्पन्न चिन्ताजनक रोजगार स्थितियों ने उन्हें बाध्य किया। अनेक लोग किराया अधिक होने के कारण छोड़ कर चले गये।

तथापि केवल आर्थिक कारण इस स्थिति की विवेचना नहीं कर सकते कि क्यों कुछ समूह एवं जरूरतमंद परिवारों ने किसी विशिष्ट क्षण पर स्थापित होने की सोची और अन्य क्षणों में निराशाजनक नहीं। जैसे 2002 का आर्थिक संकट राजनीति विशेषतः चुनावी राजनीति ने मांटीविडियों के नवीन पड़ोसी क्षेत्रों विशेषतः नियोजित क्षेत्रों के उदभव एवं उनकी एकजुटता को प्रभावित किया। उरुग्वे में तानाशाही की समाप्ति एवं 'Frente Amplio' (वृहद् गठबंधन) के रूप में वामपंथी ताकतों का तीसरी शक्ति के रूप में उभार ने यह स्थितियाँ उत्पन्न की। इस ताकत ने चुनाव में जीत के दावे किये और अन्ततः 1990 में मांटीवीडियो की नगर परिषद में विजय प्राप्त की। इसके साथ ही नगर में चुनावी प्रतियोगिता की स्थितियों को विस्तार दिया और सभी राजनीतिक दलों को इसके लिए प्रेरित किया

कि वे भूमि अतिक्रमण के प्रति सहनशीलता का रवैया अपनाएं और नये भूमि अतिक्रमण को प्रेरित करें।

1990 के आस-पास संगठित अवैध बस्तियों के अधिकांश नेताओं ने विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनीतिज्ञों से अपने सम्बंध बनाये। हालांकि अधिकांश ने स्वयं के लिए 'हम अ-राजनीतिक हैं' का दावा किया, वास्तव में वे 'हाइपर राजनीतिक' थे। अतीत में सामुदायिक नेता कोला रेडो पार्टी की तरफ आकर्षित हुए हों ताकि सड़कों की मरम्मत हो सके, क्योंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग का मंत्री कोलारेडो पार्टी से सम्बंधित था। इसके साथ ही वे फ्रंटि एम्प्लियो (Frente Amplio) के निर्वाचित प्रतिनिधियों से भी संबंध बनाए रखेंगे ताकि बस्ती बसाने के लिए उपलब्ध जमीन की जानकारी मिल सके। उन्होंने ब्लानको को पार्टी से भी अच्छे सम्बंध बनाये क्योंकि इस दल से सम्बंधित उप-नगर प्रमुख आवासीय बस्तियों का दौरा करते थे।

जल्दी ही सभी नगरों के सक्रिय कार्यकर्ताओं को यह अहसास होने लगा कि आवास की जरूरत रखने वाले परिवारों की समस्या का समाधान करने के लिए किसी राजनीतिक दल को मत देना एक तरीका हो सकता है परंतु भविष्य में इससे बड़ी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। इन आवासीय बस्तियों में जीवन जीने की स्थितियाँ चिन्ताजनक है और सेवा प्रावधानों पर व्यय में वृद्धि हो रही है। पूर्व के औपचारिक पड़ोस क्षेत्रों में मकानों पर किये गये कब्जों के समय सार्वजनिक सुविधाएं पूर्ण रूपेण विद्यमान थी पर इन नयी बस्तियों में ऐसा नहीं है। नगर परिषद के अधिकारी एवं राजनीतिज्ञ इन समस्याओं से परिचित थे और वे जानते थे कि भूमि अतिक्रमण सन् 2002 की आर्थिक विपत्ति के दौरान क्यों नहीं अधिक हुआ और क्यों निवर्तमान अध्यक्ष मुजीका, जो कि सामान्यतः लोकप्रिय समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते थे, को सन् 2011 में भूमि पर कब्जा करने के लिए निजी रूप में हस्तक्षेप करना पड़ा। भूमि खाली कराने के इस प्रयास को काफी प्रचारित किया गया था। इसके अतिरिक्त नगरीय गरीबों में मत देने के प्रति चुनावी प्रतियोगिता लगभग खत्म हो गई जब सन् 2009 में दूसरी बार वामपंथियों ने राष्ट्रीय सरकार का गठन किया।

हालांकि, मांटीवीडियों में भूमि अतिक्रमण की लहर सापेक्षिक रूप से अल्प कालिक रही, परंतु इसने नगरीय एवं सामाजिक जीवन में स्थायी परिणामों को उत्पन्न किया। देश के वर्तमान आर्थिक उन्नयन की स्थिति में भी इन अवैध बस्तियों में (Asentamientos) सेवाओं की उपलब्धता कम है और ये अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का अनुभव करती हैं। गंदी बस्तियों के उन्नयन के कार्यक्रम का विस्तार कई नवीन पड़ोसों में हुआ है, तथापि आधारभूत संरचनाओं के विस्तार की भी एक सीमा है। 20 अथवा 25 सालों में जो कुछ हुआ है उसे जल्दी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बच्चों की एक पूरी पीढ़ी उस विषम स्थितियों में बड़ी हुयी है और विभिन्न प्रकार की गरीबी से उन्हें आज भी अस्मिताओं का सामना करना पड़ता है। नगर के निवासी इन पीढ़ियों को जो कि अवैध बस्तियों में रही है, रेड जॉस के निवासियों की पहचान से जोड़ते हैं।

तथापि अनेक प्रयास किये गये हैं। विशेषतः वंचित क्षेत्रों में सुविकसित सार्वजनिक पार्कों का निर्माण किया गया है जो कि अवैध बस्तियों के निकट हैं। नवीन आवासीय कार्यक्रमों को लागू किया गया है। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में निजी ठेकेदारों द्वारा सामाजिक आवासों का निर्माण किये जाने पर करो की रियायत/सब्सिडी के रूप में सुविधाएं दी गई हैं या प्रोत्साहन दिये गये हैं। आवासीय सहकार समितियों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है परंतु इन सभी के बावजूद अवैध बस्तियों एवं उनके निवासियों का प्रभावी समावेशीकरण करना मांटीवीडियो के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ■

मारिया जोस अल्वरेज रिवाडूला से पत्र व्यवहार हेतु पता :  
<[majo.alvarez.rivadulla@gmail.com](mailto:majo.alvarez.rivadulla@gmail.com)>

# > ब्राजील के बेघर श्रमिकों के आंदोलन का विकास

सिबेली रिजेक एवं आंद्रे डल'बो, साओ पाउलो विश्वद्यालय, ब्राजील



साओ पाउलो के व्यापारिक क्षेत्र, पॉलिस्ता मार्ग पर, एम टी एस टी द्वारा 'अधिक लोकप्रिय सुधार, अधिक अधिक की मांग हेतु प्रदर्शन।

**ब्रा**जील का बेघर श्रमिक आंदोलन (MTST) 1990 के दशक के उत्तरार्द्ध में, श्रमिकों, मजदूरों, अनौपचारिक अर्द्ध रोजगारों तथा बेरोजगारों को एकजुट करने के उद्देश्य से प्रारम्भ हुआ था। इनके पास लाखों ब्राजीलवासियों की तरह समुचित आवास नहीं थे तथा जो मुख्यतः ब्राजील की नगरीय परिधि में किराये के घरों में, जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में अथवा नगरीय असुरक्षा की स्थितियों में निवास करते थे। ब्राजील की नगरीय राजनीति में एक ऊर्जावान नेतृत्व के रूप में एम.टी.एस.टी. ने सड़कों पर अनेक प्रदर्शन आयोजित किये जिसने पिछले वर्ष ब्राजील समाज को उत्तेजित किया तथा अपनी संगठनात्मक गतिशीलता के माध्यम से

देश की राजनीतिक बहस को देखने का एक अनोखा प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

आवश्यक रूप से यह आंदोलन 1980 के दशक में उभरे आवासीय आंदोलन से महत्वपूर्ण रूप से अलग था। तत्कालीन आंदोलन पार्टीदो डॉस ट्राबल्हाडोर्स (पीटी) की अध्यक्षता में बनी संघीय सरकार के साथ गठबंधन में है। यद्यपि एम टी एस टी प्रारम्भ में भूमिहीन आंदोलन (एम टी एस टी-मूलतः कृषक प्रधान प्रवेश आंदोलन) से सम्बद्ध था, बेघर श्रमिक आंदोलन की स्थापना 1997 में राष्ट्रीय जन प्रदर्शन के दौरान हुई थी, जब भूमिहीन आंदोलन के कार्यकर्त्ता ओजिल पार्क साओ पाउलो राज्य में कैपीनास के नगरीय

कब्जे में जुटे थे। एम टी एस टी का पहला कब्जा अनीता गरीबाल्दी द्वारा गुआरूलॉस में 5 साल बाद संगठित किया गया।

उस प्रथम कब्जे के बाद, एम टी एस टी ने साओ पाउलो व कैपीनास के महानगरीय क्षेत्रों में कम से कम 10 प्रमुख कब्जे किये जिनमें चिको मेंडेस (टेबू दा सेरा, 2005), जोआओ कैनडीडो (इदा-पीसीरिका दा सेरा, 2007), फ्री टीटो (कैपीनास, 2007), जीसस सिलवेरिया (इम्बू दास अर्टेस, 2008), जूम्बी दोस पालमेरस (सुमेर, 2008), दानदारा (होरटो-लेडिया एंड सांटो एंज़े, 2011) तथा नोवोस पिनहेरीनहोस (सांटो एंज़े एवं इम्बू दास अर्टेस, 2012) छावनियों सम्मिलित हैं।

जून 2013 में, ब्राजील ने लोकप्रिय सड़क प्रदर्शन की एक तीव्र प्रक्रिया को अनुभव किया, जो नव उदारवादी नीति के बदलावों से सम्बंधित लोकप्रिय सैन्य विघटन की लंबी अवधि के अंत को चिन्हित करता है। एम टी एस टी का तेजी से सक्रिय होना, निजी विकास कर्त्ताओं (डेवलपर) के साथ, अचल संपत्ति बाजार व राज्य के साथ लगभग रोज संघर्ष होना महज संयोग नहीं था। अक्सर सड़क प्रदर्शनों के अतिरिक्त, जून 2013 तथा 2014 के बीच एम टी एस टी ने साओ पाउलो तथा दूसरे महानगरीय क्षेत्रों में घातक तरीके से परित्यक्त तथा बेकार भूमि व भवनों के कब्जों को प्रेरित किया, पिछले 12 महीनों में समूचे ब्राजील में 100 से अधिक कार्यवाही की गई। ब्राजील बढ़ती आवास की कमी से पीड़ित है, 2011 और 2012 के बीच महानगरीय क्षेत्रों में यह कमी 10 प्रतिशत तक बढ़ी है। ब्राजील के हजारों परिवारों को भूमि, अचल संपत्ति तथा किरायों में प्रतिदिन होने वाली बेतहाशा वृद्धि ने उन्हें अपने घरों से बेदखल कर दिया, जो कि अचल सम्पत्ति बाजार में तेजी के वर्तमान चक्र की विशेषताएं हैं। यह आवासीय कमी ब्राजील की सरकार द्वारा देश के इतिहास में सबसे बड़ा सार्वजनिक आवासीय कार्यक्रम लागू करने के बावजूद उत्पन्न हुई। दूसरे सामाजिक कार्यक्रमों के साथ, 'मेरा घर मेरा जीवन' (एम सी एम वी, जिसका अर्थ है 'मिन्हा कासा मिन्हा वादा') नामक कार्यक्रम ने रोजगार निर्माण को बढ़ावा देकर आर्थिक वृद्धि में योगदान किया तथा ऐसे उपभोग और सेवाओं को लोगों तक पहुंचाया जो पूर्व में उच्च आय वर्गों तक सीमित थे।

हालांकि, विडम्बना यह है कि सामाजिक आवास कार्यक्रम में भी नगरीय पृथक्करण तथा बहिष्करण को मजबूती दी है, ना ही यह निर्धन ब्राजीलवासियों को केन्द्रीय शहरी क्षेत्रों में स्थायी रूप से बसने में मदद कर रहा है और ना ही विस्तार ले रही नगरीय परिधि में बसे नये निवासियों को दैनिक जीवन की आवश्यक सुविधाएं और सेवाएं प्रदान कर रहा है।

इस संदर्भ में, बेघर श्रमिक आंदोलन के विरोध ने ब्राजील की शहरी नीति को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। हालांकि, सरकार के सामाजिक आवासीय कार्यक्रम के साथ इस आंदोलन के बढ़ते सम्बंधों ने कुछ स्थितियों को जटिल बनाया है। इस आंदोलन में कब्जों को लेकर होने वाले समझौतों से सम्बंधित पक्षों ने सरकारी नीति के आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्रों में बहस को जन्म दिया है।

कब्जे के इस आंदोलन के परिणामों में इस अस्पष्टता को साफ-साफ देखा जा सकता है। जैसे ही एम टी एस टी नगरीय निकाय के साथ कब्जे के सवाल को लेकर समझौते की प्रक्रिया अपनाती है, नगर की शासक शक्तियों को यह कहा जाता है कि वे कब्जा की गई भूमि को खाली/बेदखल करने की प्रक्रिया अपनाय या इस पर विधि प्रक्रिया अपनाएं और इसके साथ ही तत्काल सरकार के आवासीय कार्यक्रम ने कब्जा कर चुके परिवारों का समावेश करने का एम टी एस टी आह्वान करती है। लेकिन नवीन सामाजिक आवासों ने स्थानिक पृथक्करण को बढ़ाया है क्योंकि गरीबों के लिए नये मकान नगरीय परिधि पर अनिवार्यतः निर्मित किये जाते हैं। इसके कारण स्थानिक असमानता में और वृद्धि होती जाती है।

एम टी एस टी इस कारण अपने आपको एक असमंजस की स्थिति में पाती है। जैसे ही सक्रिय कार्यकर्त्ता आवासीय कार्यक्रम, जो कि भवन निर्माण बाजार के द्वारा एक सार्वजनिक नीति के रूप में क्रियान्वित किया जाता है, सड़कों पर अधिकार सम्बंधी प्रदर्शन को जन्म देता है। इस प्रदर्शन में कब्जा, गिरफ्तारी और यहां तक हत्या जैसी हिंसक गतिविधियां भी सामने उभरती हैं। अतः बेघर आंदोलन ब्राजील के नगरों में एक गैर-न्यायिक एवं असमान चरित्र को उत्पन्न करता है जबकि इसे ब्राजील की सामाजिक नीतियों का एक छिपा हिस्सा होना चाहिए था। इस आंदोलन ने सामाजिक कार्यक्रमों में परिवर्तन की आंशिक स्थितियों को जन्म दिया है परंतु इसके कारण 12 साल तक श्रमिक पार्टी के आधिपत्य के बावजूद संघर्ष एवं राजनीतिक खींचातानी की उपस्थिति देखी जा सकती है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ब्राजील के सामाजिक संघर्ष के महत्वपूर्ण कर्त्ता इस आंदोलन को ब्राजील की निर्धन नगरीय जनसंख्या के लिए एक न्यायसंगत एवं समतावादी भविष्य के रूप में देखते हैं। ■

सिबेली रिजेक से पत्र व्यवहार हेतु पता :  
<cibelesr@uol.com.br>

# > दक्षिण अफ्रीका में गरीब लोगों का विरोध प्रदर्शन

प्रिशानी नायडू, बिटवाटारसैंड विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका



सोवेटो में ओरलैंडो निवासियों द्वारा 2010 के विश्वकप से पहले निर्माण परियोजनाओं में से उनके समुदाय को बहिष्कृत करने का विरोध।  
फोटो : निकोलस डायलटीनस

दक्षिण अफ्रीका के प्रथम 20 वर्षों की गैर-नस्लीय चुनावी लोकतंत्र की प्रभावी कहानी इस अवधि में उत्पन्न और सक्रिय हुई औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं, खिलाड़ियों, नीतियों तथा प्रक्रियाओं की सफलता पर बल देती है। तथापि, विरोध के रूप में संभवतः सबसे मुखर, निरन्तर अनौपचारिक हस्तक्षेप की यह पहली घटना थी जो किसी राजनीतिक दल, संगठन या श्रमिक संघ के बाहर गरीब लोगों के मध्य उभरी जिसके कारण वे अपने प्रतिदिन के जीवन में सामना कर रही समान समस्याओं के कारण एकजुट हो गये थे।

इसमें विशेष महत्व उन अनौपचारिक आवासीय परिसरों एवं कस्बों में रहने वाले उन लोगों के संघर्ष से सम्बद्ध है जिन्हें एक 'स्थायी अनौपचारिकता' के साथ जीवन जीने की स्थितियों का हिस्सा उन लोगों ने बनाया है जो कि नस्ल विरोधी योजनाकर्त्ता हैं। इस स्थिति का सम्बंध आवश्यक रूप

से अश्वेत लोगों को अधीनस्थ स्थिति में रखना और 'परेशानी से अलग' रखने के रूप में सोचा गया था। यह सब स्थितियां अश्वेत लोगों के द्वारा अवैध बस्तियां बनाये जाने के परिणामस्वरूप नगरों में उत्पन्न हुई। नस्ल-भेद वाला राज्य अनेक वर्षों से ऐसी नीतियां बनाने की कोशिश में था जिससे अश्वेत लोगों (जिन्हें सस्ते श्रम के रूप में कल्पना का हिस्सा बनाया गया था) के आंदोलन को नियंत्रित किया जा सके। 'अनौपचारिक कस्बा' अथवा आवासीय बस्तियों का निर्माण इसका भाग था परंतु ये ऐसे क्षेत्र बने जहां से नस्लभेद के विरुद्ध संघर्ष शुरू हुआ और एक ऐसे जीवन की कल्पना उभरने लगी जो कि नस्लभेद के उपरांत की स्थितियों को दर्शाती थी।

नस्लभेदी संस्थाओं एवं नीतियों के औपचारिक स्वरूप की समाप्ति के 20 वर्ष के बाद, दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ी संख्या में गरीबों का जीवन आज अनौपचारिकता

की निरन्तरता का प्रदर्शन करता है। वे ऐसी आवासीय बस्तियों में रहते हैं (और जिनमें वृद्धि हो रही है) जहां नस्लभेदी प्रकृति की जीवन स्थितियां विद्यमान हैं। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि 1990 के दशक के अंत से प्रत्येक सर्दी के मौसम में (जो लगभग पूरे साल देखा जा सकता है) गरीब निवासी जो कि अनौपचारिक अवैध बस्तियों और कस्बों में रहते हैं, स्थानीय सड़कों एवं राजमार्गों पर प्रदर्शन करते हैं ताकि उन्हें जीवन के उपयुक्त स्तर एवं गुणवत्तामूलक जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त हों। इसमें पानी, बिजली एवं उपयुक्त आवास (मूलभूत सेवाओं के साथ) सम्मिलित है। धीरे धीरे यह दक्षिण अफ्रीकी जीवन का एक सामान्य अवयव बन गया है जो एक छोटे रूप में सन् 2000 से शुरू हुआ और सन् 2004 से इसका आकार बड़ा हो रहा है।

1997 से देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग तरीके से ऐसी घटनाएं प्रकाश

>>



में आयी जिसमें विरोध कर रहे गरीब आवासियों के घरों की पानी एवं बिजली की सुविधाएं काट दी गई थी। आने वाले तीन वर्षों में इस प्रकार के समाचार सामान्य हो गये और गरीब समुदायों ने यह समझ लिया कि निजीकरण के विभिन्न स्वरूपों को लागू किया गया है जिससे रोजगार हीनता और श्रम के लचीलेकरण का रूप सामने आया है। 1996 में ए एन सी (ANC) की सरकार ने नव उदारवादी वृहद् आर्थिक नीतियों के जिस प्रारूप को स्वीकारा यह उसका परिणाम था। पानी एवं बिजली में कटौती तथा नगर परिषदों ने घर से बेदखली में वृद्धि होने लगी जैसे ही मूलभूत सुविधाओं के लिए चुकौती के तर्क को लागू किया। प्रभावित निवासी एकजुट हो कर अपने ऊपर लादी जाने वाली शर्तों को अस्वीकार करने लगे। यह स्थिति विरोध के अनेक स्वरूपों में बदल गई (जैसे प्रदर्शन, धरना, अधिकारियों को कार्यस्थलों में प्रवेश से रोकना, कार्यालयी सम्पत्ति की तोड़-फोड़ तथा पानी एवं बिजली की आपूर्ति के लिए अवैध कनेक्शन)। इन संघर्षों में अनेक स्वतंत्र सक्रिय कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया जो एक सामान्य शत्रु की पहचान करना प्रारम्भ कर रहे थे। संघर्ष भले ही भिन्न-भिन्न एवं पृथक थे पर 'नव्य-उदारवाद' एक समान शत्रु था।

सन् 2001 तक अनवरत क्रिया कलापों एवं विभिन्न आलोचकों के समूहों की सहभागिता ने ऐसी स्थिति को जन्म दिया जिसे 'नवीन सामाजिक एवं सामुदायिक आंदोलनों' होने का दावा किया जा सकता है। इस प्रकार के आंदोलन पहली बार 1994 के बाद ही उभरे थे जिन्होंने अपने आपको ए एन सी से अलग रखा था (साथ ही इनकी स्थिति विपरीत प्रकृति की थी)। इसके अतिरिक्त व्यापक कांग्रेस आंदोलन से भी यह अलग थे। सन् 2002 में समाजशास्त्री अश्विन देसाई की एक प्रभावशाली पुस्तक 'वी आर द पुअर्स' का प्रकाशन हुआ जिसमें उन्होंने 'गरीब' (द पुअर्स) को एक नया राजनीतिक विषय बताया जिसका जन्म ए एन सी (ANC) सरकार के द्वारा नव्य-उदारवादी नीतियों को स्वीकारने से उत्पन्न विभिन्न प्रभावों के विरुद्ध उस सामुदायिक संघर्ष से हुआ है जिसमें अनेक श्रेणियों सम्मिलित हैं (जैसे विद्यार्थी, शिक्षाविद् अनुसंधानकर्ता एवं अन्य स्वतंत्र सक्रिय कार्यकर्ता)।

सन् 2004 तक ऐसे अनेक आंदोलनों को ह्रास के दौर से गुजरना पड़ा। राज्य का दमन, आंतर संगठनात्मक राजनीतिक उठा-पटक एवं संसाधनों की उपलब्धता में उत्पन्न कठिनाईयों के सम्बन्धित प्रभाव

से ऐसा हुआ और इसके कारण सदस्यों के अन्दर (जिसमें बेरोजगार एवं गरीबों का बहुमत था) की ऊर्जा एवं प्रतिबद्धता में सामूहिक स्तर पर कमी आयी। अनेक प्रकरणों में आंदोलनों से उत्पन्न मांगों को राज्य ने न केवल अस्वीकारा अपितु उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया। पर यह एक विसंगति है कि सन् 2004 ही एक ऐसा वर्ष है जब बड़े पैमाने पर संघर्ष उभरे। यह लगभग उसी तरह के थे जो सन् 2000 के प्रारम्भ में नवीन आंदोलनों के रूप में लोकप्रियता प्राप्त कर चुके थे। एक बार फिर राजनीति के अनौपचारिक परिवेश ने हस्तक्षेप किया क्योंकि पहले के संघर्षों से मिलने वाले औपचारिक प्रत्युत्तर असफल हो चुके थे क्योंकि वे सबकी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे।

वास्तव में किसी भी औपचारिक सामाजिक संरचना के बाहर स्थानीय स्तर पर सन् 2004 से गरीबों के प्रतिरोध एवं संघर्ष इस तरह से व्यापक हुए हैं कि समाजशास्त्री पीटर अलेक्जेंडर इस स्थिति को 'गरीबों के विद्रोह' (rebellion of the poor) की संज्ञा देते हैं। मुख्य धारा के मीडिया ने इन प्रदर्शनों, संघर्षों एवं विरोधों को दिखाया और 'सेवा प्राप्ति हेतु विरोध' (सर्विस डिलीवरी प्रोटेस्ट) के रूप में इनहें लोकप्रिय बनाया। इन सभी क्रिया कलापों का यह छोटा नाम लोकप्रिय हो गया। हालांकि सेवा प्रदान करने की प्रणाली का अव्यवस्थित होना ऐसे अनेक आंदोलनों एवं विरोधों का कर्णधार हमेशा से मुख्य बिंदु रहा है (इसमें मुख्य सेवाओं के साथ-साथ आधारभूत संरचना की उपलब्धता के पक्ष भी सम्मिलित हैं)। इसके साथ ही, भ्रष्ट नगर प्रतिनिधि सामान्य निधि एवं सम्पत्ति का कुप्रबंधन तथा नगर परिषद एवं आवासियों के बीच अपूर्ण संचार इन विरोधों एवं आंदोलनों के अन्य प्रेरक तत्व थे। सन् 2012 तक ऐसी स्थिति हो गई थी, प्रतिदिन कम से कम एक विरोध आंदोलन सामने आने लगा।

अनेक स्थितियों में यह देखा गया है कि अधिकारियों के तंत्र के साथ बातचीत की असफलताएं आवासियों को विरोध अथवा आंदोलन के लिए प्रेरित करती हैं। या फिर यह स्थिति नगर परिषद द्वारा प्रत्युत्तर न दिये जाने से उत्पन्न होती है। सन् 2011 में कार्ल वॉन होल्ट इत्यादि ने एक पुस्तक 'द स्मोक दैट कॉलस्' का प्रकाशन किया जो कई एकल अध्ययनों का संग्रह थी। इनके अनुसार प्रदर्शनकर्ता कहते हैं कि कभी कभी सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक सम्पत्ति को जलाना है और टायर जलाकर अवरोध

उत्पन्न करना ही एकमात्र तरीका है। (इसे द स्मोक दैट कॉलस् कहा जाता है)। इस प्रकार की क्रियाओं की लगातार वृद्धि के परिणामस्वरूप मीडिया ने ऐसी घटनाओं को 'हिंसक सेवा उपलब्धता विरोध' (वायलेंट सर्विस डिलीवरी प्रोटेस्ट) की संज्ञा दी। इन विरोधी आंदोलनों से निबटने में पुलिस की कार्यवाही भी हिंसक हो गयी। समाचार पत्रों के अनुसार सन् 2009 से पुलिस कार्यवाही में कम से कम 43 आंदोलनकर्ता मारे गये।

आज ये विरोधी आंदोलनों का सम्बंध ए एन सी (ANC) की स्थानीय संरचनाओं और उनके सहयोगी संगठनों में उभरे विभेदों से भी है। यह पाया जाने लगा है कि नगरपरिषद में निर्वाचित नेतृत्व के विरुद्ध ए एन सी के सदस्य आंदोलन करने लगे हैं। ये निर्वाचित सदस्य भी ए. एन. सी. के हैं। इसलिए यह सामूहिक सक्रियता उभरते भेद की द्योतक है। कई बार इसका परिणाम राजनीतिक दल अथवा राज्य के अन्दर हार एवं असफलता के रूप में भी उभरता है। ऐसे प्रश्न उठाये जाते हैं जिनसे राज्य के संरक्षण के स्वरूप का पर्दाफाश हो सके और धनवान बनने की नेताओं की कोशिशों (टेंडर, नौकरी, फंडिंग) को सामने लाया जा सके या नेताओं के सहयोग से/ गठजोड़ से कार्यकर्ता लाभ ग्रहण कर सके। ए एन सी में होने वाले विभाजन अब नयी बात नहीं है। यह देखना रूचिकर होगा कि नये राजनीतिक खिलाड़ी जैसे 'इकॉनॉमिक फ्रीडम फाईटर्स' (EFF) एवं यूनाइटेड फ्रंट (जिसे धातु कर्मियों की राष्ट्रीय यूनियन, अन्य समुदायों एवं नागरिकीय समाजों ने मिल जुलकर बनाया है) गरीबों के स्थानियों संघर्षों के विषय में क्या दृष्टि अपनाते हैं।

हालांकि राजनीतिक खिलाड़ी औपचारिक राजनीति के अंतर्गत अपने दृष्टिकोण एवं ध्यान की रचना करते हैं (औपचारिक राजनीति का अभिप्राय राजनीतिक दलों एवं संसद से है)। परंतु स्थानीय स्तरों पर जारी संघर्ष आज भी अनौपचारिक परिवेश से मुख्यतः जुड़ा है। यह अनौपचारिक परिवेश वह संभावित क्षेत्र है जो समस्या-समाधान एवं सकारात्मक कार्यवाहियों के विकल्प उत्पन्न करता है। बहुत कुछ किया जा सकता है पर यह सब इस पर निर्भर है कि राजनीति को एक भिन्न कल्पना दृष्टि से देखा जाये, उसके प्रति प्रतिबद्धता हो और सामूहिकता में उसे आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति हो। ■

प्रिशानी नायडू से पत्र व्यवहार हेतु पता : [Prishani.Naidoo@wits.ac.za](mailto:Prishani.Naidoo@wits.ac.za)

# > जाम्बिया : सामाजिक आंदोलनों के बिना बेदखली

सिंगुम्बे मुयेबा, केप टाउन विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका



भूमि से बेदखल निवासियों द्वारा विकल्पों पर चर्चा करते हुए, जाम्बिया राष्ट्रीय सेवा सैनिकों के द्वारा चिनिका, लुसाका के ढहाये गये मकानों में से एक मकान के मलबे के ऊपर खड़ा एक बच्चा।  
फोटो : इम्मानुएल टेम्बो

अप्रैल 2013 में पश्चिमी लुसाका के भूखंड क्रमांक 10,144 में 15 सैन्य वाहनों एवं पुलिस कर्मियों ने जबरदस्ती प्रवेश किया। जो लोग वहां रह रहे थे उन्हें यह संदेह भी नहीं था परंतु भूमि खाली करने का डर उन्हें लगने लगा था। वे देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें हथियारों के द्वारा धमकाया जा रहा था। पुलिस ने 33 मकानों को ढहा दिया (गिरा दिया) और उस भूमि पर पिछले 20 वर्षों से रह रहे लगभग 365 लोग बेघर हो गए। बेघर होने वालों में कुछ निम्न क्रम के पुलिस अधिकारी भी थे। जगह खाली करने का कोई

चेतावनी पत्र पहले जारी नहीं किया गया था। लुसाका सिटी कौंसिल एवं न्यायालय से जुड़े जमानत सम्बंधी कर्मी वहां उपस्थित नहीं थे। जमीन से बेदखल करने के उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने स्वयं उस जमीन पर कब्जा कर लिया। उस महीने में अनेक जगहों पर इसी तरह से मकान तोड़े गये और जमीनें खाली करायीं गयीं। इस सबसे परेशान होकर 15 मई को बेघर परिवारों ने उप-राष्ट्रपति के कार्यालय के सामने एकजुट हो कर मार्च किया लेकिन उन्हें रोक दिया गया और सशस्त्र पुलिस ने उन्हें तितर-बितर कर दिया। सार्वजनिक व्यवस्था अधिनियम

(पब्लिक ऑर्डर अधिनियम) के अंतर्गत उनके पास इस प्रदर्शन के लिए पुलिस आज्ञा-पत्र नहीं था। बेघर लोगों के पास स्वयं की तरफ मुड़ने के अलावा कोई नहीं था। इस तरह की सक्रियता एक ऐसे आंदोलन को प्रारम्भ करने के लिए पर्याप्त नहीं थी जिससे भूमि खाली कराने के ऐसे प्रयासों को रोका जा सके और क्यों विद्यमान आवासीय सामाजिक आंदोलन इन बेघर लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सका? मैं यहां पर ऐसे ही कुछ प्रश्नों से सम्भावित उत्तर प्रस्तुत करूंगा।

लुसाका पश्चिम का यह प्रकरण अनेक प्रकरणों में से एक है। बिना किसी

>>

उत्साहमूलक संगठित क्रिया के सैंकड़ों ग्रहस्थियों को उजाड़ दिया गया। केवल सन् 2014 में लुसाका में भूमि खाली कराने की अनेक घटनाएँ हुईं। 25 जुलाई को कान्यामा में 14 मकानों को गिरा दिया गया। 3 अक्टूबर को चिनिका में 100 मकान गिरा दिये गये तथा 18 नवम्बर को मिकांगु बैरक (छावनी) में सैनिकों ने गांव को जबरदस्ती खाली करवा लिया। सन् 2007 में जाम्बिया सरकार के द्वारा प्रकटित नीति के उपरांत सार्वजनिक एवं निजी भूमि पर बने अवैध मकानों को गिराने का काम उभार लेता है। सन् 2011 में सत्ता में आने के बाद पैट्रियॉटिक फ्रंट की सरकार ने अवैध मकान को गिराने का काम जारी रखा। इसके साथ ही पूर्व सरकार की नीति के हिस्से के रूप में कुछ उन्नत परंतु अवैध आवासीय परियोजनाओं जिन्हें कि इस नीति के अंतर्गत स्वीकार किया गया था, को भी गिराना प्रारम्भ किया गया। गिराने के इस प्रक्रिया में वैधानिक कार्य प्रणाली का अनुकरण नहीं किया गया है। कुछ प्रकरणों में तो इन मकानों को गिराना काफी घातक सिद्ध हुआ है। इसके कारण जनता के मध्य जागरूकता उभरी है।

यह स्थितियाँ सामाजिक सक्रियकरण का आधार बनती हैं। नगरीय जनसंख्या का 70 प्रतिशत गंदी बस्तियों में रहता है, इसका मतलब यह है कि नगरीय जनसंख्या का हिस्सा बनी अवैध बस्तियां अत्यंत जटिल स्थिति में पहुँच जाती हैं और इसके कारण देश में विरोध एवं सामूहिक सक्रियताओं का लिपिबद्ध इतिहास मजबूती प्राप्त करता जाता है।

विरोध के अभाव का विश्लेषण कैसे किया जाये? पहला कारण यह है कि सन् 1955 में पब्लिक आर्डर अधिनियम (सार्वजनिक व्यवस्था अधिनियम) के आने के उपरांत राजनीतिक अभिजनों में असहिष्णुता का एक लंबा इतिहास रहा है। ब्रितानी औपनिवेशिक प्रशासन ने स्वाधीनता सैनानियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस कानून को प्रयुक्त किया। इसके उपरांत सत्ता में आये अनेक राष्ट्रपतियों ने इस अधिनियम का समाप्त नहीं किया। इस अधिनियम के अनुसार आंदोलनकारियों को पुलिस एवं गृहमंत्री से आंदोलन की अनुमति लेनी होती है। अनुमति प्रदान करने के आधार अनेक स्तरों पर भ्रामक हैं। आंदोलन करने के दिन से 7 दिन पूर्व यह अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। यदि कारण कानून के द्वारा स्वीकृत परिधि से बाहर है अथवा

यदि उस कारण का राजनीतिक अभिजन विरोध करते हैं तो फिर प्रदर्शन की आज्ञा अधिकतर प्रदान नहीं की जाती है। इसके साथ ही यह कानून अवधि के अधिकार को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं करता। अतः अवैध आवासियों को विरोध करने का वैधानिक अधिकार नहीं है भले ही वे उस जमीन पर अनेक वर्षों से रह रहे हों।

राजनीतिक अभिजनों का प्रतिक्रियावादी चरित्र ही विरोध की कमी में योगदान नहीं देता है अपितु उन परिणामों की तरफ भी इशारा करता है, यदि बिना स्वीकृति के प्रदर्शन किया जाये। सार्वजनिक व्यवस्था अधिनियम (पब्लिक आर्डर अधिनियम) का उल्लंघन पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्यवाही को जगह प्रदान करता है। यह कार्यवाही विकसित हुयी अवैध बस्ती में रह रहे लोगों के बीच डर पैदा करती है। उदाहरण के लिए 14 जून 2013 को कामपासां हवाई अड्डे के निकट जबरदस्ती मकान खाली कराने की कार्यवाही में जाम्बिया राष्ट्रीय सेवा के द्वारा दो लोगों को गोली मारकर बुरी तरह घायल कर दिया गया तथा एक कर्मी को चोट लगी। उन्नत अवैध बस्ती में रह रहे मेरे एक साक्षात्कारदाता जार्ज इस बात को लेकर चिंतित थे कि हाल में जबरदस्ती मकान खाली कराये जाने ने स्थितियों को बिगाड़ दिया है। हम एक निश्चित अवधि की सुरक्षा वाले अधिकार लाइसेंस के साथ निवास कर रहे हैं परंतु फिर भी स्थितियाँ सुरक्षित नहीं हैं। जब उनसे यह पूछा गया कि यदि सरकार उनकी भूमि पर पुनः स्वामित्व जमाने आए तो वे क्या करेंगे। उनका जवाब यह था कि वे अपने अधिकार को छोड़ देंगे और कहीं और चले जायेंगे।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण सरकार एवं नागरिक समाज उन संभावित लोगों को संरक्षण देने में असफल है जो जमीन खाली किये जाने को लेकर डरे हुए हैं। आवास की प्राप्ति का अधिकार संविधान में सम्मिलित नहीं है। सन् 2008 में राष्ट्रपति म्वानावासा का तर्क था कि सरकार वित्तीय संसाधन दिये जाने के प्रति प्रतिबद्ध है ताकि आवास प्राप्ति के अधिकार को मूर्त रूप दिया जा सके परंतु उनका यह दावा अमल में नहीं आ सका। इस प्रकार सरकार ने सार्वजनिक रूप से अवैध आवासियों को क्षतिपूर्ति देने के अपने दायित्व से स्वयं को अलग कर लिया। अनौपचारिक बस्तियों को उन्नत करने के लिए संसाधन देने के बजाय ढहा देना सस्ता है।

नागरिकीय समाज के पास वित्तीय संसाधनों का अभाव है। इसके फलस्वरूप वे अवैध बस्तियों के निवासियों से जबरदस्ती जमीन को खाली कराये जाने की स्थिति में उनका संरक्षण नहीं कर सकते। हालांकि जाम्बिया लैंड एलाइन्स एवं होमलैस इंटरनेशनल जैसे संगठन 'द पीपुल्स प्रोसेस ऑन हाउसिंग एंड पावर्टी इन जाम्बिया' जैसे संगठन के माध्यम से जबरदस्ती खाली कराये गये आवासियों के मुद्दों से सम्बद्ध वैचारिक संघर्ष किये हैं, पर वास्तव में वे ऐसा नहीं कर पाये। अनेक बार एलाइन्स समुदायों को सक्रिय नहीं कर पाती हैं और साथ ही संसाधनों एवं दक्षता की कमी के कारण जनहित में न्यायालय के सम्मुख इन मुद्दों को जन अपेक्षाओं के अनुरूप प्रस्तुत नहीं कर पाती (जाम्बिया लैंड एलाइन्स, 2014, <http://www.zla.org.zm/?p=9>)। सन् 2010 में सरकार एवं नागरिकीय समाज के संगठनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इन्हें मिलने वाली आर्थिक सहायता का स्थगन कर दिया गया। परिणामस्वरूप लगभग 2 साल से सभी परियोजनाएँ रुकी पड़ी हैं। ये संगठन अब जब भी संभव होता है एक विज्ञप्ति का प्रकाशन कर देते हैं अथवा प्रदर्शन की धमकियां देते हैं जबकि इनके पास वास्तव में इनके अनुकरणकर्त्ता और कार्यकर्त्ता नहीं हैं।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि लुसाका में जबरदस्ती भूमि खाली करवाने के विरुद्ध आंदोलन का उभार एवं जाम्बिया में नवीन सामाजिक आंदोलनों के सम्मुख दो मुख्य चुनौतियाँ हैं। पहली, किसी भी प्रकार का विरोध राजनीतिक अभिजनों में उत्पन्न असहजता एवं उग्रता को जन्म देता है जिसे खुले रूप में देखा जा सकता है। दूसरे, सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सरकार एवं नागरिकीय समाज आवासीय समस्या का समाधान कैसे करें? एक बार जमीन अथवा मकान को जबरदस्ती खाली कराये जाने के उपरांत लोगों के पास एकत्रित होने या जीवनयापन के कोई अवसर नहीं होते और इसलिए सामूहिक विरोध का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। सार्वजनिक व्यवस्था के कानून में परिवर्तन एवं आर्थिक उन्नति को तीव्रता प्रदान करने वाली स्थितियाँ बेदखली विरोधी आंदोलनों के उभार की स्थितियाँ प्रदान कर सकती हैं। ■

सिंगुम्बे मुयेबा से पत्र व्यवहार हेतु पता :  
<[singumbe.muyeba@uct.ac.za](mailto:singumbe.muyeba@uct.ac.za)>

# > फ़ैबलैब्स और हैकरस्पेसेज : उभरती हुई एक नई संस्कृति

इजाबेल बेरेबी-हॉफमन, मैरी क्रिस्टीन ब्यूरो एवं मिशेल लालेमण्ट, LISE-CNRS, कंजर्वेटर नेशनल डेस आर्ट्स एट मेटियर्स, पेरिस, फ्रांस



हैकरस्पेस का एक प्रारूप।  
फोटो : मिशेल लालेमण्ट

सांझा करने के नये तरीके, और सहयोगी उत्पादन और उपभोग के नये तरीके, वर्तमान अर्थव्यवस्था के लिये प्रश्न उठा रहे हैं। फ़ैबलैब्स और हैकरस्पेसेज की इस परिप्रेक्ष्य में एक खास स्थान है जहां सांझा-प्रेरित धन पंहुच और उपयोग पर आधारित है ना कि संपत्ति पर। ये सामूहिक निर्माण स्थान, जो कि 2000 के दशक के मध्य से आकार लेने लगे थे, ने एक नयी कार्य नीति का सूत्रपात किया: एक निर्माता संस्कृति। सारे संसार में बिखरी हुये इन स्थानों के विभिन्न नाम हैं: फ़ैबलैब्स (निर्माण प्रयोगशालाएँ) हैकरस्पेसेज, मेकरस्पेसज, लिविंग लैब्स, टैक

>>

शॉपस, आदि। ये विभिन्न वस्तुओं को एक साथ फेंकने की, सोफ्टवेयर प्रोग्रामों की कोडिंग करने की, या केवल कपड़ों और खाना बनाने की नई शैली सोचने की खुशी को पुनः खोजने का आमंत्रण है। संसार भर में प्रमुख शहर ऐसे स्थानों का स्वागत कर रहे हैं जो एक साथ उत्पादन, सहयोग, खपत और सीखने के नये तरीकों को बढ़ावा देते हैं।

एक 3-डी प्रिंटर अक्सर ऐसे स्थानों पर ध्यान का केंद्र होता है, क्योंकि ये इंटरनेट पर पाये जाने वाली किसी योजना का उपयोग करते हुये किसी भी वस्तु का निर्माण करने देता है। अधिकांश स्थानों पर पेशेवर उपकरण भी हैं जैसे संख्यात्मक नियंत्रण मशीनें: कटर, लेजर कटर, सिल्कस्क्रीन प्रिंटर। सिर्फ कुछ साल पहले तक इन मशीनों से सफलतापूर्वक प्रतिरूपों के निर्माण के लिये महीनों का प्रशिक्षण जरूरी होता था। आज, इन मशीनों के सही उपयोग का प्रशिक्षण कुछ ही घंटों में हो जाता है। इसके अलावा, मशीनों और डिजाइन सोफ्टवेयर की कीमतें काफी गिर गयी हैं। इस प्रकार, जैसे पर्सनल कंप्यूटर हमें तकनीकी दुनिया में पहुंचा देता है, उसी तरह पर्सनल फ़ैब्रिकेटरस् हमें भौतिक दुनिया में काम करने देते हैं।

हालांकि ये सब समान मूल्यों पर आधारित है, फिर भी बार्सीलोना, बर्लिन, सेन फ्रांसिस्को, पेरिस या बीजिंग की निर्माण प्रयोगशालाएँ एक जैसी नहीं हैं। फ़ैबलैबस् ने 2000 के दशक की शुरुआत में MIT (मैसच्युसेट्स) में जन्म लिया और विश्वव्यापी नेटवर्क बनाया। हैकरस्पेसेज् की कहानी अलग है। उनकी शुरुआत कैलिफोर्निया में 1970 के दशक की शुरुआत में होमब्रु कंप्यूटर क्लब के साथ हुयी, एक इनक्यूबेटर जहां रुचि वाले लोग सूचना प्रौद्योगिकी के अविष्कार और अन्वेषण के लिये इकट्ठा होते थे। कुछ अपने निष्कर्ष मुफ्त में साझा करते थे जबकि अन्य, स्टीव जोबस् और बिल गेटस् सहित, ने एक अधिक पारंपरिक पूंजीवादी रास्ता अपनाया। हैकर भावना से ओतप्रोत हैकरस्पेसेज् संगठनात्मक दृष्टिकोण से फ़ैबलैबस् से अलग नहीं थे। भले ही कोडिंग इन जगहों पर अधिक उन्नत हो, फिर भी हैकरस्पेसेज् समान रूप से निर्माण, खोज, विभिन्न वस्तुओं के साथ नये प्रयोगों और कुछ नयी वस्तुएँ बनाने के सामानों से युक्त थे। इसके अलावा, फ़ैबलैबस् की तरह ही, सार्वजनिक उपयोग एक महत्वपूर्ण कसौटी है, साथ ही इन जगहों को निर्माण और नवाचार का स्थान और सामूहिक सीख और ज्ञान साझा करने का स्थान बनाने की इच्छा भी।

निर्माण प्रयोगशालाएँ आंशिक रूप से उन क्षेत्रों में आधारित हैं जहां वे स्थित हैं। वे नेटवर्क से संचालित होती हैं जो नयी उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र की आकृतियां बनाते हैं। कुछ समीक्षक इन्हें नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत या पूंजीवाद से एक सभ्य निकासी के

अग्रगामी कहते हैं। परंतु किसी को इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये महसूस करने के लिये कि इन नये संसारों को गंभीरता से लेना चाहिये। ये स्थान तकनीकी, राजनैतिक और संगठनात्मक स्तरों पर बहुत नवाचारों से भरे हुये हैं। हो सकता है कि वे मुख्य अर्थव्यवस्था के हाशिये पर स्थित हो, परंतु इनकी बढ़ती सफलता लोगों के काम करने, डिजाइन, उत्पादन, निर्णय लेने और क्रिया करने के तरीके में सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव की द्योतक है।

समाजशास्त्रियों द्वारा इन नये निर्माण स्थानों का अध्ययन किया जाना दर्शाता है कि हालांकि ये स्थान असमान हैं, फिर भी ये डेवलपर और हैकर समुदायों द्वारा बनाये गये संगठन के साझा तरीके रखते हैं। कुछ दशकों पूर्व आयी मुक्त स्रोत संसार से पोषित संस्कृति ने समतावादी और क्षैतिज नेटवर्कों पर आधारित काम और सहयोग करने के नये तरीकों को जन्म दिया। उन्होंने वस्तुओं और सेवाओं को साझा करने के नये तरीकों का विकास किया जैसे कॉपीलेफ्ट लाइसेंस<sup>1</sup> के माध्यम से। निर्माता आंदोलन जिसमें निर्माण प्रयोगशालाएँ शामिल हैं, को डिजाइन की दुनिया में विलियम मोरिस द्वारा शुरू की गई औद्योगिक समाज की आलोचनात्मक परंपरा से प्रेरणा मिलती है।

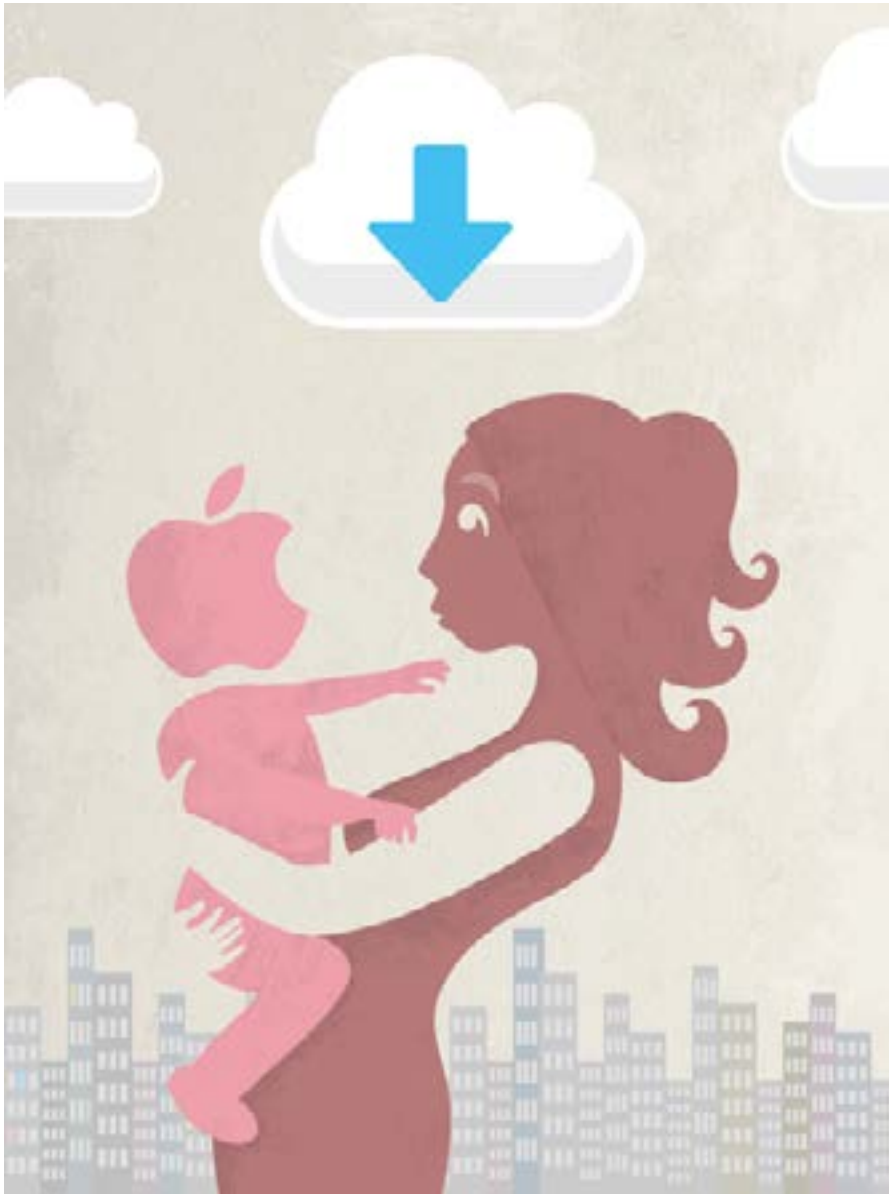
उत्तरी कैलिफोर्निया में किये गये हैकरस्पेसेज् का एक हाल ही का हमारा सर्वेक्षण बताता है कि ये वैकल्पिक निर्माता दुनिया अधिकतर 30 साल के श्वेत शिक्षित युवाओं से बनी हैं जिनका शिक्षा से मोहभंग हो गया है। गूगल इंजिनियरों और बेघर तकनीशियनों द्वारा अक्सर इस्तेमाल किये जाने वाले इन स्थानों का एक ही उद्देश्य है कि कंप्यूटरों, भौतिक वस्तुओं और यहां तक कि समाज का उपयोग कर नवाचार करना। कुछ निर्माता सक्रिय रूप से सिलिकॉन वैली के लिये नवाचार प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं जबकि कुछ अधिक परिवर्तनवादी अपनी ऊर्जा व्यवस्था स्थापित करने वालों की सेवा में लगाते हैं, जैसे कि ऑक्यूपाइ आंदोलन। सामान्यीकृत संरचनात्मक संकट के समय, इन वैकल्पिक स्थानों, असली यूटोपिया जहां काम करने, निर्णय लेने, उपभोग करने और साथ रहने के नये तरीकों को खोजा जा रहा है, का अध्ययन वाजिब है। ■

मिशेल लालेमण्ट से पत्र व्यवहार हेतु पता :  
<[michel.lallement@cnam.fr](mailto:michel.lallement@cnam.fr)>

<sup>1</sup> Berbebi-Hoffmann I., Bureau M.-C., Lallement M. (eds.), *Recherches sociologiques et anthropologiques, special issues "Tiers lieux de fabrication et culture collaborative. De nouveaux mondes de production sont-ils en train d'émerger?"* (forthcoming).

# > 'बहुसक्रिय समाज' में लैंगिक समानता को पाना

बर्नार्ड फुसुलियर, FNRS, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉवेन, बेल्जियम एवं चंताल निकोल-ड्रानकोर्ट, CNRS-LISE, कंजर्वेटर नेशनल डेस आर्ट्स एट मेटियर्स, पेरिस, फ्रांस



कार्यस्थल पर समस्यात्मक लिंग नीतियां।  
चित्रण अरबू द्वारा

घटती जन्म दर, माताओं की घटती रोजगार की दर और मातृत्व का त्याग, "विकसित" देशों में समाज कल्याण के स्तरों और जनसांख्यिकी के लिये मुख्य जोखिम माने जा रहे हैं। हांलाकि आर्थिक और बजट संकट ने कुछ गये वर्षों में सभी सामाजिक अनुबंधों को प्रभावित किया है, फिर भी इन्होंने विशेष रूप से लैंगिक समानता के आयामों को चुनौती दी है और कार्य-परिवार संतुलन की स्थिति को बदतर किया है।

सभी स्तरों के नीति निर्माता इस बढ़ती जागरूकता का विवरण देते हैं कि महिलायें सामाजिक एकता को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलायें उनकी दोहरी भागीदारी, श्रम बाजार और घरेलू गतिविधियों में योगदान के लिये जानी जाती हैं, जो कि सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हुये संस्थागत कमियों और असंतुलन को बराबर करता है और मुश्किल समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

एक नयी वैश्विक सहमति के अनुसार अधिकतर लोग उनके पेशेवर करियर को बनाये रखते हुये बच्चों और आश्रितों का ख्याल रखने की आशा करते हैं। वे मौजूदा लैंगिक श्रम विभाजन और जुड़ी हुयी प्रजनन गतिविधियों को प्रश्न किये बिना इस दोहरी जिम्मेदारी को बनाये रखने की आशा करते हैं, जो कि हमेशा की तरह ही आज भी मानती है कि महिलायें प्राथमिक जिम्मेदारी घरेलू गतिविधियों की ही लेंगी। नतीजतन, लगभग सभी देश इन दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिये माता-पिता की मदद करने और व्यक्ति और समाज के लिये एक प्रमुख मुद्दे कार्य और परिवार संतुलन के लिये सहमत हैं।

पहली नजर में, सार्वजनिक मूल्यांकन यौन तटस्थ नजर आते हैं: बिंदु यह है कि सभी एक आय के लिये काम कर सकते हैं। उन सभी देशों में जहां कल्याणकारी

>>

राज्य मजबूत है (उन सभी देशों में भी जहां ये कार्यक्रम बन रहे हैं) हमें कार्य और पारिवारिक दायित्वों को निभाने के उद्देश्य से बनने वाली सामाजिक नीतियों में अभूतपूर्व विस्तार देखने को मिलता है— कर और लाभ व्यवस्था में सुधारों से लेकर बाल देखभाल व्यवस्थाओं के बेहतर प्रबंधन तक, और काम के संगठन के संदर्भ में पेशेवर और पारिवारिक जीवन में एक बेहतर संतुलन के उद्देश्य की रीतियों के प्रोत्साहन में भी।

फिर भी सभी देशों के संदर्भ में, नीतियों के क्रियान्वन में बदलाव आ रहा है। लिंग तटस्थ बातचीतों के बावजूद, राजनीतिक एजेंडाओं (या कंपनियों में) में लिखे गये उपाय व्यवहार में अपनी तटस्थता खो रहे हैं। कार्यशील महिलाओं को सहायता देने हेतु सबके लिये माता पिता और परिवार के अवकाश एक लाभकारी तरीका बन गया; महिलाओं के लिये अंशकालिक कार्य में अचानक वृद्धि ने सबके लिये कार्यसमय में कमी के विचार को कम प्रभावी कर दिया; माता पिता दोनों को मिलने वाले जन्म अवकाश की लंबाई को महिलाओं और बच्चों की कुशलता पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में आंका जाये, आदि। दूसरे शब्दों में इन नीतियों के केन्द्र में लक्ष्य पुरुष या माता-पिता नहीं है बल्कि महिला है, वास्तविक या संभावित माता के रूप में। अक्टूबर 2014 में, उदाहरण के लिये, फेसबुक और एपल ने खुले रूप से अपनी महिला कर्मियों को उनके अंड सुरक्षित रखने का विकल्प देना स्वीकार किया, ताकि वे "अधिकाधिक श्रम बाजार और पुरुषों की प्रतिस्पर्धा से जूझ" सकें।

कुछ तो यह प्रतिरूप बदलते परिवार प्रतिमानों के प्रतिरोध को दर्शाता है—बदलाव जो कामकाजी माता पिता की मदद के लिये

हो रहे उपायों के बावजूद हो रहे हैं। इसके अलावा, माताओं का रोजगार बनाये रखना—जब अधिकतर मातायें काम और परिवार सहारे की "दोहरी पारी" करती हैं— एक वास्तविक राजनैतिक समस्या बन जाती है, प्रश्न करते हुये कि महिलाओं के "उत्पादन के बाहर" के कार्य को प्राथमिकता देना शारीरिक और मानसिक रूप से वहनीय है कि नहीं और क्या ये प्रथायें सामाजिक न्याय के आदर्शों को लांघती है या नहीं।

पेशे और परिवार की जिंदगी के सामंजस्य की लड़ाई अभी भी जीत से बहुत दूर है। हम सामान्य प्रश्न के साथ शुरू करते हैं (माता पिता को काम और पारिवारिक जीवन के बीच में सामंजस्य बिठाने में कैसे मदद की जाये), परंतु हम आंशिक समाधान ही देते हैं (यौन विभाजन को बदले बगैर माताओं से आय अर्जित करने की उम्मीद)।

आगे बढ़ने के लिये, परिवर्तन की शुरुआत 19वीं शताब्दी की मजदूरी-आधारित संगठनात्मक और संस्थागत बुनियादों और 20वीं शताब्दी के कल्याणकारी राज्य की आलोचना और पुर्ननिर्माण से होनी चाहिये। हमें स्थापित सामाजिक व्यवस्थाओं को सवाल करना चाहिये और रीतियों की सहजता को तोड़ना चाहिये जो इन व्यवस्थाओं से बनती हैं। हमें लैंगिक संबंधों से जुड़े सामाजिक अनुबंधों को प्रश्न करना चाहिये: एक ऐसी दुनिया का विचार जो उत्पादन पर केंद्रित है, देखभालकर्ता द्वारा समर्थित एक निर्माता का आणुविक चरित्र की धारणा, एक परिवार के लिये कमाने वाले पुरुष का आदर्श, एकता का पुरुष-केंद्रित समझौता। हमें उत्पादक और प्रजनन गतिविधियों के सामाजिक विभाजन और उनके लैंगिक निर्धारित कार्यों की पूर्ति को तोड़ना चाहिये।

यदि हम इन कथनों को गंभीरता से लेते हैं, तब हम एक वैकल्पिक समाज का विचार शुरू कर सकते हैं, संदर्भों के नये ढांचों के साथ जो अब रोजगार के अलावा सामाजोपयोगी गतिविधियों को दूसरे दर्जे का नहीं मानता हो। हम एक मजदूरी-आधारित समाज को एक "बहुसक्रिय समाज" में परिवर्तित करना शुरू कर सकते हैं। किसी भी गतिविधि को सर्वोच्च या महिला या पुरुष के लिये आरक्षित माने बिना रोजगार को पुर्नकल्पना में अन्य गति-विधियों की सापेक्ष सामाजिक निवेश के संदर्भ में उपयोगिता से जांचा जाये। निष्क्रियता या गैर-कार्य असामान्य हो जायेगा और काम-परिवार मंथन मुख्यतः महिलाओं पर ही बोझ नहीं रहेगा।

इस परिवर्तन के लिये गतिविधियों के नयी व्यवस्था के प्रगतिशील निर्माण की आवश्यकता है, जहां "सक्रिय" होने की स्थिति को रोजगार की प्रतिबंधित धारणा के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जाता, बल्कि देखभाल के काम और सिविल श्रम को शामिल करने वाली काम की एक अधिक समावेशी धारणा पर आधारित हो। इस दृष्टिकोण से, समाज सवैतनिक कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा और गैर-बाजार रूप वाले कार्यों की अनदेखी नहीं करेगा; इसके बजाय, हम सार्वजनिक हित और स्वस्थता के लिये योगदान देने वाली सभी गतिविधियों की उपयोगिता को पहचानने और बल देने वाली एक व्यापक अवधारणा की ओर अग्रसर होंगे। ■

बर्नार्ड फुसुलियर से पत्र व्यवहार हेतु पता :  
<bernard.fusulier@uclouvain.be>

और चंताल निकोल-ब्रानकोर्ट से पत्र व्यवहार हेतु पता : <drancourtchantal@hotmail.com>

# > कार्य में पुरानी बीमारी पर बातचीत

ऐनी-मैरी बसर, डोमिनिक ल्हूर्लियर, फ्रेडरिख बुगुयल्स, पियरे लेनल, ज्यूलाम हयूज, जोयल मेज्जा एवं कैथी हेमण्ड, कंजर्वेटर नेशनल डेस आर्ट्स एट मेटियर्स, पेरिस, फ्रांस

**फ्रांस** में कामकाजी उम्र की आबादी को कार्यरत रखना दो कारणों से चिंता का विषय बन गया है: एक तो इस आबादी की उम्र बढ़ रही है और अधिक प्रतिशत जनसंख्या में कठिन बीमारी विशेषकर कैंसर पाया गया है। विस्तृत जांच के कार्यक्रमों से प्रति वर्ष पाये जाने वाले मामलों में वृद्धि हुयी है, जबकि चिकित्सा प्रगति, जल्दी पता लगने, और कम पार्श्व प्रभाव वाले बेहतर उपचार से पहले वाली मृत्युकारक परिस्थितियों को चिरकालिक बीमारियों में बदल दिया है। फ्रांस में लगभग 15 लाख युवाओं में गंभीर बीमारियां पायी गई है जो कि कामकाजी उम्र की आबादी का लगभग 20 प्रतिशत है।

मरीज संगठनों ने लंबे समय तक बीमार या विकलांग रहने वालों की मदद करने की चिंताओं को उठाया है। हांलांकि, विभिन्न बीमारियों (हेपेटाइटिस, एचआईवी, कैंसर, मल्टीपल स्केलेरोसिस, मधुमेह, आदि) पर शोध करने वाली एजेंसियों ने हाल ही में गुणात्मक सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिये अनुरोध करना शुरू किया है। मुख्यतः वे उन व्यक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं जिन्होंने बीमारी की छुट्टी के बाद वापिस काम करना शुरू किया है और साथ ही कि वे कैसे काम करते रह रहे हैं। इस संदर्भ में, हम ने मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रीयों को साथ मिलाते हुये एक क्रियात्मक नीति अनुसंधान परियोजना बनाई: (1) बीमारी से ग्रसित एक व्यक्ति की परिस्थितियां समझने के लिये जो काम पर लौटता है और कार्यरत रहता है; और (2) सामूहिक और व्यक्तिगत संसाधन उपलब्ध कराने के लिये हस्तक्षेप जो उसके रोजगार को मदद करें।

यह क्रियात्मक शोध परियोजना तीन बड़ी फ्रांसीसी फर्मों द्वारा क्रियान्वित की गयी थी। ढाई साल में, हमने विशेष रोगों से ग्रसित लोगों के समूहों का अध्ययन किया जो काम पर लौटना चाहते थे या कोई पसंद की गतिविधि आगे बढ़ाना चाहते थे जो चाहे आर्थिक संसाधन मुहैया कराये या नहीं (देखभाल, शिक्षण, स्वयंसेवा सामुदायिक कार्य, इत्यादि)। उनकी सामाजिक परिस्थितियों के विश्लेषण करने के लिये हमने हमारे अध्ययन में तीन पदानुक्रमित स्तरों को विचार किया: 1) कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पर मानव संसाधन प्रबंधन की प्रथायें; 2) मध्यस्थ स्टाफ जो बीमारी की छुट्टी, क्रोनिक थकान, अस्थायी या स्थायी विकलांगता की स्थिति में प्रबंध करते थे; 3) कर्मचारी जो रोग मूल्यांकन के बाद काम पर लौट आये और उनके साथी भी। हम ने इस जनसंख्या द्वारा कार्य जीवन, पारिवारिक जीवन, पर्यावरण, समुदाय, आदि पर एक बीमारी का प्रभाव स्पष्ट करने के लिये प्रासंगिक माने गये सभी तत्वों का विश्लेषण किया। अधिक विशिष्ट रूप से, हमने उन बाधाओं जिनका उन्होंने सामना किया, वो संसाधन जिनका इस्तेमाल उन्होंने उन बाधाओं का सामना करने के लिये किया और वो परिस्थितियां जिनमें उन संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, के बारे में पूछताछ की।

हमारा अनुसंधान उन कर्मचारियों तक सीमित नहीं था जिनकी बीमारी या विकलांगता घोषित थी। हमने संसाधनों की तुलना करने की कोशिश की जो उन कर्मचारियों को उपलब्ध थे जिन्होंने अपनी बीमारी सहकर्मियों या पर्यवेक्षकों को नहीं बताया थी, उन कर्मचारियों



## “सिर्फ 2.5 मिलियन ही गंभीर बीमारी के प्रमाण पत्रों के लिये अनुरोध करते हैं, जबकि 9.9 मिलियन ऐसा कर सकते हैं।”

के साथ जिन्होंने अक्षमता मुआवजा लेने की प्रार्थना की और लिया था। उन सामाजिक लाभों को प्राप्त करने के लिये, उन्होंने इन दावों का आकलन करने वाली एजेंसी से बीमारी का प्रमाण पत्र का अनुरोध किया। महत्वपूर्ण यह है कि फ्रांस में गंभीर बीमारी से ग्रसित अधिकतर कर्मचारी ऐसे लाभ लेने का अनुरोध नहीं करते। वास्तव में सिर्फ 2.5 मिलियन ही ऐसे प्रमाण पत्रों के लिये अनुरोध करते हैं, जबकि 9.9 मिलियन ऐसा कर सकते हैं। हमने बीमारी को घोषित करने के परिणामों को समझने की कोशिश की, और साथ ही उन कारणों को जिनकी वजह से अधिकांश ऐसा करने से बचते हैं।

परिणाम दर्शाते हैं कि एक प्रमाणित बीमारी या विकलांगता के लिये अधिकृत मुआवजा एक कलंक माना जा सकता है या अन्यायपूर्ण माना जा सकता है। अंतरविषयक विशेषज्ञ कमीशन द्वारा जारी किये जाने वाले ये मुआवजे अक्सर बहुत कठोर होते हैं, जबकि बीमारियां अधिक लचीली हो सकती हैं। कार्य वातावरण में वे अक्सर गलत समझे जाते हैं कि सहकर्मी और पर्यवेक्षक मुआवजे के प्रकार, विविधता और अवधि के बारे में बातचीत से दूर रखे जाते हैं। इसके बाद, इन मुआवजों के क्रियान्वन में दूसरी बाधा है: मानव संसाधन या स्वास्थ्य सेवा इनको असली कार्य परिस्थितियों की आंशिक जानकारी के साथ उपर से थोप देती हैं। इसलिये, ये उपाय सहकर्मियों के बीच अनौपचारिक व्यवस्थाओं की अनदेखी कर देते हैं जो प्रबंधन के साथ समझौते में बने हो और अधिक लचीलापन प्रदान कर सकते हो। बिना पूर्व बातचीत के थोपी गयी व्यवस्थाओं की अपेक्षा, पारस्परिकता पर आधारित, सारी स्थानीय व्यवस्थाएँ जिनका हमने विश्लेषण किया, कार्यस्थल पर कम तनाव पैदा करती हैं। इसके अलावा, पारस्परिक मामलों जिनका हमने विश्लेषण किया, में

सामूहिक और व्यक्तिगत गतिविधियां शामिल थी। संक्षेप में, स्थानीय व्यवस्थाएँ विशिष्ट संदर्भों पर आधारित थी।

हमारे शोध में पाया कि सफल मुआवजे —जो कि सामाजिक कर्ता द्वारा उचित माने गये और जो बीमारी की छुट्टी से आगे भी चलते रहे —की कई विशेषताएँ थी: वे कानूनी उपायों और स्थानीय व्यवस्थाओं का मिलाजुला रूप थे; वे उन लोगों द्वारा व्यक्त किये गये थे जिन्होंने कार्यस्थल पर मुश्किलों का सामना किया था; और मुआवजा संयुक्त रूप से विस्तृत था। इन सामाजिक कर्ताओं ने किसी भी असमर्थता और किसी भी कर्मचारी के पक्ष में बात की। इन्होंने कुछ विशेषज्ञों के बीमारी के प्रमाण पत्रों की पूछताछ की जो अधिकार देते थे परंतु बीमारी को लाभ लेने का साधन जैसे लगते थे। कुल मिलाकर, फर्मों में किये गये कार्य सहायता प्रदान करने वाले और प्राप्त करने वालों के बीच में पारस्परिकता की स्थानीय परिस्थितियां पैदा करना था जो एकजुटता, सदभावना, आपसी सहयोग और विकलांगता के मुआवजे से बढ़कर हो। हमने देखा कि मरीज संगठनों ने प्रतिभागियों को अपनी कार्य परिस्थितियां बदलना शुरू करने के वास्तविक अवसर प्रदान किये। अंत में, उन्होंने व्यक्तियों को बीमार होने के मतलब को पुनः ठीक करने, एक पहचान स्थापित करने और व्यक्तिगत परिस्थितियों को सामूहिक अधिकारों के क्षेत्र में लाने की अनुमति भी दी। ■

ऐनी-मैरी बसर से पत्र व्यवहार हेतु पता :  
<[anne-marie.waser@cnam.fr](mailto:anne-marie.waser@cnam.fr)>

# > इंडोनेशिया में लोकतंत्र का उत्सव

लूसिया रातिह कुसुमादेवी, इंडोनेशिया विश्वविद्यालय, डिपोक, इंडोनेशिया, सदस्य, आई. एस. ए. शोध समिति –  
धर्म का समाजशास्त्र (RC 22) सामाजिक वर्ग एवं सामाजिक आन्दोलन (RC 47)



जोको विडोडो और जुसुफ कल्ला की अध्यक्षीय टीम के समर्थक जकार्ता में अपने चुनावी अभियान को संयोजित करते हुए।

“अभिवादन! दो अंगुलियां! जोकोवी को वोट करना मत भूलना!” स्लैक एक प्रसिद्ध राँक बैंड, खुशी से झूमते हुये अत्यंत उल्लास के साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जोकोवी और उपराष्ट्रपति पद की दौड़ के उनके साथी जुसूफ काला के समर्थन में, जकारता के बंग कारनो स्टेडियम में 5 जुलाई 2014 को गा रहा था। उनके साथ लाखों की संख्या में समर्थक; बूढ़े और जवान, पुरुष और स्त्री, अमीर और गरीब भी निशुल्क संगीत संगोष्ठी के दौरान गा रहे थे। कुछ क्षण पश्चात् जिस व्यक्ति की प्रतिक्षा थी वह प्रकट हुआ; जोकोवी मंच पर चढ़े एवं अपने समर्थकों का अभिवादन किया। भीड़ अपनी दो अंगुली थाम

कर “जोकोवी! जोकोवी! चिल्ला रही थी और वातावरण रोमांचकारी हो रहा था।

इस वर्ष, प्रथम बार, इंडोनेशिया के चुनाव ‘जन लोकतंत्र के लिये वास्तविक पार्टी’ में परिवर्तित हुये। उत्साह थम नहीं रहा था, असंख्य लोग प्रबल अभियान में भाग ले रहे थे, जिसमें वो अभियान की गतिविधियों की रचना से लेकर दान के रूप में 295 बिलियन रुपये से अधिक राशि को एकत्रित करने के कार्य में व्यस्त रहे। चुनाव के दिन, धन की राजनीति को नकारते हुये, जिसे पूर्व में एक सामान्य व्यवहार के रूप में स्वीकृत किया गया था, लोगों ने चुनाव परिवीक्षण के लिए मिलकर काम किया ताकि उसे कपट से बचाया जा सकें।

>>

यह है इंडोनेशिया के रोमांचक नये लोकतंत्र का चेहरा : महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन एक ऐसे लोकतंत्र से, जो गन्दी राजनीति और सत्ता के भूखे राजनीतिज्ञों के भार से लदा है जिनके कार्य करने का तरीका असत्य क्रियाओं से परिपूर्ण है, से आमूलचूल परिवर्तित ऐसे लोकतांत्रिक सुधारों में जिनका उद्देश्य एक अधिक सभ्य एवं मानवतावादी लोकतंत्र को स्थापित करना है। इंडोनेशिया के वर्तमान चुनावों में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लेन-देन आधारित राजनीतिक लामबंदी जो अधिकतर राजनीतिक दलों के संभ्रात व्यक्तियों द्वारा प्रचलन में थी ने अपनी लोकप्रियता खो दी और अब यह लुप्त होने के कगार पर है। उसके स्थान पर एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति का जन्म हुआ है, जिसका आधार ऐच्छिक सहभागिता है एवं हम सब इसके साक्षी हैं।

इस परिवर्तन के क्या कारण थे? कुछ अवलोकनाकर्ताओं ने यह अनुमान लगाया होगा कि यह 'प्रभाव' अकस्मात् सा हुआ प्रतीत होता है, विशेषकर इंडोनेशिया की गन्दी राजनीति के एक लम्बे इतिहास के बाद। यह स्पष्ट है कि 'जोकोवी प्रभाव' परिवर्तन को शुरू करने का मुख्य कारक रहा है, पर विशेष परिस्थितियों ने बदलाव की हवा चला दी है। एक निश्चित बिन्दु पर समस्त ब्रह्माण्ड जैसे कह रहा है 'यही समय है'—समय जिसने परिवर्तन की आकांक्षा का प्रत्युत्तर दिया और अव्यवस्था भ्रष्टाचार और राजनीति अल्पतंत्र पर हताशा एवं विरुचि अपने चरमोत्कर्ष पर है। जोको विडोडो, जो जोकोवी के नाम से प्रसिद्ध हैं, पिछले दो सालों में काफी लोकप्रिय हुये हैं। एक उद्यमी, जिन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर 2005 में सोलो, जो मध्य जावा के प्रमुख शहरों में से है, के मेयर के रूप में प्रारंभ किया। जोकोवी शालीन पृष्ठभूमि से एक ईमानदार एवं मेहनती व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनको सरकारी नीतियों को क्रियान्वित करने में मानवतावादी उपागम के लिये, अपनी नगरपालिका से भ्रष्टाचार को साफ करने के लिये और सोलो शहर का पर्यटन और संस्कृति का केन्द्र बनाने के लिये की गयी कड़ी मेहनत की वजह से भी पसंद किया जाता है। 2013 में जोकोवी को सिटी मेयरस् फाउण्डेशन ने विश्व का तीसरा सबसे अच्छा मेयर घोषित किया और 2014 में जोकोवी का नाम फॉरच्यून पत्रिका द्वारा "विश्व के शीर्ष 50 नेताओं" की श्रेणी में शामिल किया गया।

सोलो शहर में जोकोवी की सफलता ने उनके राजनीतिक कैरियर को धक्का दिया। इंडोनेशिया की डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ स्ट्रगल (पी. डी. आई. पी.) — देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी — के समर्थन से 2012 में वो जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी के राज्यपाल चुने गये। उप-राज्यपाल जाहजा बासुकी पुरनामा (अहोक), जो अपनी सत्यनिष्ठा के लिये भी जाने जाते हैं, के साथ जोकोवी ने कई नई योजनायें क्रियान्वित की—जिनमें बाढ़ रोकथाम के लिये कार्यक्रम, यातायात भीड़ जैसी समस्याओं को शामिल किया

गया, जिन्हें पूर्व में कभी भी इस महानगरी में संजीदगी से नहीं लिया गया था। नदियों पर नियंत्रण और जन यातायात में सुधार के साथ, जोकोवी और अहोक ने नगर नियोजन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किये।

जैसे-जैसे राष्ट्रपति चुनाव निकट आये, पी. डी. आई. पी. ने जोकोवी को अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाया। उनकी जोड़ी जूसूफ काला (जे.के.), पूर्व उप-राष्ट्रपति और गोलकर पार्टी के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ के साथ बनायी गयी। जोकोवी का इंडोनेशिया के लिये दृष्टिकोण को एक 'मानसिक क्रांति' को प्रारंभ करने के आमंत्रण के साथ जोड़ दिया गया। जोकोवी ने इंडोनेशिया की जनता से उनके प्रयासों के साथ जुड़ जाने का आग्रह किया। भ्रष्टाचार-विरोधी, पारदर्शिता, आपसी सहयोग, सृजनात्मकता, आत्मनिर्भरता, विभिन्नताओं का सम्मान 'मानसिक क्रांति' के कुछ मूल आधार हैं।

एक बार जोकोवी और जे. के. जब एक टीम के रूप में आये तो चुनावी नतीजों के समर्थन का बढ़ना स्पष्ट दृष्टिगत हुआ विशेषकर प्रजातंत्र समर्थक सक्रियतावादियों, बुद्धिजीवियों, संगीतज्ञों एवं कलाकारों, युवा वर्ग, छात्र, उद्योगपति और लोकप्रिय वर्ग की ओर से। इन समर्थकों ने समुदायों में बिना किसी वेतन के ऐच्छिक रूप से कार्य किया। यहां तक कि कुछ ने तो अपनी जेब से भी खर्च किया। इसके विपरीत उनके राजनीति प्रतिद्वंद्वियों प्राबोबो और हट्टा सत्ता एवं धन के लालची समूह, प्रतिक्रियावादी समूह और भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के द्वारा समर्थित थे।

और आखिरकार 22 जुलाई 2014 को आम चुनाव आयोग ने जोकोवी-जे. के. को 53.1% वोटों से विजयी घोषित किया। उनके प्रतिद्वंद्वी प्राबोबो-हट्टा, को 47.8% वोटों से पराजयी घोषित किया। कई विश्लेषकों ने इस विजय को जनता की विजय बताया। यहां उल्लेखनीय है कि जोकोवी-जे. के. की विजय का प्रत्यक्ष संबंध किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन से नहीं था। जोकोवी-जे. के. के समर्थक प्रधानतः अ-पक्षपाती हैं : उनमें से अधिकांश किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं थे और कई ने पूर्व में किसी चुनाव में भी सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था।

आज, इंडोनेशिया की जनता के लिये स्वस्थ लोकतंत्र एवं मर्यादा वाली राजनीति की एक नयी आशा है। पिछले चुनावों में स्वैच्छिक सहभागिता की नयी संस्कृति, व्यापक लोकतंत्र सुधारों के लिये बीज साबित हो सकती है और इंडोनेशिया में सामाजिक परिवर्तन का प्रथम चरण भी। ■

लुसिया कुसुमादेवी से पत्र व्यवहार हेतु पता :  
<lucia.ratih@ui.ac.id>

# > इंडोनेशिया की उच्च शिक्षा का निगमीकरण

कामान्टो सुनार्तो, इंडोनेशिया विश्वविद्यालय, डिपोक, इंडोनेशिया, सदस्य आई. एस. ए. शोध समिति—शिक्षा का समाजशास्त्र (RC 04) समाजशास्त्र का इतिहास (RC 08)



जकार्ता में शिक्षा के नवउदारवादी नियमन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए छात्र।

इंडोनेशिया के सुधार आन्दोलन के बाद जिसने वहां के 32 साल के सत्तावादी सैन्य राज को 1998 में खत्म कर दिया, राज्य ने विवादित वाले शैक्षिक सुधारों का शुभारंभ किया। 2003 से सांविधानिक अदालत की स्थापना ने नये स्थल खोले, जहां समाज उन कानूनों को चुनौती दे सकता था जिन्हें वह असांविधानिक मानता था और पिछले एक दशक

से ज्यादा समय में शिक्षाविदों, छात्र और नागरिक समाज समूहों ने नये शिक्षा कानून पर मुकदमे दायर किये।

1999 में सरकार ने एक सरकारी विनियम जारी किया जिसके द्वारा किन्हीं सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों के निगमीकरण की अनुमति प्रदान की गयी। परिवर्तन के जो कारण दिये गये वह थे—भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न कड़ी प्रतिस्पर्धा के

>>

प्रत्युत्तर में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिये अधिक स्वायत्तता प्रदान करना। इसके परिणामस्वरूप सरकार ने 2000 से 2010 के मध्य 6 सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और 2 सार्वजनिक संस्थानों का निगमीकरण किया।

सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों के निगमीकरण को जनता की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, विशेषकर अभिभावक और छात्र वर्ग की तरफ से। पूर्व में सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षा शुल्क पर सरकार का कड़ा नियंत्रण था। जैसे जैसे सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों का निरंतर विस्तार होता गया, सरकारी निधि बढ़ते हुये शिक्षा के खर्च के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पायी और शिक्षा-शुल्क बढ़ते हुये राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। शिक्षा शुल्क में आवधि का बढ़ोतरी सामान्य हो गयी।

सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने पूर्व में शिक्षा-शुल्क में वृद्धि का प्रतिरोध अपने परिसर में विभिन्न माध्यमों द्वारा किया था जैसे-परिसर और सड़क पर प्रदर्शन, कब्जा करो आन्दोलन, याचिका, सार्वजनिक बहस मीडिया द्वारा आलोचना और हाल ही में सोशल मीडिया द्वारा कई छात्रों ने सार्वजनिक उच्च शिक्षा के निगमीकरण का विरोध इस मन से किया कि अधिवृद्धित शिक्षा-शुल्क और शिक्षा का तीव्र व्यवसायीकरण अल्पसुविधा प्राप्त छात्रों के प्रवेश में प्रभावी रूप से बाधा उत्पन्न करेगा। हालांकि ज्यादातर, विरोध के यह प्रयास व्यर्थ साबित हुये क्योंकि परिसर प्राधिकारी दृढ़ खड़े रहे, उन्हें यह ज्ञात था कि उनको सरकार का समर्थन है।

2003 में राज्य ने एक नया कानून पारित किया, जिसमें अन्य वस्तुओं के साथ सभी शिक्षण संस्थाएँ-औपचारिक और अनौपचारिक, नर्सरी से लेकर तृतीयक तक सभी स्तर पर, दोनों-निजी एवं सार्वजनिक; के निगमीकरण को प्रस्तावित किया गया। तदनंतर 2009 में शिक्षण संस्थानों के निगमीकरण का कानून जारी किया गया।

इन दो नवीन कानूनों ने उन निजी प्रतिष्ठानों को खतरे का संकेत दिया जो वर्तमान में शिक्षण संस्थाएँ चला रहे थे, क्योंकि इन कानूनों से उनके नियंत्रण में महत्वपूर्ण कांट-छांट होनी थी। 2006 में 16 निजी और स्वयं सेवी संस्थाओं ने अदालत में 2003 के कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन करने की, विशेषकर निगमीकरण

के अनुच्छेद, के लिये याचिका दायर की। हालांकि याचिका को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि कानून अभी तक भी अधिनियमित नहीं हुआ।

अभिभावक, छात्र और नागरिक समाज संस्थान भी न्यायिक पुनर्विलोकन की याचिका के लिए अर्जी लगाने लगे क्योंकि उनकी अभिरुचि निःशुल्क सार्वजनिक शिक्षा को सुनिश्चित करने और सार्वजनिक उच्च शिक्षा के निगमीकरण को रोकने में थी, उनके मतानुसार इससे व्यवसायीकरण बढ़ेगा। उनका तर्क था, शिक्षा एक सार्वजनिक वस्तु हैं समस्त शिक्षा खर्च राज्य की जिम्मेदारी है एवं शिक्षा खर्च के भार को समाज पर स्थानांतरित करने का कोई भी प्रयास असंवैधानिक है।

2009 में निजी एवं स्वयं सेवी शिक्षण संस्थानों में विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों, शिक्षकों, व्याख्याताओं, अभिभावकों और बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर 2003 और 2009 के कानूनों के पुनर्विलोकन के लिये 5 अलग अलग याचिकाएँ लगाईं। उनके प्रयास रंग लाये और अदालत ने 2003 के अधिकतर आर्टिकल्स का परिशोधन किया एवं 2009 के कानून को पूर्णतः खुरच दिया।

अधिकांश मामलों में, शिक्षा सुधार के विशिष्ट पक्ष को चुनौतियों चुनौतीकर्ता की विशिष्ट सामाजिक अवस्थिति प्रतिबिंबित करती थीं। शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थानों के प्रशासन को अपनी निजी शैक्षिक संस्थानों की संवृद्धि में अभिरुचि थी। उन्होंने निगमीकरण का विरोध किया क्योंकि उनको अपनी शिक्षण संस्थानों में उनका नियंत्रण हटने का भय था एवं उन्हें वैधिक अनिश्चितताओं का भी सामना करना पड़ सकता था। 2003 के कानून के पुनर्विलोकन की उनकी याचिका के बाद, 2009 का कानून स्वीकृत किया गया और इस प्रकार उनका शिक्षण संस्थानों के निगमिकरण के विरोध पर विराम लगा।

2009 के कानून को अ-बंधनकारी घोषित करने के बाद राज्य ने 2012 में एक नया कानून जारी किया, जिसने उच्च निजी शिक्षण संस्थानों के निगमिकरण को एक वैध आधार प्रदान किया। 2013 में एक निजी विश्वविद्यालय के विधि संकाय के स्नातक छात्रों ने 2012 के कानून के 6 अनुच्छेदों को पुनर्विलोकन करने का अदालत से आग्रह किया। हालांकि इसे अस्वीकार कर दिया गया।

छात्रों, अभिभावकों, बुद्धिजीवियों एवं नागरिक समाज संगठनों को उनके न्यायिक पुनर्विलोकन के आग्रह से क्या मिला? यद्यपि 2003 का कानून संशोधित हुआ और 2009 के कानून को खुरज दिया गया, परन्तु उनके लक्ष्य-निःशुल्क शिक्षा एवं सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों के निगमिकरण पर रोक के उद्देश्य पूर्ण नहीं हुए। सब साथ में लेते हुये, अदालत के निर्णय का तात्पर्य यह है :

1. सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों को शिक्षा शुल्क देना होगा, जिस पर सरकार का नियंत्रण होगा;
2. सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों को कम-से-कम, अपने यहां उपलब्ध 20% सीटों पर आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को प्रवेश देना होगा परन्तु 20% से ज्यादा सीटों पर प्रवेश देने के लिये वे बाध्य नहीं हैं।
3. सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों को अलग-अलग छात्र प्रवेश परीक्षा की अनुमति प्रदान की गयी। जहां अदालत ने इस निर्णय को सकारात्मकता के साथ सहबद्ध किया, वहीं छात्रों ने इस नीति को व्यवसायीकरण के रूप में देखा।
4. पात्र सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों का निगमिकरण अब निर्विरोध जारी है।

छात्र, अभिभावक और सिविल सोसाइटी सक्रिय कार्यकर्ताओं के निःशुल्क सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के समस्त प्रयास टंडे पड़ गये क्योंकि सांविधानिक अदालतों के निर्णयों पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। उनकी पराजय से आन्दोलन कमजोर पड़ गया और वर्तमान में उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण का विरोध करने की कोई पहल नहीं है। तथापि, विभिन्न सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र आज भी अल्प आमदनी वाले परिवारों के लिये अनुचित शिक्षा-शुल्क का विरोध कर रहे हैं, परन्तु विरोध का क्षेत्र अब राज्य से सिकुड़कर सिर्फ उनकी संस्था रह गया है। ■

कामान्टो सुनार्तो से पत्र व्यवहार हेतु पता : [kamantos@yahoo.com](mailto:kamantos@yahoo.com)

&gt; इंडोनेशिया में

# श्रमिक आंदोलन और कामगार वर्ग राजनीति

हरि न्यूगरोहो, इंडोनेशिया विश्वविद्यालय, डिपोक, इंडोनेशिया सदस्य, आई. एस. ए. शोध समिति श्रमिक आन्दोलन (RC 44) सामाजिक आन्दोलन, सामूहिक क्रिया और सामाजिक परिवर्तन (RC 48)



जकार्ता में मई दिवस पर श्रमिक वर्ग की एकजुटता का आह्वान करते हुए श्रमिक प्रदर्शनकारी।

राजनैतिक अखाड़े से लम्बे समय की लुप्तता के बाद, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंडोनेशिया में श्रमिक आन्दोलन फिर एक नयी राजनीतिक सक्रियता ले रहे हैं। 2014 के आम चुनावों में यूनियन के नेताओं को जिला स्तर पर संसद के लिये चुना गया। यह एक ऐतिहासिक सफलता है क्योंकि तकरीबन 50 सालों से इंडोनेशिया के राष्ट्रीय और स्थानीय संसद में कामगार वर्ग का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं था। गत एक दशक से, श्रमिक आन्दोलन का अनेक सामाजिक और राजनीतिक प्रयोग के साथ कार्यस्थली से विस्तार होकर व्यापक अखाड़े की तरफ फैलना भी बहस का विषय

&gt;&gt;

बना हुआ है। अब हम यह प्रश्न कर सकते हैं : क्या अब श्रमिक आन्दोलन इंडोनेशिया में वर्ग राजनीति में परिवर्तन ला सकते हैं?

आर्थिक उदारीकरण और लोकतांत्रिकरण ने 1998 में प्राधिकारवादी शासन के गिरने के बाद, नयी चुनौतियों और औद्योगिक संघर्ष के एक अलग प्रारूप को जन्म दिया। राज्य नियंत्रण का स्थान बाजार नियंत्रण ने ले लिया। गतिशील एवं शक्तिशाली पूंजी, (अति प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक बाजार में) नई प्रतिपक्षी बनी, यूनिशन के विकास के लिये एक नयी चुनौती। नये यूनिशनों का आधार, श्रमिक बाजार की अतिलचीलता के कारण पहले ही कमजोर हो गया है—यहां तक कि उन नये संघों के दुबारा पैर जमाने से पहले, जो सुहारतो के कारपोरेट राज्य के विध्यवस्त होने के बाद आये।

वर्तमान परिस्थितियां यूनिशनों को अविलंब अलचीलाकरण की तरफ ध्यान देने को प्रेरित कर रही है। पारंपरिक कार्यसूची जिसमें वेतन वृद्धि, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कार्यमुक्ति पर रोक जैसे विषय शामिल हैं, को भी इस नये ढाँचे का हिस्सा बनाया। यूनिशनों ने राज्य पर उसकी उदार श्रमिक नीतियों और कम्पनियों पर अनिश्चित कार्य परिस्थितियों को थोपने के कारण आक्रमण किया। (जुलिआवन, 2011)। यूनिशनों ने इस प्रकार एक अधिक प्रभावशाली सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लिये अभियान चलाया, जो नौकरी असुरक्षा और श्रमिकों की बढ़ती हुयी कमजोर स्थिति की क्षतिपूर्ति करेगा। यूनिशन आन्दोलन की मुख्य मांग समाज कल्याण व्यवस्था में परिवर्तन लाने की रही है, इस प्रकार एक अधिक व्यापक निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण होगा जो हजारों संघ सदस्यों के नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा।

श्रमिक आन्दोलन के क्षेत्र के अधिक व्यापक होने से नई चुनौतियाँ प्रस्तुत हुयी, विशेषकर तब जब संघ ने आक्रामक बाजार दबाव को झेलने के लिये व्यापक सामाजिक और राजनीति समर्थन पाने के प्रयास किये। हालांकि ज्यादातर संघ रूढ़िवादी रहे, पर प्रगतिवादी राष्ट्रीय नीतियों से संबद्ध काफी संख्या में स्थानीय यूनिशनों जो हैं ने दो रणनीतियों का अनुसरण किया। प्रथम—नायक बनना विशेषकर, कामकाजी वर्ग समुदाय में परन्तु दूसरे समूह से भी रिश्ते बनाये रखना जैसे—किसान एवं सड़क पर ठेला लगाने वाले। दूसरी रणनीति है—चुनावी राजनीति में भाग लेना। यहां उद्देश्य है, संसद में प्रतिनिधित्व को बनाना और इस प्रकार नीति निर्माण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने के लिये राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के रास्ते खोलना। चुनावी राजनीति में हिस्सा लेने को भी यूनिशन के व्यापक आधार को स्थापित करने का साधन माना गया।

औद्योगिक संघर्ष का प्रारूप और उत्तर—सुहारतो युग में संघवाद के परिवर्तन, ने हो सकता है एक बढ़ते हुये और समेकित कामगार—वर्ग आन्दोलन को उत्तेजित किया हो, परन्तु लाभ को कभी आश्वस्त नहीं किया। (हदीज, 2001)। उदाहरण के लिये—बेकासी औद्योगिक क्षेत्र जो जकार्ता के निकट है, यूनिशन के दो नेताओं ने 2014 में स्थानीय चुनावी सीटों के लिये सफल अभियान किया। यह एक सफल प्रयोग था क्योंकि उन्होंने सैन्य सदस्यों के व्यवस्थित समर्थन से विजय हासिल की। उनकी ऐतिहासिक जीत के बाद, राष्ट्रीय संघ के नेताओं ने 2014 के राष्ट्रपति चुनाव में विवाददस्पद कदम उठाया। यूनिशन के सदस्यों को ऐसे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का समर्थन करने के लिये तैयार किया जिसने सुहारतो के प्राधिकारवाद शासन में कार्य किया और जिसे इस्लामिक राजनीतिक पार्टियों का

भारी समर्थन प्राप्त है, परन्तु कामगार वर्ग में जड़े कमजोर हैं। इससे राष्ट्रीय संघ नेताओं की वर्ग राजनीति में अभिरूचि के बारे में एक अहम प्रश्न उठता है।

इस दौरान, अधिकतर चुनावी राजनीति में यूनिशन के अन्य प्रयोग ठंडे पड़ गये और श्रमिक समुदाय से भी वे महत्वपूर्ण संख्या में वोट प्राप्त करने में असफल रहे। अधिकतर जिन्होंने चुनावी सीटों पर विजय प्राप्त की, ने अपने स्वयं के यूनिशन को राजनीतिक आधार के रूप में प्रयोग नहीं किया, बल्कि दूसरी राजनीतिक पार्टी से लाभ उठाया। बजाय, इसके कि कामगार वर्ग राजनीति का निर्माण हो, इन राजनीतिज्ञों ने अपने आपको धन की राजनीति के व्यवहारिकतावाद के साथ, शक्तिशाली धार्मिक विचाराधाराओं से प्रतिस्पर्धा करते हुये पाया।

इसी प्रकार की समान परिस्थितियां श्रमिक निर्वाचन क्षेत्र को समुदाय आधारित आन्दोलनों के द्वारा व्यापक करने के प्रयास में पायी गईं। हालांकि कुछ संघ व्यापक जाल को स्थापित करने में एवं सामाजिक समर्थन को राजनीतिक समर्थन से विनिमय करने में सफल रहे, परन्तु उन्हें अब एक नीतिगत आम रूचि को स्थापित करने में कठिनाई हो रही थी। जाल के अन्दर हर समूह अपने स्वयं के संकीर्ण क्षितिज के अधीन रहता है; सिर्फ विशेष समूहों में समर्थन का आदान प्रदान होता है, बिना एक आम वर्ग रूचि को बनाये, यहां तक कि श्रमिक वर्ग में भी नहीं। इसी प्रकार, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने में सफलता, श्रमिक वर्ग को व्यापक सामाजिक समूहों से जोड़ा जाना, वर्ग राजनीति की जीत नहीं मानी जा सकती : यह वर्ग पार नागरिक गठबंधन को प्रतिबिंबित करता है न कि श्रमिक वर्ग की रूचि को।

जहां एक ओर चमकदार बिंदु है, वहीं दूसरी ओर वर्तमान इंडोनेशिया के श्रमिक आन्दोलन का विकास उसके सामाजिक आधार के कमजोर होने के कारण बाधित है। यद्यपि युवा पीढ़ी—जो अधिकतम श्रम शक्ति को बनाती है और वर्तमान श्रमिक आन्दोलन की मुख्य ऊर्जा है—कभी भी सत्तावादी शासन में नहीं पली हैं। इसके विपरीत उसने विराजनीतिकरण के एक लम्बे इतिहास का अनुभव किया है। (कारावे *et al.*, 2014) औद्योगिक संघर्ष, सामाजिक आन्दोलन और इन प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित सामूहिक चेतना एक हृष्ट—पुष्ट वर्ग आधारित राजनीतिक आन्दोलन की कूट रचना करने के लिय काफी नहीं है। इसके अलावा, वर्ग—पार हित और साथ ही दूसरी पहचान जैसे धर्म आधारित पहचान श्रमिकों की निष्ठा के शक्तिशाली विरोधी है। ■

हरि न्यूग्रोहो से पत्र व्यवहार हेतु पता :

<[hari.nugroho@ui.ac.id](mailto:hari.nugroho@ui.ac.id)>

#### References

- Caraway, T. L., Ford M., Nugroho H. (2014) "Translating membership into power at the ballot box? Trade union candidates and worker voting patterns in Indonesia's national elections," *Democratization*.  
<http://dx.doi.org/10.1080/13510347.2014.930130>
- Hadiz, V. R. (2001) "New Organising Vehicles in Indonesia: Origins and Prospects," in Jane Hutchison and Andrew Brown (eds.) *Organising Labour in Globalising Asia*. London and New York: Routledge.
- Juliawan, B. H. (2011) "Street-level Politics: Labour Protest in Post-authoritarian Indonesia," *Journal of Contemporary Asia*, 41(3): 349-370.

# > जब धर्म कानूनी पहचान बन जाये

एंटोनियस काह्यादी, इन्डोनेशिया विश्वविद्यालय, डिपोक, इन्डोनेशिया, ISA धर्म के समाजशास्त्र पर शोध समिति (RC 22) और मानव अधिकारों और वैश्विक न्याय पर विषयगत समूह सामाजिक स्तरीकरण के समाजशास्त्र (TG 03) के सदस्य द्वारा



एक इंडोनेशियन पहचान पत्र जिसमें धर्म पहचान शामिल है

सुहार्तो युग (1990) के अंत में, इन्डोनेशिया सार्वजनिक क्षेत्र में धार्मिक भावना और नस्लीय असहिष्णुता उल्लेखनीय रूप से थी। इसलिये उस समय गैर-मुस्लिम या चीनी, जो कि गैर-निवासी इन्डोनेशियाई माने जाते थे, होना मुश्किल था। इन संवेदनशील मुद्दों ने 1998 के दंगों में भूमिका निभायी, जिसने "सुधार" को गति दी और सुहार्तो की नयी व्यवस्था का अंत ला दिया।

इन्डोनेशियाई-चीनी की प्रति नस्लीय भेदभाव-1967 में सरकारी नीतियों की तरह निर्धारित था जब सुहार्तो ने शासन शुरू किया -को इन्डोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति अबदुर्रहमान वाहिद ने 2000 में निषिद्ध कर दिया। कन्फ्यूषिवाद जो कि इन्डोनेशियाई-चीनी को परंपरागत धर्म माना जाता है को देश के आधिकारिक धर्मों में से एक की तरह 2006 में मान्यता दी गयी। पिछले दशक में जब नस्लीय भावना नरम हुयी है, धार्मिक भावना और पूर्वाग्रह बने हुये है। यह मुद्दा इतना संवेदनशील है कि लोग तार्किक और आलोचनात्मक सार्वजनिक बातचीतों में धर्म की बातों से बचते हैं। राजनीति ने धर्म को अछूत बना दिया।

इन्डोनेशियाई इतिहास के दौरान, 1970 के दशक में धर्म को राजनीति में इस्तेमाल किया गया, धार्मिक कानूनी पहचान की सत्तावादिता में चरम तक पहुंचा। उच्च ईस्ट इंडिया युग में (प्रारंभिक 19वीं सदी से लेकर 1942 तक) धर्म प्रमुखतः इस्लाम को राजनैतिक खतरा माना जाता था क्योंकि यह नागरिक अशांति पैदा कर सकता था। उच्च औपनिवेशिक सरकार ने "धार्मिक इस्लाम" को बढ़ने दिया परंतु इस्लाम की राजनीतिक पहचान का दमन किया। इस तरह की नीतियों ने स्थानीय देशज धार्मिक समूहों द्वारा राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया। धर्म की अभिव्यक्ति सिर्फ व्यक्तिगत मामलों तक ही सीमित थी।

जापानी औपनिवेशवाद के तहत (1942-1945), इस्लाम एक युद्ध की रणनीति बन गया। इस्लामिक आंदोलन को सहायता करने और नियंत्रित करने के लिये राज्य प्रशासन की एक विशेष इकाई बनाते हुये, जापानीयों ने इन्डोनेशिया की मुस्लिम बहुसंख्यक लोगों के मध्य उच्च-विरोधी भावना पैदा की; स्वतंत्र इन्डोनेशिया में, यही धार्मिक मामलों का मंत्रालय बन जायेगा।



इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के प्रारंभिक समय में (1945-1959), समूह, जो कि व्यापक इस्लामिक आंदोलन के भाग के रूप में चिन्हित किये गये थे, ने दावा किया कि उन्होंने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता में योगदान दिया था और तर्क दिया कि इंडोनेशिया को इस्लामिक राज्य बन जाना चाहिये। दूसरी ओर, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों लोगों वाले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी समूहों ने जोर दिया कि इंडोनेशिया को सभी धर्मों वाला राज्य बनना चाहिये।

इन दोनों समूहों के मध्य समझौता 1945 इंडोनेशियाई संविधान (अनुच्छेद 29) में निहित था। इंडोनेशिया एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था क्योंकि यह सर्वशक्तिमान ईश्वर के विश्वास पर आधारित था, परंतु यह कोई विशिष्ट धार्मिक पंथ का उल्लेख नहीं करता। इसके अलावा नया राज्य ने धार्मिक स्वतंत्रता का विश्वास दिलाया। परंतु समझौते ने 1946 में धार्मिक मामलों का मंत्रालय स्थापित किया, मुस्लिम समूहों को समायोजित करने के लिये एक कदम।

सुकार्णो के निर्देशित लोकतंत्र (1959-1965) में, वहां एक ओर धार्मिक समूहों मुस्लिम और कैथोलिक और दूसरी ओर कम्यूनिस्टों के बीच तनाव के साथ, धार्मिक और गैर धार्मिक समूहों के बीच ध्रुवीकरण था। सुकार्णो के राष्ट्रवादी गुट, जो समाजवाद की ओर झुका हुआ था, धर्म के मामले में अधिक तटस्थ होने की प्रवृत्ति लिये हुये था। धार्मिक समूहों को नास्तिक कम्यूनिस्टों के हमलों से सुरक्षित महसूस कराने और धार्मिक समूहों का समर्थन पाने के लिये सुकार्णो ने "धर्मों के दुर्व्यवहार और ईशनिन्दा की रोकथाम" के संबंध में ईशनिन्दा विरोधी कानून 1965 में प्रस्तुत किया। बाद में, इस अप्रत्याशित कानून ने इस्लामीकरण की अगले चरण का आधार प्रदान किया जैसे कि इसका इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ किया गया जो धर्म (मुख्यतः इस्लाम) के विरुद्ध काम करते देखे जा रहे थे।

सुहार्तो युग (1966-1998) के दौरान, धर्म जरूरत से अधिक सत्तावादी बन गया। ईशनिन्दा विरोधी कानून ने सार्वजनिक क्षेत्र में धर्म की स्थिति के संरक्षक के रूप में काम किया। इस कानून के तहत, सुहार्तो प्रशासन ने कन्प्यूशिवाद और स्थानीय विश्वासों को छोड़कर अनेक आधिकारिक राज्य धर्मों (इस्लाम, प्रोटेस्टेंट, रोमन कैथोलिक, बौद्ध और हिन्दु) को मान्यता दे दी।

सुहार्तो युग के बाद से ही, इंडोनेशियाई नागरिकों को उनके पहचान पत्र पर आधिकारिक तौर पर अपना धर्म घोषित करना होता था। प्रभावी ढंग से, धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने राज्य की प्रशासकीय शक्ति का उपयोग करने के लिये एक कार्यकारी अंग के रूप में काम किया। इसके साथ, राज्य प्रशासन में धर्म की शक्ति बढ़ाने के लिये 1974 में एक विवाह कानून भी अमल में लाया गया:

देश के आधिकारिक धर्मों में से एक का पालन विवाह या जन्म का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये जरूरी था। इसी बीच, 1989 धार्मिक न्यायालय अधिनियम ने धर्म की शक्ति को सरकार की न्यायिक शाखा के माध्यम से इंडोनेशियाई प्रशासनिक संरचना में गहराई से स्थापित कर दिया। धर्म एक कानूनी पहचान बन गया। धर्म मंत्रालय ने धर्म को सत्तावादी आधार देकर इसकी शक्ति को मजबूत किया; यह विभिन्न नागरिकों के बीच में अंतर कर राज्य प्रशासन में प्रवेश कर गया। इस तरह सुहार्तो ने धर्म को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया।

सुधार के साथ (1998 में सुहार्तो के इस्तीफे के बाद), इंडोनेशिया के सार्वजनिक क्षेत्र जनता का ध्यान पाने और राज्य से मान्यता प्राप्त करने के लिये कई समूहों (धार्मिक, जातीय, स्थानीय और क्षेत्रीय समुदायों) के लिये मुकाबले का स्थल बन गया। सुधार युग में वहां एक नया राजनीतिकरण वाला इस्लामिक आंदोलन जाहिर हुआ, उदाहरण के लिये, धार्मिक संघर्ष जो मोलुक्कास में 1999 में भमके। धार्मिक संघर्षों में ये उछाल अपरिचित (अनौपचारिक) धर्मों और "अन्य इस्लामिक" (अहमदिया और शिया और साथ ही बहुसंख्यक सुन्नी) को सार्वजनिक मंच पर अपनी पहचान प्रस्तुत करने के लिये नयी सहिष्णुता ले आया। कन्प्यूशिवाद और स्थानीय विश्वासों की पहचान के साथ ही, पूर्व में अमान्य धार्मिक समूहों को 2006 से उनके विवाह पंजीकरण की अनुमति दे दी गयी। व्यक्ति अब अपने पहचान पत्र पर "धर्म" खाली छोड़ सकते थे चाहे वो अधिकृत धर्मों में से किसी एक से संबंधित हो।

हालांकि, धर्म अक्सर राजनीतिक मुकाबलों में जीत जाता है, यह संकेत करता है कि धार्मिक भावनायें और संबंध सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधता से अधिक मजबूत होते हैं। इंडोनेशिया के सार्वजनिक क्षेत्र में धार्मिक भावनायें सरल नहीं हैं। परंतु साफ तौर पर, जब धर्म एक कानूनी पहचान बन जाता है, धर्म एक राज्य साधन के रूप में संगठित और शासित की उपेक्षा करने के लिये शासक द्वारा शोषित हो जाता है। इंडोनेशिया की राज्य प्रशासकीय एजेंसीयों और इनकी न्यायिक शाखा के माध्यम से धर्म की सत्ता राज्य द्वारा साथ में चुन लिया गया और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में इसकी शक्ति सुदृढ़ हो गयी। ऐसे संगठित स्वरूप में, धर्म, आध्यात्मिकता को चुनौती देते हुये एक प्रशासनिक मामला बन जाता है। ■

एंटोनियस काह्यादी से पत्र व्यवहार हेतु पता :  
<[antonius.cahyadi@ui.ac.id](mailto:antonius.cahyadi@ui.ac.id)>

# > इंडोनेशिया में उर्ध्वगामी गतिशीलता को प्रोत्साहन

इन्देरा रत्ना इरावती पट्टीनासरानी, इंडोनेशिया विश्वविद्यालय, डिपोक, इंडोनेशिया, ISA शिक्षा के समाजशास्त्र (RC 04) और सामाजिक स्तरीकरण के समाजशास्त्र (RC28) पर शोध समिति के सदस्य द्वारा



जकार्ता की एक व्यस्त सड़क पर सामाजिक स्तरीकरण।

इंडोनेशिया में 1997 की एशियाई वित्तीय संकट के बाद जबरदस्त आर्थिक सुधार का अनुभव हुआ और निम्न आय देश से G-20 के समूह में शामिल होने जा रहा है। इसके साथ, इंडोनेशिया ने राजनैतिक, वित्तीय और आर्थिक स्थिरता प्राप्त कर ली है और दुनिया की बड़ी लोकतंत्रों में से एक बन गया है (विश्व बैंक 2014a)। प्रभावशाली विकास के बावजूद, असमानता भी बढ़ रही है, जैसा कि इंडोनेशिया का गिनी गुणांक 1999 में 0.33 से बढ़कर 2011 में 0.41 हो गया। बढ़ती हुयी असमानता की वजह से

>>

गरीबी कम करने में मंदी, आर्थिक विकास में रुकावट और सामाजिक तनावों और संघर्षों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा, असमानता सार्वजनिक सेवाओं का अनुचित प्रयोग दर्शाती भी है और पैदा भी करती है: जनसंख्या के निचले दशमक के एक बच्चे की शारीरिक रूप से कमजोर होने की संभावना 43 प्रतिशत है वहीं शीर्ष दशमक में तुलनात्मक रूप से सिर्फ 14 प्रतिशत है। इसी तरह, गरीब घरों के बच्चों के विद्यालय छोड़ने की संभावना कहीं अधिक है: शीर्ष दशमक के 26 प्रतिशत की तुलना में निचले दशमक के बच्चों के विद्यालय जल्दी छोड़ने की संभावना 71 प्रतिशत है (विश्व बैंक 2014b)।

कई वर्षों तक इंडोनेशिया की असमानता में उर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के असमान अवसर सबसे अधिक स्पष्ट रहे हैं। कौनसे लोग उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने में सबसे अधिक सफल रहे हैं और कौनसे कारक उर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता लाते हैं? मेरा शोध इंडोनेशियाई पारिवारिक जीवन सर्वेक्षण 1993 2007 के द्वारा संकलित अनुदैर्घ्य आंकड़ों के आधार पर दो प्रांतों पश्चिमी और पूर्वी जावा के शहरी क्षेत्रों में असमानता का आकलन करता है। प्रतिदर्श में 20 से 64 वर्ष के 1,177 पुरुष और महिलाये शामिल हैं।

शहरी इंडोनेशिया में निम्न वर्ग इंडोनेशियाईयों की तुलना में उर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के अवसर उच्च सामाजिक वर्गों के व्यक्तियों के लिये अधिक हैं (पट्टीनासरानी, 2012)। आंकड़े मध्यम से उच्च वर्ग में 45 प्रतिशत की तुलना में निम्न से मध्यम वर्ग में 45 प्रतिशत सामाजिक गतिशीलता दर्शाते हैं। वास्तव में निम्नतर वर्गों में सामाजिक गतिशीलता के अवसर मुश्किल से ही होते हैं। अधिकतर संसार की तरह ही इंडोनेशिया में भी जितना निचला सामाजिक वर्ग होगा, उतना ही सामाजिक गतिशीलता के अवसर कम होंगे। वर्ग कठोरता की तरह ही, प्रस्थिति कठोरता अधिकतर उत्तरदाताओं को उनके माता पिता के वर्ग में ही बनाये रखती है।

लिंग के संदर्भ में, पुरुषों के उपर बढ़ने की संभावनायें समान स्थित महिलाओं की अपेक्षा अधिक है, प्रमुखत जो निम्न सामाजिक वर्ग से शुरू करते हैं। महिलाओं पर घर की लिंग भूमिकाओं के साथ साथ पेशेवर जीवन को निभाने की जिम्मेदारी उनके कैरियर को पेचीदा बना देती है और उनकी उर्ध्वगामी गतिशीलता को सीमित कर देती है। इंडोनेशिया में शिक्षा स्पष्ट रूप से सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। जितनी अधिक शिक्षा का स्तर होता है, उतना अधिक सामाजिक गतिशीलता के अवसर होंगे। पैतृक सामाजिक वर्ग का उत्तरदाताओं के वर्ग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, जबकि उत्तरदाता की शिक्षा का स्तर दूसरा सबसे अधिक मजबूत चर है।

ग्रामीण जावा में मेरा गुणात्मक शोध मेरे मात्रात्मक अध्ययनों के परिणामों कि निम्न वर्ग के व्यक्तियों के लिये मध्यम और उच्च वर्ग में जाना मुश्किल होता है, का समर्थन करता है। हालांकि, कुछ दिलचस्प अपवाद है जिनमें बिना स्कूली शिक्षा के भी निम्न वर्ग के लोग मध्यम वर्ग तक पहुंच गये। यहाँ तीन उदाहरण हैं।

1. कई इंडोनेशियाईयों ने प्रवासी श्रमिकों के रूप में विदेशों में काम करना चुनते हैं, अधिकतर घरेलू श्रमिकों की तरह (आम तौर पर महिलायें) और कारखाना और निर्माण श्रमिकों की तरह (मुख्यतः पुरुष)। प्रवासियों की तरह काम करने के निर्णय की वजह कम पढ़े-लिखे इंडोनेशियाईयों के लिये रोजगार के कम अवसर थे। इसके अलावा, प्रवासी समान काम के लिये इंडोनेशिया से ज्यादा कमा सकते थे और गांवों में रहने वाले रिश्तेदारों के लिये पैसे भी भेज सकते थे। इस धन से उनके परिवार उच्च सामाजिक वर्ग में आ सकते थे।
2. एक और रास्ता विशेष कौशल के अंतर पीढीगत संचरण के माध्यम से है। गरुत (पश्चिमी जावा) का एक समुदाय जावा में सर्वश्रेष्ठ पुरुषों के नाई बनाने के लिये प्रसिद्ध है। दशकों से यह हुनर एक पीढी से दूसरी पीढी में हस्तांतरित होते रहे हैं। सबसे सफल पेशेवर नाई उनके गांव से बाहर बड़े शहरों जैसे जकार्ता में अस्थायी रूप से काम करते हैं। नाईयों के रूप में उनके विशिष्ट कौशल के जरिये, कई लोगों उनके परिवारों के आर्थिक और सामाजिक स्थिति को उपर लाने में सफल रहे हैं।
3. तीसरा, उद्यमिता सामाजिक सीढी में उपर चढ़ने का वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है। अधिकांश गांवों में कुछ उद्यमी हैं जो स्वरोजगार के रूप में शुरू करते हैं परंतु बाद में लघु-स्तर उद्योग पर आ जाते हैं और फिर कुछ तो पड़ोसी गांवों में भी अपना कारोबार का विस्तार कर लेते हैं। वे आमतौर पर छोटी दुकानों, रेस्तरां, या व्यापार का काम करते हैं। स्थान के आधार पर, कुछ उद्यमी बैंक या सरकारी कार्यक्रमों या कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों से उधार लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। सफल उद्यमी उच्च सामाजिक वर्गों में आने में सक्षम हो सकते हैं।

इंडोनेशिया की वर्ग संरचना की कठोरता से उबरने और विवेचना करने के लिये, मुख्यत आय सीढी में सबसे नीचे वाले व्यक्तियों में उर्ध्वगामी गतिशीलता में कमी का, आगे अध्ययन चल रहे हैं। इन अध्ययनों से सामाजिक गतिशीलता के असमान अवसरों को सही करने वाले संभावित सरकारी और निजी क्षेत्रों के कार्यक्रमों पर चर्चा शुरू करने की उम्मीद है। ■

इन्देरा रत्ना इरावती पट्टीनासरानी से पत्र व्यवहार हेतु पता :  
<[indera.pattinasarany@ui.ac.id](mailto:indera.pattinasarany@ui.ac.id)>

#### References

- Pattinasarany, I. R. I. (2012) *Intergenerational Vertical Social Mobility: Studies on Urban Society in the Province of West Java and East Java*. PhD Dissertation, Department of Sociology, Graduate Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia, Depok.
- World Bank (2014a) "Indonesia: Avoiding Trap." *Development Policy Review* 2014. Jakarta: The World Bank Office.
- World Bank (2014b) "Understanding Inequality." Booklet from *Big Ideas Conference*. Jakarta: World Bank Group, September 23, 2014.